

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2006

संख्या 4/4(2)2003-2एफ.आर. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसका द्वारा सामान्य भविष्य निधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

नियमों का लागूकरण
और प्रभाव।

2. (1) यथा उपबन्धित के सिवाए ये नियम सरकारी कर्मचारियों के उन सभी प्रवर्गों, जो हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन हैं और जिनका वेतन हरियाणा राज्य की समेकित निधि में से निकाला जाता है, को लागू होंगे, अर्थात् :-

- (i) राज्य सेवा के ग्रुप 'क' से 'घ' के सभी सदस्यों ;
- (ii) हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा विधानसभा से सम्बन्धित राज्य सेवा के सदस्यों ;
- (iii) कोई अन्य सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी जिसे सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों को लागू कर सकता है।

- (2) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे:-

- (i) अनुबन्ध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों;
- (ii) तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों ;
- (iii) वर्कचार्ज कर्मचारियों;
- (iv) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों;
- (v) प्रशिक्षु रूप में कार्यरत कर्मचारियों;
- (vi) सरकारी कर्मचारियों का कोई अन्य प्रवर्ग जिनको सक्षम प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि ये नियम उन को लागू नहीं होंगे।

- (3) इन नियमों की कोई बात यथा इसमें इसके पूर्व सामान्य भविष्य निधि के अस्तित्व को निरस्वीकार करने या कोई नई निधि गठित करने को प्रभावित नहीं करेगी।

परिभाषाएं

3. (1) इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :-
 - (i) 'महालेखाकार' से अभिप्राय है महालेखाकार कार्यालयाध्यक्ष (लेखा एवं स्थापना), जो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व करता है, जो हरियाणा राज्य के लेखे रखता है और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की ओर से इन लेखों का लेखा-परीक्षा करता है ;
 - (ii) 'प्रशासनिक विभाग' से अभिप्राय है वित्त विभाग से भिन्न हरियाणा सरकार का विभाग ;
 - (iii) 'सन्तान' से अभिप्राय है, वैध सन्तान तथा इसमें दत्तक सन्तान भी शामिल है, जहां गोद लेना, संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन अभिदायकर्ता या प्रतिपाल्य को शासित करने वाली वैयक्तिक विधि द्वारा मान्य है। ऐसे मामले में जिस में किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सन्तान गोद दी है तथा यदि गोद लेने वाले की वैयक्तिक विधि के अधीन, गोद लेना प्राकृतिक सन्तान की हैसियत के रूप में विधिवत् मान्य है, ऐसी सन्तान को, इन नियमों के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक पिता के परिवार से अलग माना जायेगा;
 - (iv) इन नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के सम्बन्ध में 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्राय है, वित्त विभाग या कोई अन्य प्राधिकारी जिसको इन नियमों के द्वारा या के अधीन ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जिसके परामर्श से सरकार का सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग कार्य कर रहा है, ऐसे प्राधिकारियों की सूची अनुबन्ध-झ में दी गई है;
 - (v) 'आश्रित' से अभिप्राय है, निधि के अभिदायकर्ता का कोई भी सम्बन्धी अर्थात्: पत्नी, पति, माता-पिता, सन्तान, अव्यस्क भाई, अविवाहित बहन और मृतक पुत्र की विधवा तथा सन्तान और जहां अभिदायकर्ता के माता पिता जीवित नहीं है तब उसके पितामह-पितामही;

(vi) 'परिवार' से अभिप्राय है :

(क) **पुरुष अभिदायकर्ता** के मामले में अभिदायकर्ता की पत्नी (या पत्नियां जहां वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं) संतान, विधवा (या विधवाएं जहां वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं) और मृतक पुत्र (पुत्रों) की संतान और इसमें माता-पिता, अविवाहित बहनें और अविवाहित अभिदायकर्ता के अव्यस्क भाई भी शामिल हैं :

परन्तु यदि कोई अभिदायकर्ता यह सिद्ध करे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से अलग हो गई है या वह समुदाय जिससे वह सम्बन्ध रखती है, की प्रचलित विधि के अधीन अलग हो गई है, भरण-पोषण की पात्र हो जायेगी, वह मामला, जिससे इन नियमों का सम्बन्ध है, में अभिदायकर्ता के परिवार के सदस्य के रूप में तब तक नहीं समझी जायेगी जब तक अभिदायकर्ता बाद में महालेखाकार को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा सूचित नहीं करता कि उसे इस प्रकार सदस्य के रूप में समझा जायेगा।

(ख) **महिला अभिदायकर्ता** के मामले में, अभिदायकर्ता का पति और संतान, विधुर (या कई विधुर जहां वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं) और अभिदायकर्ता के मृतक पुत्र (पुत्रों) की संतान और इसमें अविवाहित अभिदायकर्ता के माता-पिता, अविवाहित बहनें और अव्यस्क भाई भी शामिल हैं :

परन्तु यदि कोई अभिदायकर्ता महालेखाकार को लिखित में नोटिस द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग करने की इच्छा व्यक्त करे, पति तब तक उन मामलों में जिनसे इन नियमों का सम्बन्ध है अभिदायकर्ता के परिवार का सदस्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि अभिदायकर्ता बाद में कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को लिखित में अभिव्यक्त नोटिस द्वारा इसे रद्द नहीं करवाता;

(vii) "वित्त विभाग" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार का वित्त विभाग;

(viii) "प्रथम नियुक्ति" से अभिप्राय है, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, न कि सरकार के अधीन कोई नियुक्ति धारित करने का नियुक्ति समय, यद्यपि उसने ऐसी नियुक्ति पहले भी धारित की हुई हो ;

(ix) "विदेश सेवा" से अभिप्राय है, ऐसी सेवा जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की स्वीकृति से भारत की समेकित निधि या राज्य की समेकित निधि से भिन्न किसी दूसरे स्रोत से वेतन प्राप्त करता है ;

(x) "निधि" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि ;

(xi) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(xii) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से ऐसे रूप में घोषित कोई प्राधिकारी;

(xiii) "कार्यालयाध्यक्ष" से अभिप्राय है, सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा ऐसे रूप में घोषित कोई प्राधिकारी ;

(xiv) "अवकाश" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को लागू हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार का अवकाश ;

(xv) "अवकाश वेतन" से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी जब अवकाश पर है, को वेतन के बदले दी गई मासिक राशि ;

(xvi) "नामनिर्देशिनी" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, (ऐसे व्यक्ति) जिसे अभिदायकर्ता की मृत्यु के उपरांत उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ;

(xvii) "वेतन" से अभिप्राय है, अभिदायकर्ता द्वारा वेतनमान में हर मास प्राप्त किया जाने वाला मूल वेतन, इसमें मंहगाई वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन भी शामिल हैं ;

(xviii) "सेवा छोड़ने" से अभिप्राय है, सेवानिवृत्ति तथा इसमें शामिल पदच्युति, हटाना, त्यागपत्र, सेवा से छटनी, लापता, मृत्यु तथा केन्द्र/राज्य सरकार (सरकारों) के नियंत्रण के अधीन निकायों में आमेदन ;

(xix) "अभिदायकर्ता" से अभिप्राय है, निधि का सदस्य ;

(xx) "निर्वाह भत्ता" से अभिप्राय है, निलम्बित सरकारी कर्मचारी जिसे वेतन या अवकाश वेतन नहीं मिलता, को भुगतान किया जाने वाला मासिक भत्ता ;

(xxi) "वर्ष" से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष अर्थात् जो किसी वर्ष के प्रथम अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम xix) में दिया गया है, जो परिशिष्ट क में पुनः दर्शाया गया है।

निधि का गठन।

4. (1) भारत में निधि का रख-रखाव रुपयों में किया जायेगा।

(2) इन नियमों के अधीन निधि में भुगतान की गई सभी राशियाँ "हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि" नामक लेख में सरकार के बही खातों में जमा होंगी। राशियाँ जिन की इन नियमों के अधीन देय होने के बाद अदायगी छह मास के भीतर नहीं की जाती है, तो उनको वर्ष के अन्त में "निक्षेप" में अन्तर्लित कर दिया जायेगा और निक्षेप के सम्बन्ध में सामान्य नियमों के अधीन समझी जायेगी।

पात्रता की शर्तें।

5. (1) सभी अस्थाई सरकारी कर्मचारी (जिनमें सभी परीक्षाधीन और सभी पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी शामिल हैं) और सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी निधि में अभिदाय करेंगे। इस नियम के प्रयोजन के लिये परीक्षाधीन कर्मचारियों को अस्थाई सरकारी कर्मचारी माना जायेगा। वे सेवा में आने के तुरन्त बाद सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या लेकर निधि में अभिदाय करेंगे। मास जिस में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या कार्यालय में प्राप्त हो जाती है, उसके अगले मास से अभिदाय शुरू हो जायेगा। अभिदायकर्ता जो संविदा आधार से अन्यथा बिना सेवा व्यावधान के पुनः नियोजित किया जाता है तो वह पुनः नियोजन के तुरन्त बाद अपने विद्यमान निधि खाते में अभिदाय जारी रखेगा।

(2) दूसरी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से हरियाणा सरकार के अधीन किसी पद पर स्थानांतरण या अन्यथा नियुक्त कर्मचारी के मामले में हरियाणा सरकार में पद भार ग्रहण करने पर सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त करने के बाद भविष्य निधि में अभिदाय करेगा। उसके पूर्व रोजगार में उसकी पहले से जमा राशि उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा सम्बद्ध कर्मचारी की लिखित सहमति पर नये सामान्य भविष्य निधि में अन्तर्लित की जायेगी।

(3) हरियाणा/दूसरी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्डों तथा निगमों की सेवा से हरियाणा सरकार के अधीन किसी पद पर स्थानांतरण या अन्यथा नियुक्त कर्मचारी के मामले में हरियाणा सरकार में पद भार ग्रहण करने पर सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त करने के बाद भविष्य निधि में अभिदाय करेगा। उसके पूर्व रोजगार में उसकी पहले से जमा राशि उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा सम्बद्ध कर्मचारी की लिखित सहमति पर नये सामान्य भविष्य निधि में अन्तर्लित कर दी जाएगी।

(4) हरियाणा सरकार के कर्मचारी के मामले में केन्द्र सरकार/किसी दूसरी राज्य सरकार या उन द्वारा नियंत्रित बोर्ड व निगमों के अधीन पदों पर स्थानांतरण/समायोजित होता है तो हरियाणा राज्य के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा उसकी राशि नये नियोक्ता और सम्बद्ध कर्मचारी की सहमति से नये नियोक्ता के पास अन्तर्लित कर दी जायेगी।

(5) हरियाणा सरकार के कर्मचारी के मामले में, जो हरियाणा राज्य द्वारा नियंत्रित बोर्ड और निगम के अधीन पद पर समायोजित हो जाता है, तो हरियाणा राज्य के सामान्य भविष्य निधि खाते में उसकी जमा राशि नये नियोक्ता और सम्बद्ध कर्मचारी की सहमति पर सम्बद्ध बोर्ड और निगम को अन्तर्लित कर दी जायेगी।

सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या का आबंटन।

6. (1) हरियाणा राज्य में सेवा ग्रहण करने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को विहित आवेदन पत्र संख्या पी.एफ. 1 (अनुबंध क) में तीन प्रतियों में सामान्य भविष्य निधि में प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(2) उप-नियम (1) में यथावर्णित आवेदन पत्र के साथ नाम-निर्देशन फार्म पी.एफ.2 (अनुबंध ख) तीन प्रतियों में लगाना होगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष दोहरी प्रति में नाम-निर्देशन फार्म सहित आवेदन पत्र सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या के आबंटन और नामनिर्देशिती व्यक्ति की स्वीकृति के लिए महालेखाकार को अग्रेषित करेगा।

(4) महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आबंटित करेगा और आवेदन प्ररूप की दूसरी प्रति पर सामान्य भविष्य निधि खाता अंकित करके और नाम-निर्देशन प्ररूप को विधिवत् स्वीकृति प्रदान करके कार्यालयाध्यक्ष को वापस भेजेगा।

(5) सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या प्राप्त होने पर, कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारी की सेवा पंजीका के प्रथम पृष्ठ पर इसका इन्द्राज करेगा। सेवा पंजी में नाम-निर्देशन की विषय-वस्तु का आवश्यक इन्द्राज भी अभिलिखित करेगा।

नामनिर्देशन

7. (1) अभिदायकर्ता निधि में सम्मिलित होते समय, उस राशि को जो कि निधि में उसके खाते में जमा की गई राशि के देय हो जाने के पूर्व या देय होने पर, भुगतान की गई हो, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, राशि प्राप्त करने हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को अधिकार प्रदत्त करते हुए एक नाम-निर्देशन कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को भेजेगा।

परन्तु नामनिर्देशन करते समय अभिदायकर्ता का परिवार है तो नामनिर्देशन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि मुसलमान अभिदायकर्ता द्वारा उसकी दत्तक सन्तान के पक्ष में किया गया नाम-निर्देशन स्वीकार्य नहीं होगा, जैसेकि गोद लेना मुस्लिम विधि में मान्य नहीं है।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन अभिदायकर्ता एक से अधिक व्यक्तियों का नाम-निर्देशन करता है तो वह नाम-निर्देशन में प्रत्येक नामनिर्देशिनी को देय हिस्सा ऐसी रीति में करेगा कि किसी भी समय निधि में उसके खाते में जमा सम्पूर्ण राशि अन्तर्विष्ट हो जाये।

(3) प्रत्येक नाम-निर्देशन प्ररूप संख्या पी.एफ.2 (अनुबन्ध ख) में होगा।

(4) उपरोक्त उप-नियम (1) में वर्णित शर्तों के दृष्टिगत कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को लिखित नोटिस भेजकर अभिदायकर्ता किसी भी समय नाम-निर्देशन रद्द/पुनरीक्षित कर सकता है। अभिदायकर्ता, ऐसे नोटिस सहित या अलग से इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से नया नाम निर्देशन भेजेगा। यदि अभिदायकर्ता नया नाम-निर्देशन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उसके निधन के फलस्वरूप सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि देय हो जाती है तो राशि का भुगतान निधि के नियमों के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा मानो कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है।

(5) अभिदायकर्ता नाम-निर्देशन में यह उपबन्धित करेगा :-

(क) किसी नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के सम्बन्ध में कि अभिदायकर्ता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर नामनिर्देशिनी को प्रदत्त अधिकार नाम-निर्देशन में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को मिल जायेगा, बशर्तकि ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, यदि अभिदायकर्ता के परिवार के दूसरे सदस्य हैं, तो ऐसा सदस्य या ऐसे सदस्य होंगे। इस खण्ड के अधीन जहां कोई अभिदायकर्ता एक से अधिक व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान करता है, तो नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय राशि अथवा हिस्सा इस तरह निर्दिष्ट करेगा कि उसके खाते में जमा सम्पूर्ण राशि का भुगतान हो जायेगा।

(ख) कि उसमें निर्दिष्ट किसी आकस्मिकता घटित होने पर नाम-निर्देशन अवैध हो जायेगा :

परन्तु नाम-निर्देशन करते समय अभिदायकर्ता का परिवार नहीं है तो वह नाम-निर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि बाद में उसका परिवार होने की स्थिति में नाम-निर्देशन अवैध हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि नाम-निर्देशन करते समय अभिदायकर्ता के परिवार का केवल एक सदस्य है, वह नाम-निर्देशन में उपबन्ध करेगा कि बाद में उसके परिवार में दूसरे सदस्य या सदस्यों के वृद्धि होने पर वैकल्पिक नामनिर्देशिनी को खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त अधिकार अवैध हो जायेगा।

(6) उप-नियम (5) के खण्ड (क) के अधीन जिसमें कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है या उप-नियम (5) के खण्ड (ख) अथवा उसके उपबन्ध के अनुसरण में कोई घटना होने के कारण नामनिर्देशन अवैध हो जाता है, नाम-निर्देशित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अभिदायकर्ता तुरन्त उसके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार को इस नियम के उपबंधों के अनुसार तैयार करके नये नाम-निर्देशन के साथ नाम-निर्देशन रद्द करते हुये लिखित में नोटिस देगा।

(7) अभिदायकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन तथा रद्दकरण का प्रत्येक नोटिस उस सीमा तक वैध व प्रभावी होंगे जिस तिथि को वह कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है।

(8) जब तक राशि का भुगतान नहीं होता है, सेवा के दौरान किया गया नामनिर्देशन सेवानिवृत्ति के बाद भी पुनरीक्षित किया जा सकता है :

परन्तु अभिदायकर्ता द्वारा पुनरीक्षित नामनिर्देशन सम्बद्ध नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो।

(9) अभिदायकर्ता की हत्या करने के लिए मुकदमा भुगत रहे नामनिर्देशिनी को न्यायालय का निर्णय होने तक भुगतान से वंचित किया जाए। यदि आपराधिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर, सम्बद्ध व्यक्ति अभिदायकर्ता की हत्या करने या हत्या के लिये प्रेरित करने के आरोप से दोषमुक्त हो जाता है तो उसका हिस्सा उसे दे दिया जायेगा। यदि नामनिर्देशिनी अभिदायकर्ता की हत्या करने या हत्या के लिये प्रेरित करने का दोषी ठहराया जाता है तो उसे उसके हिस्से को प्राप्त करने से वंचित किया जायेगा जो दूसरे नामनिर्देशिनी या परिवार के पात्र सदस्यों या अभिदायकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को देय होगा, जैसा इन नियमों में उपबन्धित है।

(10) नाम-निर्देशन के अनुसार निधि राशि का भुगतान करना सरकार के लिए वैध है लेकिन नामनिर्देशिनी (व्यक्तियों) को भुगतान होने से पहले यदि कोई न्यायालय डिक्री कर देता है कि नामनिर्देशिनी (व्यक्तियों) से भिन्न दूसरे व्यक्तियों को भुगतान किया जाये, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(11) यदि अभिदायकर्ता का निधन हो जाता है और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है और वैध नाम-निर्देशन नहीं है, तब दावेदार को न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

अभिदायकर्ता का खाता।

8. प्रत्येक अभिदायकर्ता के नाम से महालेखाकार के कार्यालय में एक खाता खोला जायेगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा -

(i) उसका अभिदाय ;

(ii) अभिदाय पर ब्याज, जैसा कि नियम 12 में उपबन्धित है;

(iii) निधि से लिये गये अग्रिम और निकासियां; तथा

(iv) अग्रिमों की वसूली।

अभिदाय की शर्तें।

9. (1) निलम्बन अवधि को छोड़कर अभिदायकर्ता निधि में मासिक अभिदाय करेगा :

परन्तु अभिदायकर्ता उस अवकाश अवधि जिसमें उसे कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता या अवकाश वेतन, अर्ध वेतन के बराबर या कम है, के दौरान अभिदाय न करने के विकल्प का चयन कर सकता है :

परन्तु यह और कि निलम्बन अवधि के बाद अभिदायकर्ता पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ बहाल होता है तो उसे उसके बकायाजात में से एक ही किस्त में अभिदाय का बकाया जमा करवाना अपेक्षित होगा।

(2) अभिदायकर्ता उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट अवकाश के दौरान अभिदाय न करने के अपने चयन के सम्बन्ध में अपने कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा। उचित तथा समय पर सूचना देने में असफल रहता है तो अभिदाय का चयन किया गया समझा जाएगा।

(3) उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन सूचित किया गया अभिदायकर्ता का विकल्प अन्तिम होगा।

(4) जब कोई अभिदायकर्ता विदेश सेवा में स्थानांतरित हो जाये अथवा प्रतिनियुक्ति पर भारत में या भारत के बाहर भेज दिया जाये, तो वह निधि के नियमों के अधीन वैसे ही बना रहेगा, यदि वह इस तरह स्थानांतरित नहीं किया गया होता या प्रति-नियुक्ति पर नहीं भेजा गया होता।

(5) यदि कोई अभिदायकर्ता राज्य के भीतर एक स्थापना से दूसरी स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है तो वह उसी सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या में अभिदाय करता रहेगा।

(6) अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त होने से छह मास पूर्व निधि में अभिदाय बन्द कर दिया जायेगा।

अभिदाय की शर्तें।

10. (1) अभिदाय की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिदायकर्ता द्वारा स्वयं प्रतिवर्ष नियत की जायेगी:-

(क) यह पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी;

(ख) इस प्रकार अभिव्यक्त की गई कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन यह उसके वेतन, पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश वेतन के आठ प्रतिशत से कम नहीं होगी और उसके वेतन, पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश वेतन से अधिक नहीं होगी।

(2) उप-नियम (1) में यथावर्णित अभिदाय अभिदायकर्ता द्वारा नियत किया जायेगा और कार्यालयाध्यक्ष को निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए सूचित करेगा :-

(क) उस अभिदायकर्ता के मामले में जो पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को शासकीय सेवा में था, उस दिन वेतन, पूर्ण वेतन के बराबर अवकाश वेतन;

(ख) यदि उक्त दिनांक को अभिदायकर्ता पूर्ण वेतन के अलावा दूसरे अवकाश पर था तथा जिसने ऐसे अवकाश के दौरान अभिदाय नहीं करने का चयन किया है या उक्त दिनांक को वह निलम्बित रहा हो, तो उसका वेतन वह वेतन होगा जो वह कर्तव्य पर लौटने के प्रथम दिवस को प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ग) यदि उक्त दिनांक को अभिदायकर्ता भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था तो उसका वेतन वह वेतन होगा, जो कि वह कर्तव्य पर रहते भारत में प्राप्त करने का हकदार होता;

(घ) यदि अभिदायकर्ता पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में नहीं था, वेतन का उस दिन से हकदार हो जाता है जिस दिन वह निधि में शामिल होता है ;

(ङ) यदि अभिदायकर्ता प्रथम बार निधि में सम्मिलित होता है, तो उसका वेतन वह वेतन होगा, जिसका वह निधि में सम्मिलित होने की तिथि को हकदार था;

(च) यदि अभिदायकर्ता पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च को विदेश सेवा में था, तो राशि चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिये अभिदाय के रूप में खजाने में उसके द्वारा जमा की जाएगी।

(3) इस प्रकार नियत अभिदाय की राशि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन में बढ़ोतरी या कटौती के कारण से निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए परिवर्तित नहीं की जाएगी कि अभिदायकर्ता :-

(क) वर्ष के दौरान अभिदाय किसी भी समय एक बार घटाने ;

(ख) वर्ष के दौरान अभिदाय में दो बार बढ़ोतरी करने के लिए स्वतंत्र होगा ;

परन्तु जब अभिदाय की राशि बढ़ाई जाती है तो यह वेतन या पूर्ण वेतन पर अवकाश वेतन से अधिक नहीं होगी और जब यह घटाई जाती है, तो यह उप-नियम (1) में विहित न्यूनतम अभिदाय से कम नहीं होगी;

- (4) यदि अभिदायकर्ता मास के किसी भाग के लिए ड्यूटी पर है और उस मास की शेष अवधि के लिए पूर्ण वेतन से भिन्न अवकाश पर है, तो अभिदाय उस मास के लिये नहीं किया जायेगा।
- (5) यदि अभिदायकर्ता की मास के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी अभिदाय उस मास के लिए नहीं किया जाएगा।
- अभिदाय की वसूली। 11. (1) जब अभिदायकर्ता का वेतन भारत में सरकारी खजाने से निकाला जाता है, तो अभिदाय की वसूली उसके वेतन बिलों से की जाएगी।
- (2) अभिदायकर्ता के मामले में जो केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमित निकाय में विदेश सेवा में है, तो ऐसे निकाय द्वारा अभिदाय की वसूली की जाएगी और मांग ड्राफ्ट या खजाना चालान के माध्यम से महालेखाकार को अग्रेषित की जाएगी।
- ब्याज। 12. (1) उप-नियम (6) के उपबन्धों के अधीन, सरकार अभिदायकर्ता के खाते में जमा पर ब्याज, ऐसी दर पर जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित ढंग के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की जाए, भुगतान करेगी।
- (2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से निम्नलिखित रीति में जमा किया जाएगा :-
- (i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि में से चालू वित्त वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को घटाकर -बारह मास के लिए ब्याज;
- (ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर -चालू वर्ष के प्रारंभ से प्रत्याहरण के मास के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक ब्याज;
- (iii) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के बाद अभिदायकर्ता के खाते में जमा समस्त राशि पर जमा -चालू वर्ष के अंत तक जमा की तिथि से ब्याज;
- (iv) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रूपों में होगी, पचास पैसे अगले उच्च रुपये के रूप में गिने जायेंगे।
- इसके सम्बन्ध में व्याख्या तत्काल संदर्भ के लिये अनुबन्ध 'ज' पर है।
- (3) जब किसी अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाती है तो उस पर ब्याज उप-नियम (2) के अधीन चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ से उस तिथि जिसको अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि के भुगतानयोग्य हो जाती है तक जमा किया जाएगा।
- (4) वेतन में से वसूली के मामले में जमा की तिथि उस मास का प्रथम दिन माना जायेगा जिसमें वसूली की गई है और अभिदायकर्ता/उधार लेने वाले अभिकरण द्वारा अग्रेषित राशि की दशा में प्राप्ति के मास का प्रथम दिन माना जायेगा, यदि यह खजाने में जमा की जाती है या मास के दसवें दिन तक महालेखाकार द्वारा प्राप्त की गई है, किन्तु यदि यह राशि उस मास के दसवें दिन के बाद प्राप्त हुई है तो आगामी मास का प्रथम दिन माना जायेगा।
- परन्तु जब किसी अभिदायकर्ता के नाम जमा राशि भुगतानयोग्य हो गई है, उस पर ब्याज इस नियम के अधीन केवल चालू वर्ष के प्रारंभ की अवधि से या जमा करने की तिथि से तिथि जिसको अभिदायकर्ता की जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो, अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि भुगतानयोग्य हो जाने तक जमा करवाया जाएगा।
- परन्तु यह और कि मामले में जब ऐसे निकाय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अभिदायकर्ता की राशि महालेखाकार को अग्रेषित की जाती है, तो जमा की तिथि मास की पहली तिथि मानी जायेगी, यदि यह राशि उस मास की 10 तारीख तक महालेखाकार को प्राप्त हुई है :
- परन्तु यह और कि किसी मास का वेतन उसी मास के अंतिम कार्य दिवस को आहरित करके वितरित किया जाता है तो अभिदाय की वसूली के मामले में जमा की तिथि आगामी मास का प्रथम दिन होगा :
- परन्तु यह और कि व्यतीत की गई निलम्बित अवधि के बाद पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अभिदायकर्ता से उसकी बहाली पर वसूल की गई अभिदाय की एकमुश्त राशि उस महीने की अभिदाय जिसमें यह खजाने में जमा करवाई गई है मानी जाएगी :
- (5) सेवा छोड़ने के मास के बाद छह मास की अवधि तक अतिशेष निधि पर महालेखाकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए छह मास की अवधि तुरन्त उत्तरवर्ती मास को छोड़ने के बाद अर्थात् जब अभिदायकर्ता की सेवा छोड़ने का मई मास का अंतिम दिन है, तो छह मास की अवधि की गणना जुलाई से दिसम्बर तक की न कि जून से नवम्बर तक की गिनी जानी चाहिए। यदि प्राधिकार पत्र महीने की पन्द्रह तारीख तक जारी किया गया है, तो ब्याज पूर्ववर्ती मास तक अनुज्ञात होगा और यदि प्राधिकार पन्द्रह तारीख के बाद जारी किया गया है तो ब्याज उस मास के लिए भी भुगतानयोग्य होगा तथा यह आगामी मास की पहली तारीख को या उसके बाद भुगतान- योग्य होगा। छह मास से आगे यदि प्राधिकार मास की पन्द्रह तारीख तक जारी किया है तो ब्याज आगामी मास तक अनुज्ञात होगा तथा ब्याज उस मामले के लिए भी भुगतानयोग्य होगा यदि प्राधिकार पन्द्रह तारीख के बाद जारी किया जाता है तथा उसे पूर्ववर्ती मास या प्रथम तिथि के बाद भुगतान किया जाएगा। छह मास से ऊपर की अवधि के लिए ब्याज निम्न रूप से प्राधिकृत होगा :-

- (क) दो वर्ष तक की अवधि के लिये प्रशासकीय विभाग के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद, कि अदायगी में विलम्ब अभिदायकर्ता या उस व्यक्ति जिसको ऐसा भुगतान किया जाना था, के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ है और प्रत्येक ऐसे मामले में प्रशासनिक विलम्ब शामिल है, की पूर्ण जांच-पड़ताल अधिकारी, जो ग्रुप-क के पद से नीचे का न हो, द्वारा की जायेगी और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो वह की जाएगी;
- (ख) किसी अवधि तक वित्त विभाग के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद, कि अदायगी में विलम्ब अभिदायकर्ता या उस व्यक्ति, जिसको ऐसा भुगतान किया जाना था के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ है और प्रत्येक ऐसे मामले में प्रशासनिक विलम्ब शामिल है की पूर्ण जांच-पड़ताल एक अधिकारी जो ग्रुप-क के पद से नीचे का न हो, द्वारा की जायेगी, और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित है तो वह की जायेगी ;
- (ग) तथापि, यदि कोई न्यायालय आदेश देता है कि भुगतान की विलम्बित अवधि के लिए अभिदायकर्ता को ब्याज का भुगतान किया जाए तथा न्यायालय के आदेश अंतिम रूप से हो चुके हैं या सक्षम विधिक प्राधिकारी द्वारा यह मंत्रणा दी गई है कि अभिदायकर्ता को, लिखित में कारण अभिलिखित करने के बाद, ब्याज का भुगतान किया जाए तथा कार्यवाई, यदि कोई अपेक्षित है, अतिरिक्त संचयन तथा ब्याज के भुगतान से बचने के लिए इस उप नियम के (क) और (ख) के अनुसार, की जाए।

(6) ब्याज अभिदायकर्ता के खाते में जमा नहीं किया जाएगा, यदि वह महालेखाकार को अपने कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से यह सूचित करता है कि वह ब्याज प्राप्त करना नहीं चाहता है, किन्तु यदि वह बाद में ब्याज के लिए मांग करता है यह उस वर्ष जिसमें वह उसकी मांग करता है के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा।

(7) अभिदायकर्ता के मामले में जहां यह पाया गया है कि प्रत्याहरण की तिथि को उसके खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकाल ली है, तो अधिक निकाली गई राशि बिना इस बात पर ध्यान दिये कि अधिक आहरण अग्रिम अथवा प्रत्याहरण या निधि से अंतिम भुगतान द्वारा हुआ है, उसके द्वारा उस पर देय ब्याज सहित एक मुश्त वापिस किया जायेगा और ऐसा न करने पर अभिदायकर्ता के वेतन में से एकमुश्त कटौती द्वारा वसूली करने हेतु आदेश दिए जाएंगे। यदि वसूली की जाने वाली कुल राशि अभिदायकर्ता के वेतन के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसके वेतन में से मासिक किस्तों, जोकि वेतन के एक-तिहाई से अत्यधिक न हों, में तब तक की जाएगी, जब तक पूरी राशि ब्याज सहित वसूल न हो जाये। अंतिम भुगतान के मामले में ब्याज सहित अधिक आहरण की राशि की वसूली कर्मचारी के लम्बित देय, उपदान या अवकाश नकद से अन्यथा, वसूल की जायेगी, यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, वसूली न्यायालय के माध्यम से यदि आवश्यक है, की जायेगी। इस उप-नियम के अधीन अधिक निकाली गई राशि पर ब्याज की वसूली की दर अनुज्ञा सम्बद्ध वर्ष (वर्षों) के लिए सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगी। अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया गया ब्याज सरकार के खाते में शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियां राज्य सरकार-800-अन्य "प्राप्तियों" के अधीन एक विशिष्ट उप शीर्ष "निधि" से अधिक निकासी पर ब्याज" में जमा किया जायेगा। इसके अलावा सामान्य भविष्य निधि अभिदाय आदि में अधिक राशि सत्यापित करने वाले दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी तथापि यदि महालेखाकार द्वारा जारी सामान्य भविष्य निधि विवरणी में सरकारी कर्मचारी के खाते में अधिक जमा राशि दर्शायी गई हो तो सम्बन्धित विभाग द्वारा मामला महालेखाकार के ध्यान में लाया जाएगा।

(8) जब अभिदायकर्ता सरकारी सेवा से पदच्युत/निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन वह उसकी पदच्युति/निष्कासन के विरुद्ध अपील कर देता है तो उसके खाते में जमा राशि का तब तक भुगतान नहीं होगा, जब तक उसकी अपील पर निर्णय की पुष्टि करने के अंतिम आदेश जारी नहीं हो जाते। ब्याज, उस मास के पूर्ववर्ती मास तक मिलेगा, जिसमें ऐसे आदेश पारित किये गये हैं लेकिन सेवा त्यागने की तिथि, दिन जिसको अंतिम आदेश पारित किए गए हैं, मानी जाएगी।

(9) निधि में अभिदाय के लिये इन नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक वसूल की गई राशि पर कोई ब्याज अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो परिवार को त्याग कर भगोड़ा/लापता हो गया है, के परिवार को, उत्तरवर्ती मास, जिसमें परिवार पुलिस विभाग से यह रिपोर्ट प्राप्त कर लेता है कि पुलिस के सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारी का अता-पता नहीं है, के छह मास तक ब्याज दिया जा सकता है ;

परन्तु पुलिस विभाग से उक्त रिपोर्ट मिलने की तिथि से एक मास के भीतर परिवार/नामनिर्देशिती सामान्य भविष्य निधि की राशि के अंतिम भुगतान के लिये निर्धारित फार्म पर आवेदन करे। यदि परिवार/नामनिर्देशिती एक मास के भीतर आवेदन नहीं करता है या किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण आवेदन किया जाता है तो अंतिम भुगतान के लिये परिवार/नामनिर्देशिती, आवेदन की विलम्बित अवधि के लिए (मास का अंश भी पूर्ण मास माना जायेगा) ब्याज का पात्र नहीं होगा :

(11) जब कोई अभिदायकर्ता मास के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होता है, तो छह मास की अवधि की गणना ठीक उत्तरवर्ती मास को छोड़ने के बाद की जानी चाहिए, अर्थात् उदाहरण के लिये जब अभिदायकर्ता की सेवा का अंतिम दिन 31 मई है, तो छह मास की अवधि जुलाई से दिसम्बर तक गणना की जाये, न की जून से नवम्बर तक।

(12) ऐसे अभिदायकर्ता के मामले में, जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पूर्व मास के अंतिम दिन दोपहर से पूर्व हो जाती है, तो उसका सेवा त्यागने का दिन अगला दिन समझा जायेगा जैसा कि वित्तीय नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को मृत्यु होने के दिन का वेतन और भत्ता दिया जा सकता है, चाहे मृत्यु उस दिन दोपहर पूर्व हुई हो। इसलिए ऐसे सभी मामलों में छह मास की अवधि उत्तरवर्ती मास, जिसमें अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, के दूसरे मास से गिनी जाएगी।

परन्तु परिवार/नामनिर्देशिती सामान्य भविष्य निधि की राशि के अंतिम भुगतान के लिये सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से एक मास के भीतर विहित प्ररूप में आवेदन करेगा। यदि परिवार/नामनिर्देशिती एक मास के भीतर आवेदन पत्र नहीं भेजता है या किसी भी रूप में अधूरा आवेदन पत्र भेजता है, तब परिवार/नामनिर्देशिती अंतिम भुगतान के लिये आवेदन पत्र विलम्ब से भेजने की अवधि (मास के अंश को भी पूर्ण मास माना जायेगा) के ब्याज का पात्र नहीं होगा।

(13) सेवा त्यागने के मामले में, अभिदायकर्ता को सामान्य भविष्य निधि शेष के ब्याज सहित अंतिम भुगतान इस नियम के उप-नियम (5) के प्रावधानों के अनुरूप भुगतान किया जायेगा लेकिन अभिदायकर्ता को सेवा त्यागने के एक मास के भीतर विहित प्ररूप में अंतिम भुगतान के लिये आवेदन करना होगा। अभिदायकर्ता को अंतिम भुगतान सभी तरह से महालेखाकार को पूर्ण आवेदन पत्र मिलने की तिथि से दो मास के भीतर किया जायेगा और जिसमें अंतिम भुगतान किया जाये, उसके पूर्ववर्ती मास तक ब्याज देय होगा। यदि अभिदायकर्ता सेवा त्यागने की तिथि से दो मास के भीतर आवेदन नहीं करता है या अधूरा आवेदन करता है तब वह अंतिम भुगतान के लिये आवेदन देरी की अवधि (मास के अंश को पूर्ण मास माना जायेगा) के लिये ब्याज का पात्र नहीं होगा।

(14) अधिवर्षिता पर या अधिवर्षिता के इलावा सेवानिवृत्ति के मामले में, अभिदायकर्ता का अंतिम सामान्य भविष्य निधि शेष का अंतिम भुगतान इस नियम के उप-नियम (5) के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा किन्तु अभिदायकर्ता को सेवानिवृत्ति की तिथि से एक मास के भीतर विहित प्ररूप में अंतिम भुगतान के लिए आवेदन करना होगा। अभिदायकर्ता को सभी तरह से महालेखाकार को पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से दो मास के भीतर अंतिम भुगतान किया जायेगा और जिस मास में अंतिम भुगतान किया जाता है उसके पूर्ववर्ती मास तक ब्याज अनुज्ञेय होगा। यदि अभिदायकर्ता सेवानिवृत्ति तिथि से एक मास के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है या किसी भी रूप में अधूरा आवेदन प्रस्तुत करता है तो वह अंतिम भुगतान के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की देरी की अवधि (मास के अंश को पूरा मास माना जाएगा) के लिए ब्याज का पात्र नहीं होगा। ये प्रावधान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले उस अभिदायकर्ता को भी लागू होंगे जो सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन करता है।

अग्रिम प्रदान करने के लिए सामान्य सिद्धान्त

13. (1) निधि अभिदायकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने या, यदि वह सेवानिवृत्ति तक जीवित रहता है, तो उसको तथा उसके परिवार को वृद्धावस्था में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के एकमात्र उद्देश्य से अभिकल्पित की गई है। अभिदायकर्ता के सामान्य संचयों से किसी भी तरह का हस्तक्षेप, इन उद्देश्यों से कम करता है और निधि के सही उद्देश्यों को खत्म करता है। नियम 15 मात्र अग्रिम देने की अनुमति देता है और इस स्कीम में वास्तविक उद्देश्यों से विचलित होने का एक अपवाद है और जब तक इसकी सही रूप से व्याख्या नहीं की जाती है तब तक यह खतरा है कि अभिदायकर्ता इस निधि को सामान्य बैंक खाता मानने लगेंगे जिसका अस्तित्व उन्हें प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले व्यवहार की तरह जीवन की सामान्य घटनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समझदारी से विमुक्त करेगा। यदि इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि मितव्ययिता निरुत्साहित होगी और अभिदायकर्ता को ऐसे समय के लिये घटा हुआ खाता मिलेगा जब उसे या उसके परिवार के लिये अधिक लाभदायक होता। स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी इसलिए निधि को सरस्ते ऋण खाते के रूप में प्रयोग करने के किसी भी प्रयास का और नियम 15 के अप्रत्याशित जरूरी आवश्यकताओं के उस प्रावधान के आपवादिक स्वरूप को क्रियान्वित करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दूरदर्शी विवाहित व्यक्ति, उदाहरण के लिये, डाक्टर के बिल की पूर्ति अपने संसाधनों से करने के लिये तैयार रहे और केवल ऐसी स्थिति में जब खर्च अपवाद स्वरूप लम्बा चले या आवश्यकता गम्भीर और आकस्मिक है, तभी इस प्रयोजन के लिये निधि का प्रयोग करने की सोचे।

(2) उन्हीं कारणों के लिए सगाई, शादी या दाह संस्कार खर्चों के मददे पर अग्रिम के लिये भेजे गये आवेदन के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक छानबीन की जानी चाहिए। जहां धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार रस्मी खर्च अपरिहार्य है, फिर भी इसकी मात्रा परिवार के साधनों से सीमित होनी चाहिए और किसी भी अभिदायकर्ता को निधि में जमा किए गए ऐसे खर्चों को बढ़ाने में समर्थ नहीं होना चाहिए। जहां दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां अपरिहार्य रस्मी खर्चों के लिये निधि से अग्रिम दिया जा सकता है, लेकिन केवल दिखाने के लिये बड़े पैमाने पर ऐसे खर्चों के लिये नहीं दिया जा सकता।

(3) सभी स्वीकृत देने वाले प्राधिकारी, निधि से अग्रिम स्वीकृत कराते समय अभिदायकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखेंगे और किस्तों की संख्या ऐसे रीति में निर्धारित करेंगे कि वास्तविक सेवानिवृत्ति के छह मास पूर्व अग्रिम की सम्पूर्ण राशि की वसूली संभव हो सके। कोई अग्रिम सेवानिवृत्ति के छह मास की शेष अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

14. निधि से आहरण निम्न प्रकार से नीचे दर्शाए गए अग्रिम, आहरण तथा अन्तिम भुगतान के रूप में अनुज्ञेय होगा :

(i) 'अग्रिम' से अभिप्राय है नियम 15 में वर्णित किन्हीं प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए तथा नियम 16 में वर्णित शर्तों के अनुसार वापस योग्य अग्रिम के रूप में अभिदायकर्ता को स्वीकृत की गई राशि तथा मासिक किस्तों में वापस किये जाने वाली इस प्रकार अग्रिम राशि जो स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा नियुक्त की जाये।

निधि से
आहरण।

- (ii) "प्रत्याहरण" से अभिप्राय है नियम 18 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये और नियम 19 से नियम 23 में वर्णित शर्तों के अनुरूप न वापस किये जाने वाली अग्रिम राशि के रूप में अभिदायकर्ता को स्वीकृत की गई राशि। इस प्रकार स्वीकृत की गई राशि जो अभिदायकर्ता द्वारा वापस किये जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।
- (iii) "अंतिम भुगतान" से अभिप्राय है नियम 24 में वर्णित अर्थात् सेवा त्यागने पर, सेवानिवृत्ति पर, सेवा के दौरान मृत्यु या लापता होने पर अभिदायकर्ता के खाते में संचयों के अंतिम निर्धारण के रूप में अभिदायकर्ता को अंतिम रूप में भुगतानयोग्य राशि।

अग्रिम प्रदान करने के लिये प्रयोजन।

15. कार्यालयाध्यक्ष निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के लिये समुचित स्वीकृत प्राधिकारी है जैसा कि अनुबन्ध 3 में दर्शाया गया है:-

(1) अभिदायकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति के आवश्यक यात्रा व्यय सहित, बीमारी, प्रसूति, विकलांगता से सम्बन्धित खर्चों के भुगतान करने ;

(2) अभिदायकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति के निम्न मामलों उच्च शिक्षा के खर्च जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय, सहित की लागत को पूरा करने ;

(क) उच्च विद्यालय स्तर के बाद भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, संव्यावसायिक या व्यावसायिक कोर्स के लिए शिक्षा हेतु ;

(ख) उच्च विद्यालय स्तर के बाद भारत में किसी मैडीकल, इंजीनियरिंग या दूसरे तकनीकी या विशेषज्ञता कोर्स के लिये, बशर्ते-कि अध्ययन का कोर्स दो वर्ष से कम न हो; और

(ग) भारत सरकार में या किसी राज्य सरकार में व्यावसायिक कोर्स, प्रशासनिक या रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा या किसी अनुमोदित संस्था द्वारा संचालित कोचिंग कोर्सों में उपस्थित होने हेतु ।

(3) अभिदायकर्ता की हैसियत के उचित पैमाने पर उसके परिवार के सदस्यों या उस व्यक्ति जोकि उस पर वास्तविक रूप से आश्रित है, के अनिवार्य खर्चों की पूर्ति हेतु जोकि परम्परागत रीति रिवाजों द्वारा अंशदाता ने सगाई, शादियों, दाह संस्कारों या अन्य समारोहों के सम्बन्ध में जीवन में एक बार किया जाता है । शादी में अभिदायकर्ता की स्वयं की शादी भी सम्मिलित है और समय-समय पर किये जाने वाले व्यक्तिगत धार्मिक समारोह जैसे कि जागरण, अखण्ड पाठ, रामायण पाठ, जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ आदि इसमें सम्मिलित नहीं हैं ।

(4) अभिदायकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थापित विधिक कार्यवाहियों की लागत को पूरा करने ;

(5) अभिदायकर्ता के बचाव की लागत पूरा करने जहां वह कार्यालय द्वारा दुराचरण अभिकथित के सम्बन्ध में जांच में अपना बचाव करने के लिये विधिक व्यवसायी को नियुक्त करता है ;

(6) घरेलू वस्तुओं की खरीद के लिये जैसे कि टैलीविजन, वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट प्लेयर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गीजर, सोलर हीटर, ऊर्जा उत्पादन सैट, इनवर्टर और कम्प्यूटर आदि ।

अग्रिम की स्वीकृति के लिए शर्त ।

16. (1) खण्ड (1) से (5) तक में वर्णित प्रयोजनों के लिये अभिदायकर्ता को अधिकतम छह मास के वेतन की राशि या निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, और नियम 15 के खण्ड (6) में वर्णित प्रयोजनों के लिये छह मास का वेतन या निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत या वस्तु की वास्तविक लागत, जो 20000/- रुपये से अधिक नहीं होगी, जो भी कम हो, स्वीकृत किया जायेगा।

(2) नियम-15 में दिये गये प्रयोजनों में से किसी के लिये निधि में से अभिदायकर्ता को एक समय में केवल एक ही अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा।

(3) ऐसे मामले में, जब प्रथम अग्रिम अनुज्ञेय सीमा तक नहीं लिया है, तो उसी स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय राशि और प्रथम अग्रिम के लिये स्वीकृत राशि के अन्तर के बराबर तक की राशि प्रथम अग्रिम के प्रत्याहरण की तिथि से छह मास की अवधि के बाद दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) अगला अग्रिम तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का पुनः भुगतान नहीं करता है।

(5) राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर नियुक्त सभी व्यक्ति प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अपने अपने सम्बन्धित पैतृक विभागों के नियमों द्वारा शासित रहेंगे तथापि इस नियम के अधीन सम्बन्धित पैतृक विभाग अग्रिम स्वीकृत करने के लिए स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी होंगे।

(6) अभिदायकर्ता को उसी प्रयोजन के लिये, जिसके लिये उसने नियम 18 के अधीन प्रत्याहरण लिया है, साथ-साथ स्वीकार्य नहीं होगा।

(7) अभिदायकर्ता को खर्च करने बाद भी, यदि वह दो मास के उचित समय के भीतर अग्रिम स्वीकृति के लिये आवेदन करता है तो निधि से अग्रिम दिया जा सकता है।

(8) सरकारी कर्मचारी जो निलम्बित या असाधारण अवकाश पर है उसे अग्रिम दिया जा सकता है। अग्रिम राशि की स्वीकार्यता की गणना, सरकारी कर्मचारी निलम्बन/असाधारण अवकाश के तुरन्त पहले प्राप्त कर रहा था, वेतन के आधार पर की जाएगी।

(9) अभिदायकर्ता को शिक्षा प्रयोजन के लिये अग्रिम, परिशिष्ट (ख) में यथावर्णित पाठ्यक्रमों के लिये अनुमोदित संस्थानों या राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों जिनमें भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश के संस्थान भी शामिल हैं, स्वीकार्य होगा।

(10) सन्तान/सन्तानों के शादी के लिये पुत्र के मामले में, 21 वर्ष की आयु होने से पूर्व और पुत्री या अन्य आश्रित महिला की दशा में, 18 वर्ष की आयु होने से पूर्व अभिदायकर्ता को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(11) नियम 15 के खण्ड (4) में वर्णित प्रयोजन के लिए उस अभिदायकर्ता को अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा जिसने सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में विधिक कार्यवाही सन्निहित की है।

(12) अभिदायकर्ता, जिसने अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन-पत्र दे दिया है और उसे महालेखाकार को अग्रेषित किया जा चुका है और नियम 15 के खण्ड (1) से (6) में वर्णित प्रयोजनों के लिये निधि से किसी अग्रिम लेने के लिए और आवेदन करता है तो केवल महालेखाकार की पूर्व सहमति के प्राप्त होने पर अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा जो यथाशीघ्र सम्भव अग्रिम की व्यवस्था करेगा।

(13) अभिदायकर्ता एक मास के भीतर अग्रिम का उपयोग करेगा और तदनुसार उपयोग प्रमाण-पत्र भी देगा। उपयोग प्रमाण पत्र न देने या अग्रिम का दुरुपयोग करने के मामले में, नियम 26 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(14) कार्यालयध्यक्ष के मामले में अग्रिम, उसके बाद उच्च प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

अग्रिम (अग्रिमों) की वसूली।

17. (1) अभिदायकर्ता से अग्रिम की वसूली समान मासिक किस्तों की ऐसी संख्या जो स्वीकृतकर्ता निर्दिष्ट करे में की जायेगी, लेकिन किस्तों की ऐसी संख्या 12 से कम और 36 से अधिक नहीं होगी। यद्यपि, अभिदायकर्ता अग्रिम की वसूली के लिये 12 किस्तों से कम किस्तों का चयन कर सकता है। स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी किस्तों की संख्या ऐसी रीति में निर्धारित कर सकता है कि अभिदायकर्ता के सेवानिवृत्त होने की तिथि से छह मास पूर्व अग्रिम की पूर्ण वसूली हो जाये।

(2) वसूली उस मास के आगामी मास से आरम्भ की जाएगी जिस मास में अग्रिम निकाला गया था और उसे अंशदाता के खाते में जमा कराया जायेगा। अंशदाता एक मास में एक से अधिक किस्त चुकाने का चयन कर सकता है।

(3) जब अभिदायकर्ता को निर्वाह भत्ता मिल रहा है तो उसकी लिखित सहमति के बिना वसूली नहीं की जायेगी। फिर भी, उसकी बहाली पर, यदि उसे पूरा वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाता है तो अग्रिम की वसूली एकमुस्त में उसके बकायों में से की जा सकती है।

(4) अभिदायकर्ता से वसूली नहीं की जायेगी, यदि वह अवकाश पर है, जिसमें उसे कोई अवकाश वेतन नहीं मिलता या अवकाश वेतन आधे वेतन के बराबर या कम मिलता है। फिर भी, अभिदायकर्ता की सहमति से वसूली की जा सकती है।

(5) नियम 16 के उप नियम (3) के अधीन यदि एक अभिदायकर्ता को दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया गया है, तो वसूली के प्रयोजन के लिए उसे अलग माना जाना चाहिए।

प्रत्याहरण के लिये प्रयोजन।

18. यथाअन्यथा उपबन्धित के सिवाय विभागाध्यक्ष निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिये समुचित स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी है :-

- (1) अभिदायकर्ता के निवास के लिये गृह निर्माण या उपयुक्त मकान या निर्मित प्लैट अर्जन करने के लिये जिसमें स्थल की लागत या आवास बोर्ड, आवास निर्माण समिति और राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार/केन्द्रशासित सरकार द्वारा अनुमोदित विकास अभिकरण द्वारा आबटित प्लाट या प्लैट के लिए कोई भुगतान भी शामिल है ;
- (2) प्राधिकृत अभिर्ता के माध्यम से खुले बाजार से आवासीय प्रयोजनों के लिये निर्मित मकान/प्लैट के अर्जन के लिये ;
- (3) अभिदायकर्ता के निवास के लिये मकान निर्माण या उपयुक्त मकान या प्लैट के अर्जन के लिये स्पष्ट रूप से ऋण की मदद पर बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिये;

- (4) अभिदायकर्ता द्वारा अपने निवास के लिये मकान बनाने के लिये स्थल की खरीद के लिये या इसी प्रयोजन के लिये स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मदद पर बकाया के पनुर्भगतान के लिये ;
- (5) अभिदायकर्ता द्वारा पहले से ही स्वामित्व या अर्जित वाले मकान या प्लैट का पुनः निर्माण, उसमें परिवर्धन या परिवर्तन के लिए ;
- (6) पैत्रिक मकान या सरकार के सहायता या ऋण से बनाये गये मकान का नवीनीकरण, परिवर्धन, परिवर्तन या रखरखाव के लिये;
- (7) बेरोजगार बच्चों के भूमि व्यवस्थापन के लिये वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्जित करने या निर्माण करने या व्यवसाय स्थापित करने के लिये ;
- (8) अभिदायकर्ता के किसी भी सन्तान की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ;
- (9) अभिदायकर्ता की लड़की (लड़कियों) या अभिदायकर्ता पर वास्तविक रूप से निर्भर किसी अन्य महिला रिश्तेदार की शादी से सम्बंधित खर्चों को करने के लिये ;
- (10) अभिदायकर्ता के सन्तान (सन्तानों) की शादी से सम्बंधित खर्चों के लिये;
- (11) अभिदायकर्ता की स्वयं की शादी से सम्बंधित खर्चों के लिये ;
- (12) मोटर वाहन(वाहनों) अर्थात् मोटर कार और मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिये ;
- (13) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर 90 प्रतिशत प्रत्याहरण।

टिप्पण :- अभिदायकर्ता, जिसने अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन-पत्र दे दिया है और उसको महालेखाकार को अग्रप्रेषित किया जा चुका है और नियम 15 के खण्ड (1) से (13) में वर्णित प्रयोजनों के लिये निधि से किसी प्रत्याहरण को लेने के लिए और आवेदन करता है, तो प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल महालेखाकार की पूर्व सहमति प्राप्त होने पर की जाएगी, जो यथासंभव शीघ्र अग्रिम की व्यवस्था करेगा।

गृह निर्माण के लिये प्रत्याहरण की शर्तें।

19. (1) नियम 18 के खण्ड (1) से (7) में वर्णित प्रयोजनों के लिये निधि से प्रत्येक प्रत्याहरण के सामने निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र विभागाध्यक्ष को अग्रप्रेषित करना होगा। तथापि सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान एक ही प्रयोजन के लिये केवल एक बार प्रत्याहरण अनुमत किया जायेगा। नियम 18 के खण्ड (1) से (4) में यथावर्णित उद्देश्यों को उसी प्रयोजन के रूप में माना जायेगा, जिसके लिये पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण होने के उपरान्त अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत या वास्तविक लागत तक, जिसमें पंजीकरण शुल्क जो भी कम है, भी शामिल है, प्रत्याहरण अनुज्ञात किया जा सकता है।

(2) नियम 18 के खण्ड (1) से (7) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी एक प्रयोजन के लिये निधि से प्रत्याहरण स्वीकृत के लिए प्रस्ताव अग्रप्रेषित करते हुए, यह सुनिश्चित करना होगा कि -

- (i) अभिदायकर्ता ने पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है;
- (ii) पहले से ही स्वामित्व या अर्जित की गई भूमि के भूखण्ड पर गृह निर्माण के लिये अग्रिम हेतु आवेदन किया गया हो, ऐसी भूमि जिस पर गृह निर्माण किया जाना है, उस पर अभिदायकर्ता का व्यक्तिगत रूप से या उसके/उसकी पत्नी/पति के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व का निर्विवाद हक है; यदि भूखण्ड जिस पर गृह निर्माण किया जाना है, पट्टे पर है, तो पट्टे की शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो उसे गृह निर्माण अग्रिम के लिये हकदार बनाएं ;
- (iii) खुले बाजार से निर्मित मकान की खरीद के मामले में, यह सभी तरह के भारों से मुक्त होना चाहिए ;
- (iv) यदि निम्नलिखित के लिये प्रत्याहरण हेतु आवेदन किया गया है :
 - (क) पहले से ही स्वामित्व या अर्जित मकान में परिवर्धन और परिवर्तन करने के लिये; या
 - (ख) मकान की खरीद या पुनः निर्माण या पहले से ही स्वामित्व या अर्जित मकान में परिवर्धन और परिवर्तन करने के लिये पहले स्पष्ट रूप से ऋण की बकाया राशि के पुनः भुगतान के लिये, अभिदायकर्ता का पहले से ही स्वामित्व वाले या अर्जित भूमि और/या मकान पर व्यक्तिगत रूप

से या उसकी/उसके पत्नी/पति जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त रूप से स्वामित्व का निर्विवाद हक होना चाहिए :

- (v) जहां अभिदायकर्ता ने विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड या राज्य द्वारा अनुमोदित मकान निर्माण समिति के माध्यम से स्थल या मकान या प्लैट की खरीद या निर्मित प्लैट के लिये किस्तों में अदायगी करनी है, तो उसे किस्त की अदायगी करने के समय, चाहे किस्तों की संख्या कितनी ही क्यों न हो, प्रत्याहरण की स्वीकृति मिलगी बशर्ते कि अग्रिम की कुल राशि पहली किस्त स्वीकृत करने समय अभिदायकर्ता के निधि में जमा खाता में राशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (vi) यदि किसी शहर/कस्बे या किसी नगरीय सम्पदा की नगरपालिका सीमाओं के भीतर मकान का निर्माण/पुनः निर्माण किया जाना है, तो अभिदायकर्ता से वास्तुकार (वास्तुकारों) द्वारा सम्पत्ति रूप से प्रमाणित अनुमानों सहित स्थल नक्शा की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जानी चाहिए और यदि मकान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किया जाना है, तो राजस्व प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि भूमि/सम्पत्ति पर अभिदायकर्ता का निर्विवाद हक है और यह गांव के 'लाल डोरा' के भीतर आता है। यद्यपि अभिदायकर्ता को अनुमानों सहित वास्तुकार या अनुमोदित भवन ठेकेदार या सिविल इंजीनियर द्वारा सम्पत्ति रूप से प्रमाणित स्थल नक्शा देना होगा ;
- (vii) अभिदायकर्ता, जिसने निधि से धन के प्रत्याहरण की स्वीकृति दी गई है, वह स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रत्याहरण की तिथि से छह मास के भीतर संतुष्ट करेगा कि जिस प्रयोजन जिसके लिए धन का प्रत्याहरण किया था, के लिए धन का उपयोग किया गया है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहरण की गई पूर्ण राशि का तुरन्त पुनः भुगतान एकमुश्त राशि में करना होगा, ऐसा पुनः भुगतान न करने की स्थिति में, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी इसकी वसूली उसके वेतन से या तो एकमुश्त राशि वसूली करने या स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित मासिक किस्तों ऐसी संख्या में वसूल करने के आदेश जारी करेगा :

परन्तु इस उप-नियम के अधीन प्रत्याहरण के पुनः भुगतान करने से पूर्व प्रभावी है, तो अभिदायकर्ता को संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर लिखित रूप में स्पष्ट करने का अवसर दिया जायेगा कि क्यों न पुनः भुगतान को प्रभावी बनाया जाए; और यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है या अभिदायकर्ता द्वारा निर्धारित तीस दिन की उक्त अवधि में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी वसूली को प्रभावी बनाएगा और अभिदायकर्ता को नियम 18 के खण्ड (1) से (7) तक के अधीन किसी भी प्रत्याहरण के लिए नियम 26 के उपबन्धों के अनुसार पांच वर्ष के लिए वंचित भी कर दिया जायेगा।

- (viii) नियम 18 के खण्ड (5) में यथा दिये गये प्रयोजन के लिये, अभिदायकर्ता को, पहले प्रत्याहरण की स्वीकृति के पांच वर्षों के उपरान्त अभिदायकर्ता की निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत या अनुमानित लागत, जो भी कम है, के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जायेगी;
- (ix) नियम 18 के खण्ड (6) में यथा दिये गये प्रयोजन के लिये अभिदायकर्ता को, उसके पैत्रिक मकान, जिसमें उसका विनिर्दिष्ट हिस्सा है, के रख-रखाव के लिये पांच वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त और इस उप नियम के खण्ड (viii) के अधीन पहले प्रत्याहरण के दस वर्ष के बाद अभिदायकर्ता की निधि में जमा राशि का 50 प्रतिशत या अनुमानित लागत, जो भी कम है, के प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी ;
- (x) अभिदायकर्ता को नियम 18 के खण्ड (1) से (4) तक में वर्णित प्रयोजनों के लिये नया प्रत्याहरण करने की भी अनुमति दी जायेगी चाहे उसने उक्त प्रयोजनों के लिये पहले ही सामान्य भविष्य निधि से प्रत्याहरण या सरकार से ऋण लिया हुआ है और वह उक्त निर्मित मकान/प्लैट/प्लाट का निपटान करने का इरादा रखता है/निपटान कर दिया है। नये प्रत्याहरण की ग्राह्यता अभिदायकर्ता के खाते में जमा कुल राशि, जिसमें पहले से ही प्रत्याहरण की गई राशि को शामिल करके इस प्रकार से प्राप्त की गई राशि का 10 प्रतिशत और सामान्य भविष्य निधि खाते में चालू उपलब्ध बकाया में से प्रत्याहरण के रूप में पहले प्रयोजन के लिए पहले राशि घटाकर निर्धारित की जाएगी :

परन्तु प्लाट और उस पर निर्मित किये जाने वाले मकान या खरीदे जाने वाले प्लैट या निर्मित मकान की लागत, प्लाट/प्लैट/निर्मित मकान की बिक्री से प्राप्त जिसमें अब प्रत्याहरण की मांग की गई राशि शामिल है, से अधिक होनी चाहिए। खर्च की लागत में पंजीकरण प्रभार भी शामिल है। इस प्रयोजन के लिए मुख्तारनाम पर की गई खरीद को नहीं विचारा जायेगा ;

नये प्रत्याहरण के लिये ग्राह्यता राशि का परिकलन निम्न अनुसार किया जायेगा :-

उदाहरण : श्री “भ” ने निर्मित मकान/प्लैट/प्लॉट की खरीद के लिये सामान्य भविष्य निधि से 2 लाख रुपये की राशि पहले से प्रत्याहरण कर ली थी। अभिदायकर्ता के खाते में इस समय अतिशेष 6 लाख रुपये हैं। अब उसने 3 लाख रुपये की लागत पर अपने पहले वाले मकान के निपटान के बाद 6 लाख रुपये की लागत पर कोई दूसरा निर्मित मकान/प्लैट/प्लॉट की खरीद के लिए 3 लाख रुपये की नई प्रत्याहरण राशि के लिए आवेदन किया है।

	(राशि रुपयों में)
1. पहले लिया गया प्रत्याहरण	2.00 लाख
2. सामान्य भविष्य निधि में जमा (वर्तमान)	6.00 लाख
3. कुल (1+2)	8.00 लाख
4. खाना 3 की राशि का 10 प्रतिशत	0.80 लाख
5. ग्राह्य प्रत्याहरण(खाना 2 – खाना 4)	5.20 लाख
6. पहले से ही किया गया प्रत्याहरण घटाकर (कालम 1)	2.00 लाख
7. अब ग्राह्य प्रत्याहरण (खाना 5 –खाना 6)	3.20 लाख

उप नियम (2) के खण्ड (i) से (iv) में वर्णित प्रयोजनों के लिये श्री ‘भ’ को 3,20,000/– रुपये तक स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(xi) नियम 18 के खण्ड (7) में यथा दिये गये प्रयोजन के लिये पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद, प्रत्येक बच्चे के लिये अभिदायकर्ता को जमा राशि का 50 प्रतिशत तक प्रत्याहरण करने की अनुमति दी जायेगी। प्रत्याहरण तभी अनुज्ञेय होगा, यदि बेरोजगार सन्तानों जिनमें अविवाहित लड़कियाँ भी शामिल हैं, की आयु 18 वर्ष हो गई है।

(xii) अभिदायकर्ता जिसे नियम 18 के खण्ड (1) से (7) के अधीन निधि में उस की जमा राशि में से प्रत्याहरण करने की अनुमति दी गई है, वह प्रत्याहरण की राशि से निर्मित मकान या अर्जित या खरीदे गये मकान स्थल के स्वामित्व का परित्याग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा, चाहे यह बिक्री के रूप में हो, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी रखने को छोड़कर), उपहार, विनिमय या दूसरे तरीके से हो :

परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिये अनिवार्य नहीं होगी—

(क) तीन वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये मकान या मकान-स्थल; या

(ख) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम जिसमें भारत सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं, जो नये मकान के निर्माण के लिए या वर्तमान मकान में परिवर्धन करने या परिवर्तन करने या प्लॉट खरीदने के लिए अग्रिम ऋण देता है, के पास गिरवी रखा जाये ;

(xiii) निधि से कुल प्रत्याहरण जिसमें सरकार से लिया गया मकान निर्माण अग्रिम भी शामिल है, 18 लाख रुपये या मकान निर्माण अग्रिम के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत सीमा से अधिक नहीं होगा ;

(xiv) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति उनसे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

उच्चतर शिक्षा हेतु
प्रत्याहरण के लिए
शर्तें ।

20. नियम 18 के खण्ड (8) के अधीन प्रारम्भिक प्रवेश के लिये प्रत्येक संतान के लिये अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक या सम्बन्धित संस्था से प्रमाण-पत्र के अनुसार वांछित वास्तविक राशि, जो भी कम है, और आगामी शैक्षणिक वर्षों के लिये प्रत्येक संतान के लिए अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या संस्था द्वारा वांछित वास्तविक राशि, जो भी कम है, के प्रत्याहरण की निम्न शर्तों के अधीन रहते हुये अनुमति दी जायेगी—

(i) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु; और हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में मैडीकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी या विशेष कोर्स हेतु, बशर्ते कि पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम न हो;

- (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्याहरण अनुज्ञेय होगा। अनुमोदित पाठ्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है;
- (iii) ऐसे मामले में जहां आगामी वर्षों में भुगतान समेस्टर आधार पर किया जाना है, वहां अभिदायकर्ता को वर्ष में दो बार उसके खाते में जमा राशि का 25 प्रतिशत तक या सम्बद्ध संस्था द्वारा प्रमाणित अनुमानित खर्च, जो भी कम है, के प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा;
- (iv) अभिदायकर्ता प्रत्याहरण राशि का एक मास के भीतर उपयोग करेगा और तदनुसार उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ;
- (v) निधि से प्रत्याहरण की गई कोई भी राशि जो अभिदायकर्ता द्वारा उस प्रयोजन के लिये वास्तविक वांछित राशि से अधिक पाई जाती है, तो निधि में तुरन्त पुनः संदत की जाएगी;
- (vi) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

विवाह हेतु प्रत्याहरण के लिए शर्तें ।

21. नियम 18 के खण्ड (9), (10) और (11) के अधीन प्रत्याहरण अभिदायकर्ता की प्रत्येक लड़की या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य महिला नातेदार; अभिदायकर्ता के प्रत्येक लड़के के विवाह और स्वयं के विवाह के लिये अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि के 75 प्रतिशत तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुमति होगी :-

- (i) लड़की या आश्रित किसी अन्य महिला की आयु 18 वर्ष से और लड़के के मामले में आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लड़की/आश्रित महिला और पुत्र के विवाह के लिये, अग्रिम के लिये आवेदन करते समय अभिदायकर्ता द्वारा आयु का आवश्यक सबूत देना अपेक्षित होगा। अभिदायकर्ता की आयु स्वयं की शादी के प्रयोजन के लिए, महिला की दशा में 18 वर्ष तथा पुरुष की दशा में 21 वर्ष से कम नहीं होगी;
- (ii) यदि दो या से अधिक विवाह साथ-साथ सम्पन्न किये जाते हैं, तो प्रत्येक विवाह के सम्बन्ध में लिये अनुज्ञेय राशि का निर्धारण इस तरीके से होगा कि मानों एक के बाद दूसरे विवाह के लिये अलग से अग्रिम स्वीकृत किए जाते हैं ;
- (iii) एक ही विवाह के सम्बन्ध में अभिदायकर्ता या तो इस नियम के अधीन या नियम 15 के अधीन धन का प्रत्याहरण कर सकता है,
- (iv) अभिदायकर्ता जो नियम 15 के अधीन अग्रिम राशि प्रत्याहरण करता है, तो वह स्वेच्छा से कार्यालयाध्यक्ष को सम्बोधित लिखित रूप में अनुरोध करके इस नियम में अधिकथित शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की सतुष्टी होने पर बकाया शेष को अंतिम प्रत्याहरण में परिवर्तित करवा सकता है;
- (v) अभिदायकर्ता को प्रत्याहरण की मास जिसमें वास्तव में शादी होनी है, के पूर्ववर्ती तीन मास से पहले अनुमति नहीं दी जा सकती;
- (vi) अभिदायकर्ता विवाह की तिथि से एक मास के भीतर या यदि वह अवकाश पर है तो, अवकाश से वापसी पर एक मास के भीतर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि निकाले गये धन का उपयोग उसी प्रयोजन पर किया गया है, जिसके लिये आशियत था। यदि अभिदायकर्ता अपेक्षित प्रमाण-पत्र देने में असफल रहता है या यदि निकाली गई राशि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न पर किया गया है, जिसके लिए स्वीकृति दी गई थी, तो अभिदायकर्ता द्वारा पूरी राशि एकमुश्त निधि में तुरन्त पुनः भुगतान करनी होगी और यदि वह इस प्रकार करने में असफल रहता है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा आदेश किया जायेगा कि उसके वेतन से या तो एकमुश्त या ऐसी मासिक किस्तों में वसूली की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए ;
- (vii) सगाई रस्म और विवाह रस्म को अलग-अलग माना जाये। नियम 15 के अधीन यदि अभिदायकर्ता ने सगाई रस्म के लिये अग्रिम ले लिया है तो भी विवाह के प्रयोजन के लिये निधि से प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी ;
- (viii) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

मोटर वाहन (वाहनों) की खरीद हेतु प्रत्याहरण के लिए शर्तें ।

22. नियम 18 के खण्ड (12) के अधीन वाहन अर्थात् मोटर कार और मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिए प्रत्याहरण अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत तक या वाहन की लागत, जो भी कम हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा :-

- (i) अभिदायकर्ता का वेतन मोटर कार की खरीद के लिये प्रत्याहरण के मामले में प्रतिमास 9750 रुपये या से अधिक या जो सरकार द्वारा समय-समय से विनिश्चित किया जाए, होना चाहिए। मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिये प्रत्याहरण के लिये न्यूनतम वेतन की कोई शर्त नहीं है ;

- (ii) अभिदायकर्ता की कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए ;
- (iii) अभिदायकर्ता को सेवाकाल के दौरान केवल एक बार मोटर कार और मोटर साइकिल या स्कूटर या मोपेड की खरीद के लिये प्रत्याहरण की स्वीकृति दी जा सकती है ;
- (iv) अभिदायकर्ता को इसी प्रयोजन के लिये सरकार से लिये गए वाहन की लागत और ऋण की लागत के अन्तर तक की राशि का निधि से प्रत्याहरण की स्वीकृति दी जा सकती है ;
- (v) नियम 18 के खण्ड (12) में वर्णित प्रयोजनों के लिये सरकार या बैंक से स्पष्ट रूप से लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के लिये अभिदायकर्ता को निधि से प्रत्याहरण भी अनुज्ञात किया जा सकता है ;
- (vi) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

अधिवर्षिता पर
सेवानिवृत्ति से पूर्व 90
प्रतिशत प्रत्याहरण के
लिये शर्तें ।

23. (1) नियम 18 के खण्ड (13) के अधीन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने की तिथि से पूर्व एक वर्ष के भीतर अभिदायकर्ता की निधि में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक कोई कारण या प्रयोजन बताए बिना प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।
- (2) विभागाध्यक्ष के मामले में प्रत्याहरण की स्वीकृति अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

संचय का अंतिम
भुगतान ।

24. निधि में अभिदायकर्ता का संचय, सेवा छोड़ने पर, उसकी सेवानिवृत्ति पर, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की दशा में, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार अंतिम संदाय होगा :-

(1) सेवा छोड़ने पर —

- (i) जब अभिदायकर्ता सेवा छोड़ता है तो निधि में उसकी जमा राशि उसे देय होगी।
- (ii) अभिदायकर्ता के मामले में, जो कि सेवा से पदच्युत/सेवामुक्त कर दिया गया है और बाद में सेवा में बहाल कर दिया जाता है, तो वह नियम 12 में विहित दर पर उस पर ब्याज सहित उस राशि का पुनर्भुगतान करेगा, जो उसे निधि से अदा की गई थी। इस प्रकार से पुनर्भुगतान की गई राशि निधि में उसके खाते में जमा करवा दी जायेगी।
- (iii) जब अभिदायकर्ता हरियाणा सरकार के अधीन एक विभाग से दूसरे विभाग में नियुक्ति के लिये सेवा छोड़ता है, तो यह सेवा छोड़ने के रूप में नहीं माना जायेगा।
- (iv) अभिदायकर्ता की छटनी को सेवा छोड़ना माना जायेगा।

(2) सेवा निवृत्ति पर —

जब अभिदायकर्ता अधिवर्षिता या अन्य तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि देय हो जाती है। महालेखाकार अभिदायकर्ता के खाते में जमा राशि के उस भाग जिस पर कोई विवाद या शंका नहीं है की अदायगी के लिये कर्मचारी की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के 15 दिन पूर्व और दूसरे मामलों में तीन मास के अन्दर अदायगी प्राधिकृत करेगा और शेष राशि यथाशीघ्र जारी कर दी जायेगी।

(3) मृत्यु या लापता होने पर —

- (i) जब अभिदायकर्ता की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो निधि में उसकी जमा राशि उसके परिवार के सदस्यों/नामित (नामितों) को भुगतानयोग्य होगी।
- (ii) जब अभिदायकर्ता लापता/फरार हो जाता है और उसके ठौर-ठिकाने का पता नहीं है तो पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद कि कर्मचारी का पता नहीं चल रहा है तो निधि में उसकी जमा राशि उसके परिवार के सदस्यों/नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) को भुगतानयोग्य होगी।

(4) जब अभिदायकर्ता अपने पीछे परिवार छोड़ जाता है —

- (i) अभिदायकर्ता द्वारा नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार यदि अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों की जीविका के पक्ष में नामनिर्देशन किया हुआ है तो निधि में उसकी जमा राशि या उसका भाग जिसके लिये नामांकन किया हुआ है वह नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को उसके नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतानयोग्य होगा।

- (ii) यदि अभिदायकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों की जीविका के पक्ष में ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया गया है या यदि ऐसा नामनिर्देशन निधि में उसकी जमा राशि के केवल किसी भाग से सम्बन्धित है तो सारी राशि या उसका भाग जिसके लिए नामांकन संबंधित नहीं है, जैसे भी स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किए गए आशयित किसी नामनिर्देशन के हांतों हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर के हिस्से में भुगतान योग्य होगा :

परन्तु मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और सन्तान या सन्तानों केवल उसी हिस्से को आपस में बराबर बराबर बांटेंगे जो उस पुत्र को मिलना था, यदि वह अभिदायकर्ता का उत्तरजीवी होता !

(5) जब अभिदायकर्ता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है —

जब अभिदायकर्ता पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ता है, यदि उस द्वारा नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की जीविका के पक्ष में कोई नामनिर्देशन किया गया है, तो निधि में उसकी जमा राशि या उसका भाग जिससे नामनिर्देशन सम्बन्धित है, उसके नामनिर्देशिनी या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतानयोग्य होगा। यदि अभिदायकर्ता की मृत्यु हां जाती है और उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है और वैध नामनिर्देशन नहीं है तो न्यायालय से उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले दावेदार को भुगतान किया जायेगा।

(6) मरणोपरान्त पैदा हुए संतान की स्थिति —

अभिदायकर्ता का मरणोपरान्त पैदा हुई सन्तान उसकी मृत्यु के समय उसके परिवार का सदस्य है और यदि जीवित पैदा होता है तो उसे अभिदायकर्ता की मृत्यु से पूर्व पैदा हुए जीवित संतानों के समान समझा जाना चाहिए। यदि मरणोपरान्त पैदा न हुए बच्चे के अस्तित्व की सूचना संवितरण अधिकारी को दी जाती है, तो उसके जीवित पैदा होने की स्थिति में उसे मिलने वाली राशि रख ली जाये और शेष राशि का वितरण सामान्य तरीके से किया जाये। यदि संतान जीवित पैदा होती है, तो रखी गई राशि का भुगतान उसी तरह से किया जाये, जिस तरह से अव्यस्क संतानों के मामले में किया जाता है लेकिन यदि कोई संतान पैदा नहीं होती है, तो रखी गई राशि का वितरण परिवार को सामान्य नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(7) जब अभिदायकर्ता लापता/फरार हो जाता है और उसके ठौर-ठिकाने का पता नहीं है —

जब कोई कर्मचारी परिवार को छोड़कर लापता हो जाता है तो प्रथमतः उसके परिवार को कर्मचारी द्वारा किये गये नामनिर्देशन को ध्यान में रखते हुए सामान्य भविष्य निधि की राशि का निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत भुगतान किया जा सकता है :—

- (i) परिवार सम्बद्ध पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट अवश्य दर्ज करवाये और इस आशय की एक रिपोर्ट भी प्राप्त करे कि पुलिस के सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारी का पता नहीं चल रहा ;
- (ii) नामनिर्देशिनी/कर्मचारी के आश्रितों से क्षतिपूर्ति बंध-पत्र लिया जाये कि कर्मचारी के प्रकट होने पर और किसी भी तरह का दावा करने पर सभी भुगतानों का समायोजन कर्मचारी को देय भुगतानों के विरुद्ध किया जायेगा ;
- (iii) परिवार, जो सरकारी कर्मचारी की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहा है, को न्यायालय के निर्णय तक कोई भी भुगतान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

भुगतान की रीति।

25. निधि से भुगतान नियम 15 के अधीन अग्रिम, नियम 18 के अधीन प्रत्याहरण तथा नियम 24 के अधीन अन्तिम भुगतान लेकर निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है :—

(1) अग्रिम —

नियम 15 में वर्णित प्रयोजनों के लिये नियम 16 में निर्धारित शर्तों के अधीन प्ररूप संख्या पी.एफ.-3 (अनुबन्ध ग) में निधि से अग्रिम प्राप्त किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी अभिदायकर्ता की ग्राह्यता के अनुसार प्ररूप संख्या पी.एफ.-7 (अनुबन्ध छ) में अग्रिम लेने के लिए स्वीकृति जारी करेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार, हरियाणा को पृष्ठांकित की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी अग्रिम की वसूली के लिये किस्तों की संख्या का विशेष उल्लेख करेगा। निधि से राशि उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार खजाने/उप-खजाने से निकाली जायेगी और उसका अभिदायकर्ता को संवितरण किया जायेगा। अग्रिम की स्वीकृति के अनुसार अग्रिम राशि की वसूली का दायित्व कार्यालयाध्यक्ष का होगा। महालेखाकार, हरियाणा उसके कार्यालय में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निधि से निकाली गई राशि की कटौती करेगा।

(2) प्रत्याहरण —

नियम 18 में वर्णित प्रयोजनों के लिये प्ररूप पी.एफ.-4 (अनुबन्ध घ) में नियम 19, 20, 21, 22 और 23 में निर्धारित शर्तों के अधीन निधि से प्रत्याहरण किया जा सकता है। अभिदायकर्ता किसी भी आशयित प्रत्याहरण के लिये दोहरी प्रति में निर्धारित प्ररूप में कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन करेगा। कार्यालयाध्यक्ष आवेदन की जांच-पड़ताल करने के उपरांत इसकी

एक प्रति समर्पित दस्तावेजों के साथ विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करेगा यदि उसे इन नियमों के अनुबन्ध 'झ' में यथावर्णित विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। विभागाध्यक्ष प्रत्याहरण की शर्तों और ग्राह्यता से संतुष्ट होने के उपरांत निधि से प्रत्याहरण के लिए प्ररूप पी.एफ.-8 (अनुबन्ध ज) में स्वीकृति जारी करेगा, जिसकी एक प्रति सम्बद्ध कार्यालयाध्यक्ष और महालेखाकार हरियाणा को भी पृष्ठांकित की जायेगी। निधि से राशि की निकासी कार्यालयाध्यक्ष, उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार खजाने या उप खजाने से की जायेगी और इसका अभिदायकर्ता को संवितरण किया जायेगा। यदि प्रत्याहरण विभागाध्यक्ष के कार्यालय में काम कर रहे किसी अभिदायकर्ता से सम्बन्धित है प्रत्याहरण उस कार्यालय द्वारा किया जायेगा। महालेखाकार, हरियाणा उसके कार्यालय में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निधि से प्रत्याहरण की स्वीकृति का उचित विवरण रखेगा।

(3) अंतिम भुगतान-

- (i) कार्यालयाध्यक्ष अभिदायकर्ता से दोहरी प्रति में आवेदन प्ररूप संख्या पी.एफ.-5 (अनुबन्ध ड) में अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन प्ररूप प्राप्त करने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति से 6 मास पूर्व महालेखाकार हरियाणा को उसे अग्रेषित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष अग्रिम के विरुद्ध जो अभी चालू हैं तथा किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं, को प्रभावित करने वाली वसूली का भी उल्लेख करेगा और प्रत्याहरण, यदि कोई हो, महालेखाकार, हरियाणा द्वारा भेजे गए अभिदायकर्ता को भेजी गई अन्तिम लेखा विवरणी के बाद की अवधि में किया गया है तो उसका भी उल्लेख करेगा। महालेखाकार बही-खातों से सत्यापन के उपरांत अभिदायकर्ता को देय राशि का उसके विकल्प के अनुरूप कार्यालयाध्यक्ष या खजाने को उसकी अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व प्राधिकार पत्र जारी करेगा, जोकि अधिवर्षिता के अगले कार्य दिवस में देय होगा। खजाना अधिकारी, महालेखाकार द्वारा खजाना कार्यालय के लिये जारी प्राधिकार पत्र की प्रति प्राप्त होने के बाद ही भुगतान को अनुज्ञात करेगा।
- (ii) सेवा के दौरान अभिदायकर्ता की मृत्यु हो जाने के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष निधि में संचायन के अंतिम भुगतान के लिये तुरन्त कार्यावाही शुरू करने के लिए महालेखाकार को प्रस्तुत करने के लिये अभिदायकर्ता के परिवार के सदस्यों/नामनिर्देशिनी (नामनिर्देशितियों) से प्ररूप संख्या पी.एफ.-6 (अनुबन्ध च) में आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। अव्यस्क (अव्यस्कों) के मामले में, यदि अवस्यक का प्राकृतिक संरक्षक जीवित नहीं है, भुगतान कानूनी संरक्षक के माध्यम से किया जायेगा। इस उप-नियम के खण्ड (i) में यथावर्णित अन्य पूर्व शर्तों/औपचारिकताएं पूरी की जायेंगी और तद अनुसार प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
- (iii) यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, इन नियमों के अधीन किसी राशि का भुगतान किया जाना है, जो पागल है और भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का अधिनियम IV) के अधीन उसकी सम्पदा के लिये निमित्त प्रबन्धक नियुक्त किया हुआ है, तो भुगतान ऐसे प्रबन्धक को किया जायेगा, न कि पागल को :
परन्तु जहां कोई भी प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और व्यक्ति जिस को राशि देय है, वह न्यायाधीश द्वारा पागल प्रमाणित किया हुआ है, भुगतान भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का अधिनियम IV) की धारा 95 की उप धारा (I) के अनुसार कलक्टर के आदेशों द्वारा उस व्यक्ति को भुगतान होगा, जो ऐसे पागल की देखरेख कर रहा है और महालेखाकार जितनी उचित समझेगा, केवल उतनी ही राशि का पागल की देखरेख करने वाले व्यक्ति, यदि कोई है, को भुगतान करेगा या उसका ऐसा भाग, जो वह उचित समझे, भरण पोषण के लिये उसे भुगतान किया जायेगा।
- (iv) प्रत्याहरण राशि का भुगतान केवल भारत में ही होगा। व्यक्ति जिसको राशि देय है वह भारत में राशि प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेगा।

अग्रिम/प्रत्याहरण का दुस्प्रयोग।

26. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के पास शंका का कारण है कि नियम 15 या 18 के अधीन निधि से अग्रिम या प्रत्याहरण के रूप में आहरित राशि का उपयोग, उससे भिन्न के प्रयोजन के लिए किया गया है तो जिस के लिये राशि के आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, वह अपनी शंका के कारणों से अभिदायकर्ता को संसूचित करेगा तथा उससे अपेक्षा करेगा कि ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तिथि के तीस दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण दे कि क्या अग्रिम या प्रत्याहरण का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिये राशि आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यदि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अभिदायकर्ता द्वारा तीस दिन की उक्त अवधि में प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है, तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अभिदायकर्ता को निर्देश देगा कि वह प्रश्नाधीन राशि तत्काल निधि में पुनः जमा करवाये या चूक होने की स्थिति में अभिदायकर्ता के वेतन में से एकमुश्त कटौती द्वारा वसूल करने के आदेश देगा चाहे वह अवकाश पर हो। यदि, तथापि, पुनः भुगतान की जाने वाली कुल राशि अभिदायकर्ता की वेतन राशि के आधे से अधिक है तो वसूली मासिक किस्तों में, जो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अवधारित करे किन्तु, उसके वेतन के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। अभिदायकर्ता को निधि से कोई अग्रिम लेने के लिए दो वर्षों की अवधि के लिये और प्रत्याहरण के लिये पांच वर्षों की अवधि के लिये विवर्जित भी कर दिया जायेगा।

महालेखाकार के
कार्यालय में
सामान्य भविष्य
निधि लेखों का
रख-रखाव ।

27 (1) इन नियमों के अधीन निधि में प्रदत्त सभी राशियाँ सरकार के खातों में "सामान्य भविष्य निधि" नामक लेख में जमा की जाएंगी। इन नियमों के अधीन जो राशि देय हो जाती है और उसका भुगतान छह मास के भीतर नहीं किया जाता है, तो वर्ष के अन्त में ऐसी राशि को 'जमा' में अंतरित कर दिया जायेगा और उस पर जमा से सम्बन्धित साधारण नियम लागू होंगे।

(2) भारत में अभिदाय की राशि जमा करवाते समय, चाहे यह वेतन से कटौती द्वारा या नकद रूप में हो, अभिदायकर्ता निधि का अपना लेखा संख्या उद्धृत करेगा जो उसे महालेखाकार द्वारा संसूचित किया जायेगा। इसी तरह संख्या में कोई परिवर्तन आता है तो महालेखाकार द्वारा अभिदायकर्ता को संसूचित किया जाएगा।

(3) महालेखाकार, यदि अभिदायकर्ता द्वारा अपेक्षित है, तो एक बार, लेकिन एक बार से अधिक नहीं, अभिदायकर्ता को वर्ष में उस मास के अंत में, जिसके लिये उसका लेखा आलेखित किया गया है, उसके निधि के लेख में जमा कुल राशि की जानकारी देगा।

वार्षिक सामान्य भविष्य
निधि विवरणी जारी
करना।

28 (1) महालेखाकार, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के बाद, यथा संभव शीघ्र प्रत्येक अभिदायकर्ता को वर्ष के प्रथम अप्रैल को आरंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान जमा या नामें डाली गई कुल राशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा राशि का कुल व्याज तथा उस तिथि को अंत अतिशेष को दर्शाते हुए निधि में उसके लेख की विवरणी भेजेगा। महालेखाकार खाते की विवरणी के साथ सम्बद्ध कर्मचारी की जन्म तिथि, यदि उसके कार्यालय में उपलब्ध है, खाते की विवरणी के साथ संलग्न करेगा और प्रश्न करेगा कि क्या अभिदायकर्ता :-

(i) नियम 7 के अधीन किये गये किसी नामनिर्देशन में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहता है ; या

(ii) ऐसे मामलों में जहां उसका परिवार हो गया है और नियम 7 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अभिदायकर्ता ने उसके परिवार के सदस्य के पक्ष में नामनिर्देशन नहीं किया है।

(2) अभिदायकर्ताओं की वार्षिक विवरणी के सहीपन बारे स्वयं की संतुष्टि होनी चाहिए और गलतियों को विवरणी की प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर महालेखाकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

प्रत्यायोजन ।

29. विभागाध्यक्ष इन नियमों के अधीन अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिए उन्हें प्रदत्त शक्तियाँ अपनी जिम्मेदारी पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जिन्हें वे लगाना पसंद करें, उसके मुख्यालय/जिला/कोई अन्य कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत किसी अधिकारी को पुनः प्रत्योजित कर सकते हैं।

नियमों में ढील :

30. जब यह अनुभव किया जाये कि इन नियमों के किन्हीं के प्रचालन से अभिदायकर्ता को अनावश्यक कठिनाई होती है या होने की संभावना है, तो वित्त विभाग, इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभिदायकर्ता के मामलों का निपटान ऐसी रीति में करेगा, जो न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हों।

निर्वचन।

31. इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उठता है, तो उसे वित्त विभाग, हरियाणा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

निरसन तथा
व्यावृत्ति ।

32. पंजाब सामान्य भविष्य निधि नियम, 1936 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं। इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुबन्ध क

प्ररूप संख्या पी.एफ.-1

(देखिए नियम 6)

सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आबंटन के लिये आवेदन पत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें)

आवेदक का नाम और पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/ नियमित सेवा में आने की तिथि	पद नाम और कार्यालय पता	धारित पद का नाम (i) परिवीक्षा पर (ii) अस्थाई (iii) स्थाई	वर्तमान वेतनमान और मासिक मूल वेतन	अभिदाय की मासिक दर	क्या आवेदक का परिवार है या नहीं	महालेखाकार द्वारा आबंटित खाता संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान—

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक—20

(हस्ताक्षर)
कार्यालयाध्यक्ष

कार्यालय महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़

संख्या—दिनांक—

खाना 8 में यथावर्णित आबंटित सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या के साथ—को लौटाया जाता है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किये जाने वाले सभी पत्राचारों में यह संख्या अंकित की जाये। सम्पत्क रूप से स्वीकृत किया गया नामनिर्देशन प्ररूप भी कार्यालय रिकार्ड के लिये वापिस लौटाया जाता है।

(हस्ताक्षर)
महालेखाकार, हरियाणा

अनुबन्ध ख
प्ररूप संख्या पी.एफ.-2
(देखिए नियम 7)
नाम-निर्देशन का प्ररूप

खाता संख्या-----

में ----- इसके द्वारा निम्न वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को जो कि मेरे परिवार का सदस्य है (सदस्य हैं)/गैर सदस्य है (सदस्य हैं), जैसा कि हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 7 में परिभाषित है, को राशि देय होने से पूर्व या देय होने, लेकिन भुगतान न होने से पूर्व मेरा निधन होने पर निधि में मेरी जमा राशि निम्न अनुसार प्राप्त करने के लिये नामनिर्देशित करता हूँ :

नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पता	अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध	नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) की आयु	प्रत्येक नामनिर्देशित को देय हिस्सा	घटनाएं जिनके घटित होने पर नामनिर्देशन अवैध हो जायेगा	उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, पता और सम्बन्ध, यदि कोई है, जिसे अभिदायकर्ता के पूर्व निधन होने पर नामनिर्देशित व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होगा	यदि नामनिर्देशित व्यक्ति नियम 3 में यथाउपबंधित परिवार का सदस्य नहीं है तो कारण बताएं
1	2	3	4	5	6	7

स्थान-----

दिनांक----- 20

अभिदायकर्ता के हस्ताक्षर

बड़े अक्षरों में नाम-----

पदनाम-----

दो गवाहों के हस्ताक्षर

नाम और पता

हस्ताक्षर

1.

2.

टिप्पण : (1) प्ररूप तीन प्रतियों में भरा जायेगा। दो प्रतियां महालेखाकार, हरियाणा को अग्रेषित की जायेंगी, जो एक प्रति सम्पक् रूप से स्वीकृत और हस्ताक्षर करके कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय रिकार्ड के लिये लौटाएगा।

(2) खाना 4 में, यदि केवल एक व्यक्ति नामनिर्देशित किया गया है तो नामनिर्देशित के सामने “सम्पूर्ण” शब्द अंकित किया जाना चाहिए। यदि एक से ज्यादा व्यक्ति नामनिर्देशित किये गये हैं तो निधि की सम्पूर्ण राशि के वितरण के लिये प्रत्येक नामनिर्देशित व्यक्ति का भुगतान योग्य हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाये।

कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिये

श्री/सुश्री----- पदनाम----- से दिनांक-----को प्राप्त नामनिर्देशन अग्रिम कार्रवाई के लिये महालेखाकार, हरियाणा को अग्रेषित करने हेतु प्राप्त।

दिनांक-----

(हस्ताक्षर)

कार्यालयाध्यक्ष

महालेखाकार, हरियाणा के प्रयोग के लिये

श्री/ सुश्री-----पदनाम-----कार्यालय----- द्वारा किया गया नाम निर्देशन स्वीकृत किया जाता है और कार्यालय प्रयोग के लिये----- (कार्यालयाध्यक्ष) को कार्यालय रिकार्ड के लिये वापिस भेजा जाता है।

(हस्ताक्षर)

महालेखाकार, हरियाणा

अनुबन्ध ग

प्ररूप संख्या पी.एफ.-3

(देखिए नियम 15 से 17)

सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के लिये आवेदन पत्र

विभाग/कार्यालय _____

1. अभिदायकर्ता का नाम :
2. पदनाम :
3. खाता संख्या (पूर्ण) :
4. विद्यमान वेतनमान :
5. विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन, जिसमें
महंगाई वेतन, वैयक्तिक वेतन,
विशेष वेतन, यदि कोई है, शामिल है :
6. सेवा ग्रहण करने की तिथि :
7. सेवानिवृत्ति की तिथि :
8. अभिदायकर्ता के खाते में आवेदन की तिथि को

निम्न अनुसार अतिशेष :

- | | | |
|-------|---|-------|
| (i) | वर्ष _____ की नवीनतम सामान्य भविष्य निधि विवरणी के
अनुसार अन्तिम अतिशेष (प्रति संलग्न) : | रुपये |
| (ii) | नियमित मासिक अभिदाय को जोड़ें और इसमें उपरोक्त (i) पर
वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी के बाद यदि कोई
एकमुश्त अभिदाय जमा हुआ है तो उसे भी इसमें जमा करें : | रुपये |
| (iii) | उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि
के बाद अग्रिम (अग्रिमों) के धन की वापसी को जोड़ें : | रुपये |
| (iv) | कुल (i) + (ii) और + (iii) : | रुपये |
| (v) | उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के बाद
लिये गये अग्रिम (अग्रिमों) और प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) को घटाएं : | रुपये |
| (vi) | जमा में शुद्ध अतिशेष : | रुपये |
9. अपेक्षित अग्रिम की राशि _____ रुपये
 10. प्रयोजन जिसके लिये अग्रिम अपेक्षित है :
 11. रस्म की तिथि :
 12. नियम जिसके अन्तर्गत अग्रिम स्वीकार्य है :
 13. सेवा के दौरान लिये गये अग्रिमों का पूर्ण विवरण :

क्रम संख्या	अग्रिम का प्रयोजन	आहरण की तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से अदायगी प्राप्त की
1.				
2.				
3.				

14. क्या पूर्व में लिये गये अग्रिम की पूरी वसूली हो चुकी है।

15. यदि उपरोक्त मद 13 का उत्तर नकारात्मक है तो निम्न सूचना दें :-

क्रम संख्या	अग्रिम का प्रयोजन	अग्रिम की राशि	आहरण का मास	वसूली की किस्तों की संख्या	वसूला गया अग्रिम	बकाया अग्रिम
1.						
2.						

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे सामान्य भविष्य निधि से पहले जो अग्रिम लिया था (लिये थे) का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये अग्रिम स्वीकृत किया था (किये थे) उस पर उपयोग किया है और मैंने पहले ही कार्यालयाध्यक्ष को उपयोग प्रमाण पत्र भेज दिया है जैसा कि नियम 16 में अपेक्षित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की रस्म/शिक्षा आदि के लिये अग्रिम लेने हेतु आवेदन किया गया है वह पूर्ण रूप से और केवल मेरे उपर आश्रित है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है या कोई भी मिथ्या कथन नहीं है। मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि तथ्यों के छिपाने या गलत तथ्य देने से मुझे मेरे सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम (अग्रिमों) लेने के लिये दो वर्षों की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम _____

पदनाम _____

शाखा _____

दिनांक _____

अनुबन्ध घ

प्ररूप संख्या पी.एफ.-4

(देखिए नियम 18 से 23)

सामान्य भविष्य निधि से प्रत्याहरण के लिये आवेदन-पत्र

भाग-।

विभाग-----

कार्यालयाध्यक्ष-----

1. अभिदायकर्ता का नाम :
2. पदनाम :
3. लेखा संख्या (पूर्ण):
4. विद्यमान वेतनमान :
5. विद्यमान वेतनमान से मूल वेतन, जिसमें महंगाई वेतन, वैयक्तिक वेतन, रुपये
विशेष वेतन, यदि कोई है, शामिल है :
6. सेवा ग्रहण करने की तिथि :
7. सेवानिवृत्ति की तिथि :
8. अभिदायकर्ता के खाते में आवेदन की तिथि को निम्न अनुसार अतिशेष :
 - (i) वर्ष -----की नवीनतम सामान्य भविष्य निधि विवरणी रुपये
के अनुसार अंतिम अतिशेष (प्रति संलग्न) :
 - (ii) नियमित मासिक अभिदाय को जोड़ें और इसमें उपरोक्त (i) पर रुपये
वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी के बाद यदि कोई एकमुश्त
अभिदाय जमा हुआ है तो उसे भी इसमें जमा करें :
 - (iii) उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि रुपये
के बाद अग्रिम (अग्रिमों)के धन की वापसी को जोड़ें :
 - (iv) कुल (i) + (ii) और + (iii) : रुपये
 - (v) उपरोक्त (i) पर वर्णित सामान्य भविष्य निधि विवरणी की तिथि के रुपये
बाद लिये गये अग्रिम (अग्रिमों) और प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) को घटाएं :
 - (vi) खाते में शुद्ध अतिशेष : रुपये
9. प्रत्याहरण की अपेक्षित राशि: रुपये-----
10. प्रयोजन जिसके लिये प्रत्याहरण अपेक्षित है :
11. नियम जिसके अन्तर्गत प्रत्याहरण स्वीकार्य है :
12. क्या इसी प्रयोजन के लिये पहले कोई प्रत्याहरण
लिया गया है, यदि लिया गया है तो राशि और तिथि का उल्लेख करें :

क्रम संख्या	आहरण की तिथि	स्वीकृति संख्या और तिथि	राशि	कार्यालय का नाम जहां से भुगतान प्राप्त किया हो
1.				
2.				
3.				

टिप्पण : प्लेट की खरीद, मकान की खरीद, मकान निर्माण, परिवर्तन तथा परिवर्धन, मकान की मरम्मत और इन प्रयोजनों के लिये ऋण के पुनर्भुगतान हेतु लिए गये सभी प्रत्याहरणों को उसी प्रयोजन के रूप में समझा जाना चाहिए । मोटर साइकिल, स्कूटर और मोपेड की खरीद हेतु लिये गए सभी प्रत्याहरणों को इसी प्रयोजन के रूप में समझा जाना चाहिए और नियम 22 में वर्णित शर्तों के अधीन मोटरकार के लिये अलग से प्रत्याहरण लिया जा सकता है।

13. अतिरिक्त जानकारी सम्बद्ध भागों में (भाग-संलग्न)
 दी जाये अर्थात् प्लेट/पलैट का अर्जन भाग - II में/
 विवाह की रस्म का विवरण भाग-III में/
 उच्च शिक्षा का विवरण भाग -IV में/
 मोटर वाहन/वाहनों का विवरण भाग-V में :

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे सामान्य भविष्य निधि से पहले जो प्रत्याहरण लिया था (लिये थे) का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये प्रत्याहरण स्वीकृत किया गया था (किये गये थे) उसी पर उपयोग किया है और मैंने पहले ही कार्यालयाध्यक्ष को उपयोग प्रमाण-पत्र भेज दिया है जैसा कि नियम 19/20/21/22 में अपेक्षित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की रस्म/शिक्षा आदि के लिये अग्रिम लेने हेतु आवेदन किया गया है वह पूर्ण रूप से और केवल मेरे ऊपर आश्रित है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है या कोई भी मिथ्या कथन नहीं है। मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि तथ्यों को छिपाने, गलत तथ्य देने से मुझे मेरे सामान्य भविष्य निधि से प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) लेने के लिये पांच वर्षों की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पदनाम _____

कार्यालय _____

दिनांक _____

(कार्यालय द्वारा परीक्षण/सत्यापन)

1. प्रमाणित किया जाता है कि अभिदायकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये इस विवरण की कार्यालय ने जांच पड़ताल और सत्यापन कर लिया है। अभिदायकर्ता द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्यापित और ठीक हैं।
2. अभिदायकर्ता नियम 18 के अधीन आवेदित प्रत्याहरण को लेने का हकदार है; या अभिदायकर्ता आवेदित प्रत्याहरण के लिये हकदार नहीं हैं और निम्न कारणों से नियमों में छूट देने का निवेदन किया है।

(i)

(ii)

(iii)

(मोहर सहित कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध घ
प्ररूप संख्या पी.एफ.-4

भाग-II

यदि आवेदन पत्र प्लॉट अर्जित करके उस पर मकान बनाने/पलैट या मकान अर्जित करने/मकान निर्माण हेतु प्रत्याहरण के लिये है तो निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रदान की जाये :

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1.	प्रयोजन	(i) मकान के लिये प्लॉट का अर्जन (ii) निर्मित पलैट का अर्जन (iii) निर्मित मकान का अर्जन (iv) मकान का निर्माण (v) आवास इकाई अर्जित करने के लिये अभिव्यक्त रूप से वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण के पुनः भुगतान (vi) मकान की मुरम्मत/सौन्दर्यकरण
2.	अर्जन का स्रोत (कृपया अभिकरण का विवरण दें, अर्थात् हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/सहकारी आवासीय समिति/खुला बाजार या कोई अन्य स्रोत)	
3.	व्यक्ति जिसके नाम प्लॉट/मकान/पलैट (स्पष्ट हक है) स्वामित्व का प्रमाण/आबंटन पत्र की प्रति संलग्न करें।	
4.	सरकार की स्कीम के अधीन लिये गये गृह निर्माण अग्रिम की राशि, यदि कोई हो	
5.	क्या सामान्य भविष्य निधि से इस प्रयोजन के लिये पहले प्रत्याहरण किया गया है।	हां/नहीं
6.	यदि उपरोक्त का उत्तर 'हां' में है, कृपया विवरण दें : (i) उसी इकाई के लिये लिया गया प्रत्याहरण (ii) किसी अन्य इकाई (इकाइयों) के लिये लिया गया प्रत्याहरण (iii) क्या पूर्व इकाई का निपटान कर दिया है और उसी (इकाई) से लिया गया वापिस खाते में जमा करवा दिया है	(i) (ii) (iii)
7.	यदि पति या पत्नी के नाम प्लॉट हेतु प्रत्याहरण के लिये आवेदन किया जा रहा है, तो कृपया यह उल्लेख करें कि सामान्य भविष्य निधि संचय को प्राप्त करने वाला पहला नामनिर्देशित कौन है।	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पदनाम _____

कार्यालय _____

अनुबन्ध घ
प्ररूप संख्या पी.एफ.-4
भाग-III
(विवाह रस्म के लिये प्रत्याहरण)

क्रम संख्या	विषय	ब्यौरे
1.	स्वयं/बेटा/बेटी/आश्रित बहन की शादी	
2.	आश्रित का नाम, जिसकी शादी के लिये अग्रिम के लिये आवेदन किया जाता है	
3.	आश्रित की जन्म तिथि	
4.	क्या शादी के लिये पहले कोई प्रत्याहरण लिया गया है ? यदि हां, तो ली गई राशि का विस्तृत विवरण	
5.	प्रत्याहरण राशि जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है	
6.	विवाह की तिथि	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पदनाम _____

कार्यालय _____

अनुबन्ध घ
प्ररूप संख्या पी.एफ.-4
भाग-IV
(संतान की उच्च शिक्षा के लिये प्रत्याहरण)

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1.	संतानों की उच्च शिक्षा के लिये प्रत्याहरण के लिये आवेदन किया जा रहा है :-	पुत्र/पुत्री
2.	संतान का नाम	
3.	अध्ययन के पाठ्यक्रम के ब्यौरे	
4.	अध्ययन संस्थान का नाम	
5.	प्रवेश का प्रमाण	
6.	अग्रिम को न्यायोचित करने के समर्थन में फीस का प्रमाण	
7.	इस प्रयोजन के लिये पूर्व में लिए गए प्रत्याहरणों के ब्यौरे	(i) (ii) (iii)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पदनाम _____

कार्यालय _____

अनुबन्ध घ
प्ररूप संख्या पी.एफ.-4
भाग-V
(मोटरवाहन (वाहनों) की खरीद के लिये प्रत्याहरण)

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1.	प्रत्याहरण का आवेदन मोटरवाहन अर्थात् मोटर कार, मोटर साईकिल, स्कूटर या मोपेड के लिये किया जा रहा है ।	
2.	पूर्व में लिए गए प्रत्याहरण या ऋण, यदि कोई हो, के विवरण ।	राशि प्रत्याहरण या ऋण निकासी की तिथि
3.	वाहन की लागत (प्रपत्र बीजक संलग्न करें) ।	
4.	वाहन की खरीद के लिये अपेक्षित राशि ।	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पदनाम _____

कार्यालय _____

अनुबन्ध ड
प्ररूप संख्या पी.एफ.-5
(देखिए नियम 24)

निगमित निकायों/अन्य सरकारों में अंतिम भुगतान/स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र

सेवा में

महालेखाकार,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
(कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

श्रीमान,

मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ/हो गया हूँ/सेवा मुक्त/पदच्युत कर दिया गया हूँ/स्थायी रूप से -----में स्थानांतरित कर दिया गया हूँ/सरकारी सेवा से अंतिम रूप से त्याग-पत्र दे दिया है/-----में नियुक्ति के लिये ----- सरकार की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है और मेरा त्याग-पत्र ----- पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकार लिया गया है। मैंने ----- में ----- को पूर्वाह्न/अपराह्न में सेवा में प्रवेश कर लिया है ।

2. मेरा निधि खाता संख्या ----- है ।

3. मैं मेरे कार्यालय----- या ----- खजाना/उपखजाना के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहता हूँ। पहचान के लिए मेरे व्यक्तिगत चिन्ह, बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली की छाप (निराक्षर अभिदायकर्ता के मामले में) और नमूना हस्ताक्षर (साक्षर अभिदायकर्ता के मामले में) के ब्यौरे दोहरी प्रतियों में सरकार के राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित, संलग्न हैं।

4. मेरा अनुरोध है कि मेरे खाते में जमा सम्पूर्ण राशि और उस पर नियमों के अधीन देय ब्याज सहित मुझे अदा की जायें/-----को अंतरित की जाये।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

नाम

पता

तिथि:

(विनिर्दिष्ट किया जाए)

(कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

आवश्यक कार्यवाही के लिये महालेखाकार, हरियाणा को अग्रेषित।

2. श्री/सुश्री----- सेवानिवृत्त हो गया है/सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया है/-----में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है/सरकारी सेवा से अंतिम रूप से त्याग-पत्र दे दिया है/-----में नियुक्ति के लिये ----- सरकार की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है और उसका त्याग-पत्र ----- पूर्वाह्न/अपराह्न से स्वीकार कर लिया गया है। उसने-----में ----- को पूर्वाह्न/अपराह्न से सेवा में प्रवेश कर लिया है।

3. अंतिम निधि कटौती उसके वेतन से, कार्यालय बिल संख्या-----दिनांक----- रुपये----- (-----रुपये) ----- खजाने में/खजाना वाउचर संख्या-----, कटौती की राशि ----- रुपये और अग्रिम के पुनःभुगतान की वसूली -----रुपये कर ली गई थी।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्नलिखित अग्रिम लिये हैं, जिनके सम्बन्ध में -----रुपये की -----किस्तें अभी वसूल की जानी हैं और निधि खाते में जमा की जानी हैं/सेवा त्यागने/सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश पर जाने या उसके बाद ठीक पहले पूर्वगामी बारह मास के दौरान उसे स्वीकृत किये गये अग्रिम (अग्रिमों)/प्रत्याहरण (प्रत्याहरणों) का विस्तृत विवरण निम्न अनुसार है-

क्रम संख्या	अग्रिमों/प्रत्याहरणों की राशि	नगद पाने का स्थान	वाउचर संख्या और दिनांक
1.			
2.			
3.			
4.			

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसने केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकार के अधीन या राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले निगमित निकाय में नियुक्ति के लिये राज्य सरकार से पूर्व अनुमति से सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नहीं दिया है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि महालेखाकार, हरियाणा की सहमति के बिना इसके बाद अभिदायकर्ता को कोई अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. प्रमाणित किया जाता है कि अभिदायकर्ता/दावेदार ने दिनांक ----- मास ----- वर्ष -----को आवेदन किया है।

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध च
प्ररूप संख्या पी.एफ.-6
(देखिए नियम 24)

नामनिर्देशितियों या किन्हीं अन्य दावेदारों, जहां कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, को अंतिम भुगतान हेतु आवेदन पत्र

सेवा में

महालेखाकार,
हरियाणा, चण्डीगढ़।
(कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

श्रीमान,

निवेदन है कि श्री/सुश्री-----के सामान्य भविष्य निधि खाते में संघों का अंतिम भुगतान करने की कृपया व्यवस्था करवा दें। इस सम्बन्ध में अपेक्षित आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं :-

- सरकारी कर्मचारी का नाम :
- जन्म तिथि :
- सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद :
- मृत्यु की तिथि :
- मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में मृत्यु का प्रमाण (नगरपालिका प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी) :
- अभिदायकर्ता का सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या (पूर्णा) :
- अभिदायकर्ता की मृत्यु के समय उसके खाते में जमा राशि यदि ज्ञात है :
- अभिदायकर्ता की मृत्यु के समय नामनिर्देशित जीवित व्यक्तियों का विवरण, यदि नामनिर्देशन किया गया हो :

नामनिर्देशित का नाम	अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध	नामनिर्देशित का हिस्सा	विशेष कथन
1. -----	-----	-----	-----
2. -----	-----	-----	-----
3. -----	-----	-----	-----

- यदि नामनिर्देशन परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में है, तो परिवार का विवरण यदि अभिदायकर्ता ने बाद में परिवार अर्जित किया है :

नाम	अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध	मृत्यु की तिथि को आयु	विशेष कथन
1. -----	-----	-----	-----
2. -----	-----	-----	-----
3. -----	-----	-----	-----

- यदि कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, अभिदायकर्ता की मृत्यु की तिथि को परिवार के जीवित सदस्यों के विवरण। बेटी या अभिदायकर्ता के मृतक पुत्र की बेटी जिसकी शादी अभिदायकर्ता की मृत्यु से पूर्व हुई है, के मामले में, उसके नाम के सामने यह उल्लेख किया जाये कि क्या अभिदायकर्ता की मृत्यु की तिथि को उसका पति जीवित था।

नाम	अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध	मृत्यु की तिथि को आयु	विशेष कथन
1. -----	-----	-----	-----
2. -----	-----	-----	-----
3. -----	-----	-----	-----

11. प्राकृतिक/कानूनी संरक्षक का नाम :
(ऐसे मामले में जब राशि अव्यस्क बच्चे को देय है)
12. यदि अभिदायकर्ता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है और कोई नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, व्यक्तियों के नाम जिन्हें सामान्य भविष्य निधि राशि देय है (प्रोबेट पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र इत्यादि से समर्थित) :

नाम	अभिदायकर्ता के साथ सम्बन्ध	मृत्यु की तिथि को आयु	विशेष कथन
1. -----	-----	-----	-----
2. -----	-----	-----	-----
3. -----	-----	-----	-----

13. भुगतान कार्यालय-----के माध्यम से -----खजाना/उपखजाना के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी/मैजिस्ट्रेट द्वारा सम्पक रूप से सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:-
- (i) पहचान के व्यक्तिगत चिन्ह
- (ii) बाएं/दाएं हाथ के अंगूठे या अंगुली के छापे (निराक्षर दावेदारों के मामले में)
- (iii) दो नमूना हस्ताक्षर (साक्षर दावेदार के मामले में)

भवदीय

स्थान-----
दिनांक-----

(दावेदार के हस्ताक्षर)
(पूरा नाम तथा पता)

(कार्यालयाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

महालेखाकार, हरियाणा को आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित उपरोक्त विवरण विधिवत् सत्यापित है।

2. श्री/सुश्री-----का सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-----है।
3. उसकी दिनांक-----को मृत्यु हो गई थी। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है (प्रति संलग्न)।
4. सामान्य भविष्य निधि की अंतिम कटौती उसके -----मास के वेतन से खजाना वाउचर संख्या -----दिनांक-----को इस कार्यालय के बिल संख्या----- दिनांक-----को -----रुपये (-----रुपये) खजाना चालान संख्या-----दिनांक-----द्वारा-----रुपये और वसूली राशि-----रुपये आहरित की गई थी।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उसने निम्न अग्रिम लिये थे, जिनके सम्बन्ध में -----किस्तें जो-----रुपये की हैं वसूल की जानी हैं और निधि खाते में जमा की जानी हैं। उसकी मृत्यु की तिथि के तुरंत पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान उसे दिए गये प्रत्याहरणों का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	अग्रिमों/प्रत्याहरणों की राशि	नगद पाने का स्थान	वाउचर संख्या और दिनांक
1.			
2.			
3.			
4.			

6. प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार ने दिनांक -----मास----- वर्ष-----को आवेदन किया था।

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध छ

प्ररूप संख्या पी.एफ.-7

(देखिए नियम 15)

श्री/सुश्री-----को-----के सम्बन्ध में खर्चों को पूरा करने के लिये उसके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-----से-----रुपये (केवल-----रुपये) के अग्रिम की हरियाणा सामान्य भविष्य निधि के नियमों के नियम-----के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अग्रिम की वसूली-----मासिक किस्तों में होगी और प्रत्येक मासिक किस्त-----रुपये की होगी, आहरण मास-----के उत्तरवर्ती अगले मास के वेतन से शुरू होगी।

3. स्वीकृति तिथि को श्री/सुश्री-----के खाते में अतिशेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | -----वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि विवरण के अनुसार अतिशेष | -----रुपये |
| (ii) | पश्चात्तर्वर्ती जमा | -----रुपये |
| (iii) | खाना (i) और (ii) का कुल योग | -----रुपये |
| (iv) | पश्चात्तर्वर्ती अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई है | -----रुपये |
| (v) | स्वीकृति तिथि को अतिशेष खाना (iii) घटाया (iv) | -----रुपये |

(नाम)

दिनांक :

कार्यालयाध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या :

दिनांक :

प्रति अग्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ और अभिदायकर्ता के खाता पुस्तिका में इंदराज के लिये।

2. श्री/सुश्री-----। उसका ध्यान निधि नियमों के नियम-----के उपबंधों की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार एक अभिदायकर्ता जिसे निधि से धन के आहरण की अनुमति प्रदान की गई है, वह स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करे कि जिस प्रयोजन के लिये राशि का आहरण किया गया है, यह उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है। आहरण की तिथि से एक मास के भीतर इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि आहरण की गई राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिस प्रयोजन के लिये स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. खजाना अधिकारी-----।

(हस्ताक्षर)

अनुबन्ध ज

प्ररूप संख्या पी.एफ.-8

प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति आदेश

(देखिए नियम 18)

श्री/सुश्री----- (यहां नाम तथा पदनाम लिखें) को हरियाणा सामान्य भविष्य निधि नियमों के ----- नियम के अधीन उसके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या----- से----- रुपये (केवल----- रुपये) के प्रत्याहरण की स्वीकृति उसे----- सम्बन्ध में खर्च करने के लिये प्रदान की जाती है।

2. इस प्रत्याहरण के लिये निर्धारित शर्तों की सीमाओं के भीतर प्रत्याहरण की राशि।

3. स्वीकृति तिथि को श्री/सुश्री ----- के खाते में अतिशेष का विवरण निम्न प्रकार है:-

- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | वर्ष----- के लिए सामान्य भविष्य निधि विवरणी
अनुसार अतिशेष | ----- रुपये |
| (ii) | पश्चात्पूर्ती जमा | ----- रुपये |
| (iii) | खाना (i) और (ii) का कुल योग | ----- रुपये |
| (iv) | पश्चात्पूर्ती अग्रिम/प्रत्याहरण, यदि कोई है | ----- रुपये |
| (v) | स्वीकृति तिथि को अतिशेष
खाना (iii) घटाया (iv) | ----- रुपये |

(नाम)

विभागाध्यक्ष

दिनांक :

पृष्ठांकन संख्या

दिनांक

प्रति अग्रेषित

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ और अभिदायकर्ता के खाता पुस्तिका में इंदराज के लिये।

2. श्री/सुश्री -----। उसका ध्यान सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम----- के उपबंधों की ओर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार अभिदायकर्ता जिसे निधि से धन के आहरण की अनुमति प्रदान की गई थी, वह स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करे कि धन उस प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया, जिसके लिए यह आहरण किया गया। इस आशय का प्रमाण पत्र कि आहरण राशि उस प्रयोजन के लिए उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, निकासी की तिथि से ----- मास के भीतर प्रस्तुत करें।

3. कार्यालयाध्यक्ष-----।

4. खजाना अधिकारी,-----।

(विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध 'झ'

(देखिये नियम 2 (IV), 15 और 18)

अग्रिम/प्रत्याहरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	नियम	अधिकार की प्रकृति	किसको प्रत्यायोजित	शक्ति की सीमा
01	15 (1) 15 (2) 15 (3) 15 (4) 15 (5)	अग्रिम की स्वीकृति के लिये :- बीमारी, प्रसूति या विकलांगता उच्च शिक्षा बाध्यकर खर्च न्यायालय में विधिक कार्यवाही विभागीय जांच में बचाव	कार्यालयाध्यक्ष	छह मास का वेतन या सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम है और आगे नियम 16 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
02	15 (6)	अग्रिम की स्वीकृति के लिये :- घरलू वस्तु (वस्तुओं) की खरीद	कार्यालयाध्यक्ष	छह मास का वेतन या सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या वस्तु की वास्तविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 16 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
03	18 (1) 18 (2) 18 (3) 18 (4)	प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :- सरकारी एजेन्सी से मकान/फ्लैट/प्लॉट का अर्जन खुले बाजार से मकान/फ्लैट/प्लॉट का अर्जन मकान/फ्लैट के लिये ऋण का प्रतिसंदाय करना भवन स्थल की खरीद	विभागाध्यक्ष	सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत या वास्तविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 19 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
04	18 (5) 18 (6) 18 (7)	प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :- मकान/फ्लैट में परिवर्धन या प्रत्यावर्तन पैत्रिक मकान का रख-रखाव बेरोजगार बच्चों के व्यवस्थापन के लिये वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्जित करने या कारोबार स्थापित करना	विभागाध्यक्ष	सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या वास्तविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 19 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
05	18 (8)	प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :- बच्चे की उच्च शिक्षा	विभागाध्यक्ष	(i) प्रारम्भिक प्रवेश के लिये- प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक या संस्थान द्वारा अपेक्षित राशि जो भी कम है और आगे नियम 20 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए। (ii) वार्षिक भुगतान के लिए - प्रत्येक बच्चे के लिये सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या संस्थान द्वारा अपेक्षित राशि जो भी कम है और आगे नियम 20 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए या सत्र भुगतान के लिए - प्रत्येक बच्चे के लिये वर्ष में दो बार सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 25 प्रतिशत या संस्थान द्वारा

				अपेक्षित वास्तविक राशि जो भी कम है और आगे नियम 20 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
06	18 (9) 18(10) 18(11)	प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये:- बेटी की शादी या महिला रिश्तेदार की शादी. बेटे की शादी स्वयं की शादी	विभागाध्यक्ष	सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत और आगे नियम 21 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
07	18(12)	प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये :- मोटर वाहन (वाहनों) की खरीद	विभागाध्यक्ष	सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत या वाहन की वास्तविक लागत जो भी कम है और आगे नियम 22 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।
08	18(13)	अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से पूर्व 90 प्रतिशत प्रत्याहरण की स्वीकृति	विभागाध्यक्ष	सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत और आगे नियम 23 में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए।

टिप्पण 1 : विभागाध्यक्ष केवल अपनी जिम्मेदारी पर और ऐसे निबन्धन तथा शर्तों, जिन्हें वह लगाना चाहे, पर उन्हें उपरोक्त तालिका में दी गई शक्तियों का लिखित में उनके अधीन मुख्यालय/जिला/कोई अन्य कार्यालय (कार्यालयों) में कार्यरत किसी अधिकारी को पुनः प्रयोजित कर सकते हैं। पुनः प्रयोजित करने की प्रतियां सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग और महालेखाकार, हरियाणा को पृष्ठांकित की जायेंगी।

टिप्पण 2 : निम्नलिखित अधिकारी विभागाध्यक्षों के अधिकारों को प्रयोग करेंगे, जहां तक इन नियमों का सम्बन्ध उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके नियंत्रण की अधीनस्थ स्थापना से है :

- (i) मण्डल (लों) आयुक्त (तों) ।
- (ii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
- (iii) पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक (रेंज/रेलवे)।
- (iv) वन-संरक्षक ।
- (v) नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री ।
- (vi) अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
- (vii) जिला शिक्षा अधिकारी/उप मण्डल शिक्षा अधिकारी ।
- (viii) राजकीय कला तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य (यों)।
- (ix) सिविल विभागों के उप मण्डलों में उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) तथा जिला के मुख्यालयों में नगराधीश ।

टिप्पण 3 : कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का अग्रिम/प्रत्याहरण क्रमशः विभागाध्यक्ष और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

टिप्पण 4 : स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उन द्वारा स्वीकृत अग्रिमों/प्रत्याहरणों की समेकित सूची प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही विभागाध्यक्ष को भेजेगा और इसमें अग्रिम/प्रत्याहरण का पूर्ण विवरण जैसे कि अभिदायकर्ता का नाम, सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या, राशि और प्रयोजन अंकित करेगा ताकि अभिदायकर्ता के सम्बद्ध सामान्य भविष्य निधि खाते से वास्तविक अग्रिम/प्रत्याहरण का सत्यापन किया जा सके। विभागाध्यक्ष अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा स्वीकृत अग्रिम/प्रत्याहरण जिसमें मुख्यालय पर स्वीकृत अग्रिम/प्रत्याहरण शामिल है का समेकन करेगा और इनका महालेखाकार हरियाणा के साथ मिलान किया जायेगा।

टिप्पण 5 : अभिदायकर्ता, जिसने अंतिम प्रत्याहरण के लिये आवेदन किया हुआ है और उसका आवेदन महालेखाकार को अग्रेषित किया जा चुका है, को अग्रिम/प्रत्याहरण की स्वीकृति केवल महालेखाकार, हरियाणा से सहमति प्राप्त होने पर ही की जाएगी।

अनुबन्ध 3
(देखिए नियम-12)

सामान्य भविष्य निधि संचय पर वर्ष 2003-04 के लिये निम्न आंकड़ों के आधार पर ब्याज का आंकलन :-

क्रम	विवरण	राशि
संख्या		
1.	प्रारम्भिक अतिशेष 1-4-2003 को	2,25,980/- रुपये
2.	मासिक अभिदाय	प्रतिमास 3,000/- रुपये
3.	6/2003 को महंगाई भत्ते का बकाया जमा	2,214/- रुपये
4.	बेटी की सगाई रस्म के लिये 12/12/03 (प्रतिमास 1000/- रुपये की दर से 25 किस्तों में वसूली) को अदा अग्रिम	25,000/- रुपये
5.	2/2004 को जमा महंगाई भत्ते का बकाया	3,035/- रुपये
6.	बेटे की उच्च शिक्षा के लिये 4-3-2000 को प्रत्याहरण	30,000/- रुपये
7.	वर्ष के दौरान ब्याज दर	8% प्रति वर्ष
हल		

भुगतान का मास	अभिदाय	अग्रिमों की वसूली	कुल	आहरण	अतिशेष	मासिक गुणनफल
04/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X12=36000
05/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X11=33000
06/2003	3000+2214	—	5214	—	5214	5214X10=52140
07/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X9=27000
08/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X8=24000
09/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X7=21000
10/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X6=18000
11/2003	3000	—	3000	—	3000	3000X5=15000
12/2003	3000	—	3000	25000	(-)22000	(-)22000X4=(-)88000
01/2004	3000	1000	4000	—	4000	4000X3=12000
02/2004	3000+3035	1000	7035	—	7035	7035X2=14070
03/2004	3000	1000	4000	30,000	(-)26000	(-)26000X1=(-)26000
						138210

वार्षिक गुणनफल

(1)	प्रारम्भिक अतिशेष	2,25,980.00 रुपये
(2)	वित्तीय वर्ष का गुणनफल 138210 भाग 12 = 11,517.50	11,517.50 रुपये
कुल (1+2)		2,37,497.50 रुपये
ब्याज = 237497.50 X 8% = 18999.80 अर्थात्		19,000.00 रुपये

परिशिष्ट क
[देखिए नियम 3 (2)]
भविष्य निधि अधिनियम, 1925

सरकारी भविष्य निधियों और अन्य भविष्य निधियों से सम्बन्धित विधि संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम

चूंकि सरकारी भविष्य निधियों और अन्य भविष्य निधियों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करना समीचीन है।
अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 है।
- (2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं :- इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,-

- (क) "अनिवार्य निक्षेप" से किसी भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय या निक्षेप अभिप्रेत है जो उस निधि के नियमों के अधीन, जीवन बीमा की किसी पालिसी के सम्बन्ध में प्रीमियम के संदाय या किसी कुटुम्ब पेंशन निधि के सम्बन्ध में अभिदाय या प्रीमियम के संदाय के प्रयोजन से अन्यथा, मांग पर तब तक प्रतिसंदेय नहीं है जब तक कोई विनिर्दिष्ट घटना न हो जाए और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो किसी ऐसे अभिदाय, निक्षेप, या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत हो जाती है और कोई ऐसा अभिदाय, निक्षेप, अंशदान, ब्याज या वृद्धि भी जो ऐसी किसी घटना होने के पश्चात् अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में बाकी बच जाती है, इसके अन्तर्गत है ;
- (ख) "अंशदान" से कोई ऐसी रकम अभिप्रेत है जो किसी भविष्य निधि में उस निधि का प्रबन्ध करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा उस निधि में किसी खाते में जमा अभिदाय या निक्षेप या अतिशेष के परिवर्धन के तौर पर जमा की गई है; और "अंशदायी भविष्य निधि" से ऐसी भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसके नियम अंशदानों को जमा करने के लिए उपबंध करते हैं ;
- (ग) "आश्रित" से किसी भविष्य निधि में अभिदाय या निक्षेप करने वाले किसी मृत व्यक्ति के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं, अर्थात् पत्नी, पति, माता पिता, संतान, अवयस्क भाई, अविवाहित बहिन और मृत पुत्र की विधवा तथा संतान, और जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहां पितामह-पितामही ;
- (घ) "सरकारी भविष्य निधि" से ऐसी कोई भविष्य निधि अभिप्रेत है जो रेल भविष्य निधि से भिन्न है और जो सेक्रेटरी आफ स्टेट, केन्द्रीय सरकार, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार से, उस सरकार की सेवा में व्यक्तियों के अथवा शैक्षिक संस्थाओं में नियोजित अथवा केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान निकायों द्वारा नियोजित किसी वर्ग के व्यक्तियों या किन्हीं वर्गों के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, तथा इस अधिनियम में सरकार के प्रति निर्देशों को तदनुसार अर्थ दिया जाएगा।
- (ङ) "भविष्य निधि" से ऐसे निधि अभिप्रेत हैं जिसमें किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के अभिदाय या निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं और उनके पृथक् खातों में रखे जाते हैं, और कोई अंशदान तथा कोई ऐसा ब्याज या वृद्धि जो ऐसे अभिदाय, निक्षेप या अंशदान पर निधि के नियमों के अधीन प्रोद्भूत होती है इसके अंतर्गत है ;
- (च) "रेल प्रशासन" से अभिप्रेत है —
 - (i) भारत के किसी भाग में या तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी विशेष अधिनियम या किसी भारतीय विधि के अधीन अथवा सरकार के साथ की गई किसी संधि के अधीन किसी रेल या ट्राम का प्रशासन करने वाली कोई कम्पनी, या
 - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किसी रेल या ट्राम का प्रबन्धक, और उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार इसके अन्तर्गत है ;
- (छ) "रेल भविष्य निधि" से किसी रेल प्रशासन के प्राधिकार से उसके किसी वर्ग या किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई भविष्य निधि अभिप्रेत है।

3. **अनिवार्य निक्षेप का संरक्षण .-** (1) किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि का कोई अनिवार्य निक्षेप किसी भी प्रकार से समनुदेशित या भारित नहीं किया जा सकेगा और अभिदायकर्ता अथवा निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के सम्बन्ध में किसी सिविल, राजस्व या दाण्डिक न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकेगा तथा न तो कोई शासकीय समनुदेशिनी और न कोई रिसीवर ही, जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) के अधीन नियुक्त किया गया हो, किसी ऐसे अनिवार्य निक्षेप का हकदार होगा और न उसका उस पर कोई दावा ही होगा।

(2) किसी ऐसी निधि में किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के समय जमा कोई राशि, जो निधि के नियमों के अधीन उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के किसी आश्रित को अथवा ऐसे व्यक्ति को संदेय है जो इस निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए और उस दशा को छोड़कर जब आश्रित अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए किसी समनुदेशन के अधीन, किसी समनुदेशिनी के अधिकारों के भी अधीन रहते हुए, आश्रित में निहित होगी और मृत व्यक्ति द्वारा उपगत अथवा उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु से पूर्व आश्रित द्वारा उपगत किसी ऋण या अन्य दायित्व से, यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, मुक्त होगी।

4. **प्रतिसंदायों के बारे में उपबंध .-** (1) जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के नियमों के अधीन किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि या उसका अतिशेष इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती करने के पश्चात् संदेय हो गया है तब वह अधिकारी, जिसका कर्तव्य उसका संदाय करना है, यथास्थिति, उस राशि या अतिशेष का अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को संदाय करेगा अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई तो—

(क) यदि वह राशि या अतिशेष अथवा कोई भाग धारा 3 के उपबंधों के अधीन किसी आश्रित में निहित है तो उसका संदाय उस आश्रित को या ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसके निमित्त संदाय प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है ; या

(ख) यदि सम्पूर्ण राशि या अतिशेष पांच हजार से अधिक नहीं है तो उसका या उसके किसी भाग का संदाय, जो खंड (क) के अधीन संदेय नहीं है, निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को अथवा यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्देशित नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो उसे प्राप्त करने के लिए अन्यथा उसको हकदार प्रतीत हो ; या

(ग) यदि ऐसी राशि या अतिशेष या उसका कोई भाग खण्ड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को संदाय नहीं है, तो उसका संदाय —

(i) निधि के नियमों के अधीन उसे प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रबन्ध उसे देना साक्ष्यित करने वाला प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, अधिनियम, 1889 के अधीन या 1827 के मुम्बई विनियम 8 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र, जो उसके धारक को ऐसी राशि, अतिशेष या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाता हो, पेश किए जाने पर करेगा, या

(ii) यदि कोई नामनिर्देशित व्यक्ति नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को करेगा जो ऐसा प्रोबेट, प्रशासन पत्र या प्रमाण पत्र पेश करे :

परन्तु जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा सम्पूर्ण राशि या उसका कोई भाग इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित किया गया है, और समनुदेशन की लिखित सूचना अधिकारी को समनुदेशिनी से मिल चुकी है, वहां वह अधिकारी इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई कटौती तथा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की विधवा या संतान को या उसके निमित्त खंड (क) के अधीन देय कोई संदाय करने के पश्चात्,—

(i) यदि अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता, अथवा यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो वह व्यक्ति जिसको किसी विधिमन्य समनुदेशन के अभाव में वह राशि या अतिशेष उस उपधारा के अधीन संदेय होता, अपनी लिखित सहमति दे देता है तो, यथास्थिति, उस राशि या भाग का या उसके अतिशेष का संदाय समनुदेशिनी को करेगा, या

(ii) यदि ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होती है तो, यथास्थिति, उस राशि, भाग या अतिशेष का संदाय, उसे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में किसी सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय तक के लिए रोक रखेगा।

- (2) **उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत संदाय करने पर,** यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन, अभिकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि में से इतनी राशि के सम्बन्ध में, जितनी इस प्रकार संदत्त की गई रकम के बराबर है समस्त दायित्व से पूर्ण रूप से उन्मोचित हो जाएगा।

5. **नामनिर्देशितियों के अधिकार** — (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उस निधि में अपने खाते में जमा राशि या उसके किसी भाग के, वसीयती या अन्य, किसी बयान में किसी बात के होते हुए भी, जहां निधि के नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से किया गया कोई नामनिर्देशन, उस राशि के संदेय हो जाने के पूर्व, अथवा उस राशि के संदेय हो जाने पर उसका संदाय किए जाने के पूर्व, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर ऐसी सम्पूर्ण राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करना तात्पर्यित करता है वहां उक्त व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए उस अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को यथापूर्वोक्त मृत्यु पर, यथास्थिति, ऐसी राशि या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा, किन्तु यदि —

- (क) ऐसा नामनिर्देशन उसी प्रकार किए गए दूसरे नामनिर्देशन से किसी समय परिवर्तित किया गया है अथवा उन नियमों द्वारा विहित रीति से और प्राधिकारी को दी गई सूचना से अभिव्यक्तता रद्द कर दिया गया है ; अथवा
- (ख) ऐसा नामनिर्देशन किसी समय उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने के कारण अविधिमान्य हो गया है, तो यह व्यक्ति हकदार नहीं होगा, और यदि उक्त व्यक्ति, अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता से पहले मर जाता है तो नामनिर्देशन, जहां तक वह उक्त व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार से सम्बन्धित है, शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा :

परन्तु जहां निधि के नियमों के अनुसार, नामनिर्देशन में मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से उपबन्ध किया गया है वहां ऐसा अधिकार, उक्त व्यक्ति की यथापूर्वोक्त मृत्यु हो जाने पर ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा।

- (2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या 1827 के मुम्बई विनियम 8 में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को जो यथापूर्वोक्त हकदार हो जाता है ऐसी राशि या भाग का संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाने वाला हक प्रमाणपत्र, यथास्थिति, उस अधिनियम या उस विनियम के अधीन दिया जा सकेगा और ऐसा प्रमाणपत्र मृत व्यक्ति की सम्पदा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रोबेट या प्रशासन पत्र दिए जाने से अविधिमान्य या अधिकांत हुआ नहीं समझा जाएगा।
- (3) भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1946 (1946 का 11) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध उस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व किए गए समस्त ऐसे नामनिर्देशनों को भी लागू होंगे।

परन्तु इस प्रकार संशोधित इस उपधारा के उपबन्ध किसी ऐसे मामले पर प्रभाव नहीं डालेंगे जिसमें उक्त तारीख से पूर्व, किन्हीं नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से किए गए किसी नामनिर्देशन के अनुसरण में किसी राशि का संदाय कर दिया गया है या निधि के नियमों के अधीन वह संदेय हो गई है।

6. **कटौतियां करने की शक्ति** — जब किसी सरकारी भविष्य निधि या रेल भविष्य निधि के, जो अंशदायी भविष्य निधि है, किसी अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा राशि संदेय हो जाती है तब, यदि निधि के नियमों में उस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निदेश देता है तो उसमें से निम्नलिखित रकम काट ली जाएगी और यथास्थिति, सरकार या रेल प्रशासन को संदत्त कर दी जाएगी —

- (क) अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता द्वारा उपगत किसी दायित्व के अधीन सरकार या रेल प्रशासन को देय कोई रकम किन्तु जो किसी भी दशा में अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता के खाते में जमा किन्हीं अंशदानों की तथा किसी ऐसे ब्याज या वृद्धि की, जो ऐसे अनुदानों पर प्रोद्भूत हो गई है, कुल रकम से अधिक नहीं होगी; या
- (ख) जहां अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता को उसके नियोजन से किन्हीं ऐसे कारणों से, जो निधि के नियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, पदच्युत कर दिया गया है अथवा जहां उसने ऐसे नियोजन को उसके प्रारम्भ के पांच वर्ष के अन्दर त्याग दिया है, वहां किन्हीं ऐसे अंशदानों, ब्याज और वृद्धि की सम्पूर्ण रकम या उसका कोई भाग।

- 6 क. **सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर पूर्व अनुज्ञा के बिना वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की दशा में सरकारी अंशदानों को रोक लेना या उनकी वसूली** — (1) इस धारा में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "केन्द्रीय सरकार का अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि में कोई ऐसा अभिदायकर्ता या निक्षेपकर्ता अभिप्रेत है, जो अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक पूर्व केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 का सदस्य है, किन्तु किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी सेवा-संविदा के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ख) "वाणिज्यिक नियोजन" से व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक कारबार में लगी हुई किसी कम्पनी, सहकारी सोसाईटी, फर्म या व्यंष्टि के अधीन (अभिकर्ता की हैसियत सहित) किसी भी हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :-

- (i) किसी कम्पनी का निदेशक पद ;
- (ii) किसी सहकारी सोसाईटी में अध्यक्ष, सभापति, प्रबन्धक, सचिव, कोषपाल जैसे किसी भी नाम से ज्ञात किसी पद को, चाहे वह निर्वाचित हो या न हो, धारण करना ; और
- (iii) ऐसे विषयों में सलाहकार या परामर्शी के तौर पर या तो स्वतन्त्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में व्यवसाय प्रारम्भ करना, जिनकी बाबत :-
 - (क) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास कोई वृत्तिक अहर्ताएं नहीं हैं और वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है या चलाया जाता है, उसकी शासकीय जानकारी या अनुभव से सम्बद्ध है, या
 - (ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के पास वृत्तिक अहर्ताएं हैं, किन्तु वे विषय, जिनकी बाबत ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ किया जाना है, ऐसे हैं जिनसे यह सम्भव है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन उनके द्वारा धारित पदों के कारण उसके व्यवहारियों को नावाजिब फायदा हो ; या
 - (ग) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को ऐसे कार्य का भार ग्रहण करना है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों से सम्पर्क या संबन्ध अन्तर्गस्त है,

किन्तु किसी ऐसे निगम या कम्पनी में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या प्रर्याप्त रूप से सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में है अथवा किसी ऐसे निकाय में या उसके अधीन नियोजन, जो पूर्ण रूप से या प्रर्याप्त रूप से सरकार के नियन्त्रण में है या उसके द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ग) "सरकारी अंशदान" से भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी अवधि की बाबत किए गए अंशदान अभिप्रेत हैं ;

(घ) "विहित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, उस दशा में जब वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है, किसी अंशदायी भविष्य निधि में उसके नाम से जमा किए गए, सरकारी अंशदानों के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1 — इस उपधारा और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से, सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य वर्ग 1 पद पर या किसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही किसी अन्य पद पर सेवा-विच्छेद के बिना पुन नियोजित केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के सम्बन्ध में वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसको केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी सरकारी सेवा में अन्ततः पुनर्नियोजित नहीं रहता।

स्पष्टीकरण 2 — केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के बारे में, जिसे उसकी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान किसी विशिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में अपने बने रहने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को, उस आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो आवश्यक समझे, अनुज्ञा दे सकती हैं, या ऐसे कारणों से, जो आदेश में अभिलिखित किए जाएंगे, अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने में या देने से इन्कार करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :

- (क) जिस नियोजन को ग्रहण करने का विचार है उसकी प्रकृति और नियोजन के पूर्ववृत्त ;
- (ख) क्या उस नियोजन में, जिसे ग्रहण करने का उसका विचार है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसे सरकार का विरोध करना पड़े ;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी ने सेवा के दौरान उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन उसका नियोजन प्राप्त करने का विचार है, ऐसे कोई संव्यवहार किए थे जो इस संदेह के लिए युक्तियुक्त आधार हो सकते हैं कि ऐसे अधिकारी ने उस नियोजक के साथ पक्षपात किया था ;

(घ) कोई अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं।

(5) यदि उपधारा (3) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है, या आवेदक को ऐसे इन्कार की संसूचना नहीं देती है, तो ये समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अनुज्ञा दे दी है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(6) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन देती है या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है तो आवेदक, उस आशय के केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, किसी ऐसी शर्त या इन्कार के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, और केन्द्रीय सरकार उस पर ऐसे आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश जो ऐसी शर्त को रद्द करने या किन्हीं शर्तों के बिना ऐसी अनुज्ञा देने वाले आदेश से भिन्न है, अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या कोई ऐसी शर्त भंग करता है जिस पर कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए उसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा दी गई है तो केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जो उसमें अभिलिखित किए जाएंगे, यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे सरकारी अंशदानों के, जो उस अधिकारी के सम्बन्ध में किए गए हों, इतने भाग का हकदार नहीं होगा जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि वह उसे प्राप्त कर चुका है तो यह निदेश देने के लिए सक्षम होगी कि वह सरकारी अंशदानों के उक्त भाग के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को वापस करे :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, सम्बन्धित अधिकारी को ऐसी घोषणा या निदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :-

- (i) सम्बन्धित अधिकारी की वित्तीय परिस्थिति ;
- (ii) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे उपलब्धियां ;
- (iii) ऐसी अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं।

(8) यदि कोई ऐसी रकम, जो उपधारा (7) के अधीन किसी आदेश द्वारा वापस की जानी अपेक्षित है, विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती है तो वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(9) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सम्बन्धित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(10) इस धारा के उपबंध, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या किसी अंशदायी भविष्य निधि को लागू नियमों में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

(11) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. **सदभावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण .—** इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

8. **अधिनियम को अन्य भविष्य निधियों को लागू करने की शक्ति .—**

(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि (धारा 6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सब उपबंध स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे, और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तदनुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, सरकार हो।

(2) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि (धारा 6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सब उपबंध, अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी के अथवा ऐसी संस्थाओं के किसी समूह के कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तदनुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और वह प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में निधि है, सरकार हो :

परन्तु धारा 6 इस प्रकार लागू होगी मानो उस धारा में निर्दिष्ट अंशदान करने वाला प्राधिकारी, सरकार हो।

(3) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था का नाम जोड़ सकेगी जिसे वह ठीक समझे और इस प्रकार जोड़ा जाना ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम द्वारा किया गया हो।

(4) इस धारा में "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है —

(क) किसी छावनी प्राधिकरण, किसी महापत्तन के लिए पत्तन प्राधिकरण और किसी ऐसी संस्था के संबंध में, जो या जिसके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत प्रतीत हों, केन्द्रीय सरकार ; और

(ख) अन्य मामलों में राज्य सरकार।

स्पष्टीकरण .— सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था के सम्बन्ध में "राज्य सरकार" से उस राज्य की राज्य सरकार अभिप्रेत है जिसमें वह सोसाईटी रजिस्ट्रीकृत है।

9. **सैनिकों की सम्पदाओं के बारे में व्यावृत्तियां .—** धारा 4 या धारा 5 की कोई बात किसी ऐसी सम्पदा के धन को लागू नहीं होगी जिसके प्रबन्ध के प्रयोजन के सम्बन्ध में रैजीमेंटल डैट एक्ट, 1893 (56 और 57 विक्ट.सी.5) लागू होता है।

10. **निरसन .—** निरसन अधिनियम, 1927(1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

अनुसूची

(जोड़ी नहीं गई)

परिशिष्ट-ख

[देखिए नियम 16(9)]

नियम 21 में वर्णित अनुमोदित पाठ्यक्रमों की सूची

क्रम संख्या पाठ्यक्रम का नाम

1. मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित यांत्रिकी एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा कोर्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, टेलिकम्यूनिकेशन/रेडियो इंजीनियरिंग, मेटालर्जी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लैडर टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कैमीकल टेक्नोलॉजी इत्यादि।
2. मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा संचालित यांत्रिकी एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री कोर्स जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, टेलिकम्यूनिकेशन/रेडियो इंजीनियरिंग, मेटालर्जी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लैडर टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कैमीकल टेक्नोलॉजी इत्यादि।
3. विश्वविद्यालयों द्वारा तथा मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित यांत्रिकी एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर कोर्स।
4. मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित आर्कीटेक्चर, नगर योजना तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स।
5. मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित वाणिज्य में डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्स।
6. मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित प्रबन्धन में डिप्लोमा कोर्स।
7. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा संचालित कृषि, पशु विज्ञान तथा सम्बन्धित विषयों में डिग्री कोर्स।
8. मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित आर्ट/अप्लाइड आर्ट तथा सम्बन्धित विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स।
9. मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित मैडीकल पाठ्यक्रमों (जिनमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियाँ) शामिल हैं।
10. विज्ञान में स्नातक (गृह विज्ञान) पाठ्यक्रम।
11. मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होटल प्रबन्धन में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स।
12. गृह विज्ञान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कोर्स।
13. मैडिसन में प्रीप्रोफेशनल कोर्स यदि मैडिसन में नियमित पांच वर्षीय कोर्स या उसका हिस्सा है।
14. जीव रसायन विज्ञान में पी.एच.डी.।
15. कानून में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स।
16. माइक्रोबायोलॉजी में "आनर्स" कोर्स।
17. संघ संस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट।
18. संघ संस्थान के कास्टस तथा वर्क अकाउंटेंट।
19. वाणिज्य प्रशासन या प्रबन्धन में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
20. सांख्यिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
21. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान से कम्पनी सचिव कोर्स।
22. वाणिज्यिक जहाजों के भावी पैकजनेटिंग अधिकारियों को प्री-सी का कोर्स या प्रशिक्षण जहाज "राजिन्द्रा" पर प्रशिक्षण।
23. खनन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग निदेशालय द्वारा संचालित खनन इंजीनियरिंग कोर्स।

भास्कर चटर्जी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FINANCE DEPARTMENT****Notification**The 9th May, 2006.

No. 4/4(2)2003-2FR .-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to regulate the General Provident Fund, namely :-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana General Provident Fund Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Application and effect of rules.

2. (1) Except as otherwise provided, these rules shall apply to all the categories of Government employees who are under the administrative control of the Haryana Government and whose pay is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana, namely :-

- (i) members of State Service, Group A to D;
- (ii) members of State Service belonging to Haryana Public Service Commission and Haryana Legislative Assembly;
- (iii) any other Government employee or class of Government employees to whom the competent authority may by general or special order, make these rules applicable.

- (2) These rules shall not apply to the following categories :-

- (i) employees working on contract basis;
- (ii) employees working on ad-hoc basis;
- (iii) work-charged employees;
- (iv) daily wages employees;
- (v) employees working as apprentices;
- (vi) any other category of Government employee to whom the competent authority may by general or special order, direct that these rules shall not apply to them.

- (3) Nothing in these rules shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the General Provident Fund as heretofore, or of constituting any new fund.

Definitions.

3. (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (i) **"Accountant General"** means the Head of Office of Accountant General (Accounts and Establishment) representing the Comptroller and Auditor General of India, who maintains the accounts of the Haryana State and exercises audit functions in relation to those accounts on behalf of the Comptroller and Auditor General of India;
 - (ii) **"Administrative Department"** means a department of the Haryana Government, other than the Finance Department;
 - (iii) **"Child"** means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognized by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890. In a case in which a person has given a child in

adoption to another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognized as conferring the status of a natural child, such a child should, for the purpose of these rules, be considered as excluded from the family of the natural father;

(iv) "**competent authority**" in relation to the exercise of any power under these rules means the Administrative Department concerned of Government acting in consultation with the Finance Department or any other authority to which such powers may be delegated by or under these rules. A list of such authorities is given in Annexure-I;

(v) "**dependent**" means any of the relatives of a subscriber in a fund, namely, a wife, husband, parent, child, minor brother, unmarried sister and a deceased son's widow and child and where no parent of subscriber is alive then paternal grand-parent;

(vi) "**family**" means,-

(a) in the case of a **male subscriber**, the wife (or wives where permissible under personal law), children, widow (or widows where permissible under personal law) and children of a deceased son(s) of the subscriber and also includes parents, unmarried sisters and minor brothers of an unmarried subscriber:

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently intimates by express notice in writing to the Accountant General that she shall continue to be so regarded;

(b) In the case of a **female subscriber**, the husband and the children of a subscriber, widow (or widows where permissible under personal law) and children of a deceased son(s) of a subscriber and also includes parents, unmarried sisters and minor brothers of an unmarried subscriber:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accountant General expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels by express notice in writing to the Accountant General through her Head of Office.

(vii) "**Finance Department**" means the Finance Department of the Haryana Government.

(viii) "**first appointment**" means the appointment of a person not at the time of appointment holding any appointment under Government, even though he may have previously held such an appointment.

(ix) "**foreign service**" means service in which a Government employee receives his pay with the sanction of Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of State.

(x) "**Fund**" means "The General Provident Fund of Haryana Government employees."

"**Government**" means the Haryana Government in the Administrative Department.

- (xii) **"Head of Department"** means the authority declared to be as such by the Government in consultation with the Finance Department.
- (xiii) **"Head of Office"** means the authority declared to be as such by Government/Head of Department.
- (xiv) **"leave"** means any kind of leave recognized by the Civil Services Rules applicable to Haryana Government employees.
- (xv) **"leave salary"** means the monthly amount paid in lieu of pay to a Government employee while on leave.
- (xvi) **"nominee"** means the person(s) conferred upon the right to receive the amount at credit in the account of the subscriber after his death.
- (xvii) **"Pay"** means basic pay drawn monthly in the scale by the subscriber. It also includes dearness pay, special pay and personal pay.
- (xviii) **"quitting service"** means and includes retirement, dismissal, removal, resignation, retrenchment from service, disappearance, death and absorption to bodies under the control of Central/ State Government(s).
- (xix) **"subscriber"** means the member of the Fund.
- (xx) **"subsistence allowance"** means a monthly allowance paid to a Government employee under suspension who is not in receipt of pay or leave salary.
- (xxi) **"Year"** means a financial year i.e. commencing on 1st April of any year and ending on 31st March of the succeeding year.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Provident Funds Act, 1925 (Act XIX of 1925), as reproduced in **Appendix A**.

Constitution of the fund.

4. (1) The fund shall be maintained in India in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in the books of Government to an account named "The General Provident Fund of Haryana Government employees". Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules shall be transferred to "Deposits" at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

Conditions of eligibility.

5. (1) All temporary Government employees (including all probationers and all re-employed pensioners) and all permanent Government employees shall subscribe to the Fund. Probationers shall be treated as temporary Government employees for the purpose of this rule. They shall subscribe to the fund immediately on joining service after obtaining General Provident Fund account number. The subscription shall commence from the month following the month during which the General Provident Fund account number is received in the office. A subscriber, who is re-employed without break other than on contract basis shall continue to subscribe to his existing Fund account immediately after re-employment.

(2) In the case of an employee appointed on transfer or otherwise to a post under Haryana Government from service of another State Government or from the Central Government shall subscribe to the Fund on joining the post in the Haryana Government after obtaining the General Provident Fund account number. The amount already standing to his credit in the

previous employment may be transferred to the new General Provident Fund account number by his previous employer with the written consent of the employee concerned.

(3) In the case of an employee appointed on transfer or otherwise to a post under Haryana Government from service of Boards and Corporations controlled by Haryana/other State Government or Central Government shall subscribe to the Fund on joining the post in the Haryana Government after obtaining the General Provident Fund account number. The amount already standing to his credit in the previous employment may be transferred to the new General Provident Fund account number by his previous employer with the written consent of the employee concerned.

(4) In the case of an employee of Haryana Government is transferred/absorbed to a post under Central Government/any other State Government or Boards and Corporations controlled by them, the amount already standing to his credit in the General Provident Fund Account of Haryana State may be transferred to the new employer with the consent of the new employer and employee concerned.

(5) In the case of an employee of Haryana Government is absorbed to a post under Boards and Corporations controlled by Haryana State, the amount standing to his credit in the General Provident Fund account of Haryana State shall be transferred to the concerned Board and Corporation with the consent of the new employer and employee concerned.

*Allotment of
General Provident
Fund account
number.*

6. (1) Every Government employee on joining in the Haryana State shall require to submit an application for admission to General Provident Fund in triplicate in the prescribed application form No. **P.F.1 (Annexure A)**.

(2) The application form as mentioned in sub-rule (1) shall accompany the nomination form in triplicate in **P.F.2 (Annexure B)**.

(3) The Head of Office shall forward the application along with nomination form in duplicate to the Accountant General for allotment of General Provident Fund account number and acceptance of nomination.

(4) The Accountant General shall allot the General Provident Fund account number and also return the second copy of application form indicating General Provident Fund account number thereon along with nomination form duly accepted to the Head of Office.

(5) The Head of Office, on receipt of the General Provident Fund account number shall record the same on the first page of the employee's service book. Necessary entry of contents of nomination shall also be recorded in the service book.

Nomination.

7. (1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Accountant General through the Head of Office, a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund, in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable, has not been paid:

Provided that if, at the time of making the nomination, the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family

Provided further that a nomination made by a Muhammadan subscriber in favour of his adopted child should not be accepted, as adoption is not recognized in Muhammadan Law.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), he shall specify in the nomination the share payable to each of the nominee in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time;

(3) Every nomination shall be made in Form No. **P.F.2 (Annexure B)**.

(4) A subscriber may at any time cancel/revise a nomination by sending a notice in writing to the Accountant General, through Head of Office, keeping in view the conditions mentioned in sub-rule (1) above. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination, through Head of Office, in accordance with the provisions of this rule. If the subscriber fails to furnish a fresh nomination and the General Provident Fund deposit becomes payable as a result of death of the subscriber, the payment shall be made in accordance with the rules of the Fund as if no valid nomination subsists.

(5) A subscriber may provide in a nomination, -

- (a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass on to such other person or persons as may be specified in the nomination provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.
- (b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein:

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family:

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-rule (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-rule (5) or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Accountant General through his Head of Office, a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provision of this rule.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, takes effect on the date on which it is received by the Head of Office.

(8) Nomination made while in service can be revised even after retirement by the subscriber so long as the amount remains unpaid:

Provided that the revised nomination is made in accordance with the provisions of the relevant rules.

(9) Nominee facing trial for the murder of the subscriber may be denied payment till the decision of the court. If on the conclusion of the criminal proceedings, the person concerned is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the subscriber, his share shall be paid to him. If the nominee is convicted for the murder or abetting in the murder of the subscriber, he shall stand debarred from receiving his share which shall be payable to other nominees or eligible members of the family or legal heir(s) of the subscriber, as per provisions of these rules.

(10) The payment of Fund money in accordance with the nomination earns a valid discharge for the Government but if any court of law decrees that payment should be made to persons other than the nominee(s), before actual payment has been made to the nominee(s), the orders of the court shall be complied with.

(11) If a subscriber dies having no family member and valid nomination then the payment shall be made to the claimant on production of succession certificate from the court of law.

*Subscriber's
account.*

8. An account shall be opened in the name of each subscriber in the office of the Accountant General, in which shall be shown—

- (i) his subscriptions;
- (ii) interest as provided by rule-12, on subscriptions;
- (iii) advances and withdrawals from the Fund; and
- (iv) recoveries of advances.

*Conditions of
subscription.*

9. (1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during the period of suspension:

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay:

Provided further that a subscriber on reinstatement with full pay and allowances after a period passed under suspension shall be required to pay the arrear of subscription in one instalment from his arrears.

(2) The subscriber shall intimate to his Head of Office regarding his election not to subscribe during the leave referred to in the first proviso of sub-rule (1). Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

(3) The option of a subscriber intimated under sub-rule (2) above shall be final.

(4) When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation within India or out of India, he shall remain subject to the rules of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

(5) If any subscriber, who is transferred from one establishment to another establishment within the State he shall continue to subscribe to the same General Provident Fund account number.

(6) The subscription to Fund shall be stopped six months prior to retirement on superannuation.

*Rates of
subscription.*

10. (1) The amount of subscription shall be fixed each year by the subscriber himself, subject to the following conditions: -

- (a) it shall be expressed in whole rupees;
- (b) it may be any sum, so expressed not less than 8% of his pay, leave salary equal to full pay and not more than his pay, leave salary equal to full pay.

(2) The subscription as mentioned in sub-rule (1) will be fixed by the subscriber and intimated to the Head of Office by taking into consideration the following conditions:—

- (a) in the case of a subscriber who was in Government service on the 31st March of the preceding year, the pay, leave salary equal to full pay on that day;
- (b) if the subscriber was on leave other than on full pay on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his pay shall be the pay to which he was entitled on the first day after his return to duty;

- (c) if the subscriber was on deputation out of India on the said date, his pay shall be the pay to which he would have been entitled had he been on duty in India;
- (d) if the subscriber who was not in Government service on the 31st March of the preceding year, the pay to which he is entitled on the day he joins the Fund;
- (e) if the subscriber joined the Fund for the first time, his pay shall be the pay to which he was entitled on the date of joining the Fund;
- (f) if the subscriber was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the treasury on account of subscription for the month of April in the current year.

(3) The amount of subscription so fixed shall not be varied due to increase or decrease in pay during the financial year subject to the condition that the subscriber will be at liberty to -

- (a) reduce the subscription once at any time during the course of the year;
- (b) enhance the subscription twice during the course of the year;

Provided that when the amount of subscription is increased, it shall not be more than the pay or leave salary on full pay and when it is reduced, it shall not be less than the minimum subscription prescribed in sub-rule (1).

(4) If the subscriber is on duty for part of a month and on leave other than on full pay for the remainder of that month then the subscription shall not be made for that month.

(5) If a subscriber dies during the course of a month, no subscription shall be made for that month.

Realisation of subscription.

11. (1) When pay of the subscriber is drawn from a Government treasury in India, recovery of subscription shall be made from his pay bills.

(2) In the case of a subscriber on foreign service to a body corporate, owned or controlled by Central or State Government, the subscription shall be recovered and forwarded to the Accountant General by such body through Demand Draft or Treasury Challan.

Interest.

12. (1) Subject to the provisions of sub-rule (6), Government shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year according to the method prescribed from time to time by the Government.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner:-

- (i) on the amount at the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year = interest for twelve months;
- (ii) on sums withdrawn during the current year = interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal;
- (iii) on all sums credited to subscriber's account after the last day of the preceding year = interest from the date of deposit up to the end of the current year;
- (iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee, 50 paise counting as the next higher rupee.

An illustration in this regard is given at Annexure 'J' for ready reference.

(3) When the amount standing at the credit of subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under sub-rule (2) from the beginning of the current year upto the date on which the amount standing at the credit of the subscriber became payable.

(4) The date of deposit shall, in the case of a recovery from pay, be deemed to be the first day of the month in which it is recovered and in the case of an amount forwarded by the subscriber/borrowing agency shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is deposited in the Treasury or received by the Accountant General upto the tenth day of that month, but if it is received after the tenth day of that month then the first day of the succeeding month:

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this rule in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable:

Provided further that in the case of an amount forwarded to the Accountant General of a subscriber on deputation by such body, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month, if it is received by the Accountant General upto the 10th of that month :

Provided further that where the pay for a month is drawn and disbursed on the last working day of the same month, the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscription, be deemed to be the first day of the succeeding month :

Provided further that the lump sum subscription recovered from a subscriber on his reinstatement with full pay and allowances, after a period passed under suspension, will be treated the subscription of the month in which it has been deposited in Treasury.

(5) Payment of interest on the fund balance upto the period of six months after the month of quitting service may be made by the Accountant General. For this purpose the period of six months should be counted after excluding the immediately succeeding month i.e. to say, when a subscriber's last day of quitting service is in the month of May, the period of six months should be computed from July to December and not from June to November. The interest shall be allowed upto the preceding month if the authority is issued upto 15th of the month and the interest shall also be payable for that month in case the authority is issued after 15th and the same shall be made payable on or after the first of the succeeding month. The interest beyond a period of six months shall be authorized as under:-

- (a) The Administrative Department upto a period of two years after fully satisfying that the delay in payment was occasioned by the circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated by an officer not below the rank of Group A and action, if any required, be taken.
- (b) The Finance Department upto any period after fully satisfying that the delay in payment was occasioned by the circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated by an officer not below the rank of Group A and action, if any required, be taken.
- (c) However, if a Court orders that the interest be paid to the subscriber for the delayed period of payment and the court orders have attained finality or it has been opined by the competent legal authority that the case is not fit for appeal, the payment of interest may, after recording the reasons in writing, be made to the subscriber and action, if any required, taken as per clauses (a) and (b) of this sub-rule to avoid further accumulation and payment of interest.

(6) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accountant General through his Head of Office that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the over drawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the Fund, shall be repaid by him with interest thereon in lump sum and in default, be ordered to be recovered, by deduction in lump sum, from the pay of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's pay, recoveries shall be made in monthly instalments not exceeding $1/3^{\text{rd}}$ of his pay till the entire amount together with interest is recovered. The overdrawn amount along with interest in the case of final payment shall be recovered from the pending dues of the employee, gratuity or leave encashment, if unpaid, otherwise consent of the retiree may be obtained for recovery from his pension. If the consent is not given by the retiree then recovery shall be effected through the court of law, if necessary. The rate of interest to be charged for this sub-rule on overdrawn amount would be $2\frac{1}{2}\%$ over and above the normal rate of interest admissible on General Provident Fund amount for the relevant year(s). The interest realized on the overdrawn amount shall be credited to Government account, under distinct sub-head "Interest on over drawals from Fund", under the Head, "0049-Interest Receipt of State Government-800-other Receipts." Besides responsibility should be fixed and action taken against the erring officials certifying excess amount in General Provident Fund subscription etc. However, if the General Provident Fund statement issued by the Accountant General shows excess amount in the credit of the Government employee, the matter may be brought to the notice of Accountant General by concerned department.

(8) When a subscriber is dismissed/removed from the service of Government but has appealed against his dismissal/removal, the balance at his credit in the Fund shall not be paid to him until final orders confirming the decision are passed on his appeal. Interest shall, however, be paid upto the preceding month in which such orders have been passed but the date of quitting the service shall be reckoned, the day on which the final orders are passed.

(9) No interest shall be allowed on the amount recovered on account of the subscriptions to the Fund in excess of the maximum limit prescribed in these rules.

(10) In respect of persons found absconding/disappearing leaving the family, the family may be paid interest upto six months succeeding the month in which a report has been obtained by the family from the Police Department that the employee has not been traced after all efforts made by the Police:

Provided that the family/nominee submits application in the prescribed form for final payment of General Provident Fund amount within one month from the date of receipt of the said report from the Police Department. If the family/nominee does not submit the application within one month or submit incomplete application in any respect then the family/nominee shall not be entitled to the interest for the delayed period (the fraction of a month shall be construed as full month) of submission of application for final payment.

(11) When a subscriber retires on the last day of a month, the period of six months should be counted after excluding the immediately succeeding month, i.e. to say, for instance, when a subscriber's last day of service is the 31st of May, the period of six months should be computed from July to December and not from June to November.

(12) In the case of subscriber, who dies in the forenoon on the last day of a month before retirement, he should be deemed to have quit the service the following day as according to financial rules the pay and allowance can be drawn for the day of the Government employee's death even though he may have died in the forenoon of that day. Therefore, in all such cases the period of six months should be reckoned from the second month following the month in which the subscriber dies:

Provided that the family/nominee submits application in the prescribed form for final payment of General Provident Fund amount within one month from the date of the death of the Government employee. If the family/nominee does not submit the application within one month or submit incomplete application in any respect then the family/nominee shall not be entitled to the interest for the delayed period (the fraction of a month shall be construed as full month) of submission of application for final payment.

(13) In case of quitting service, the final General Provident Fund balance of the subscriber along with interest is to be paid in accordance with the provisions of sub-rule (5) of this rule but the subscriber shall have to apply for final payment in the prescribed form within one month of quitting service. The final payment shall be made to the subscriber within two months from the date of submission of application complete in all respects to the Accountant General and the interest shall be admissible upto the preceding month in which the final payment is made. If the subscriber does not submit the application within one month from the date of quitting service or submit incomplete application then he will not be entitled to the interest for the delayed period (the fraction of month shall be construed as full month) of submission of application for final payment.

(14) In case of retirement on superannuation or other than on superannuation, the final General Provident Fund balance of the subscriber is to be paid in accordance with the provisions of sub-rule (5) of this rule but the subscriber shall have to apply for the final payment in the prescribed form within one month from the date of retirement. The final payment shall be made to the subscriber within two months from the date of submission of application complete in all respects to the Accountant General and the interest shall be admissible upto the preceding month in which the final payment is made. If the subscriber does not submit the application within one month from the date of retirement or submit incomplete application in any respect then he will not be entitled to the interest for the delayed period (the fraction of month shall be construed as full month) of submission of application for final payment. These provisions will also apply to the subscriber retiring on superannuation, who applies for the final payment after the date of retirement.

*General principles
for the grant of
advance.*

13. (1) The Fund is designed solely for the protection of a subscriber's family against his sudden death, or, if he survives until retirement, to provide both him and the family with additional resources in old age. Anything, which interferes with a subscriber's normal accumulations, detracts from these purposes and tends to defeat the true object of the fund. Rule 15 merely permits an advance and wholly exceptional departure from the real purposes of the scheme, and unless it is strictly interpreted, there is a danger that subscribers will come to regard the Fund as an ordinary banking account, the existence of which absolves them from the necessity of providing for the normal incidents of life with the prudence which a private individual would exercise. The inevitable result, if this tendency is countenanced, will be to discourage thrift, and to leave the subscriber with a depleted account at the time when it ought to be most helpful to him or his family. Sanctioning authorities ought, therefore, to have no hesitation in resisting any attempt to use the Fund as a cheap loan account, and in enforcing the altogether exceptional character of rule 15 as a provision to meet urgent needs which would not ordinarily have been anticipated. Every prudent married man, for example, should be prepared to meet a certain demand upon his resources on account of doctor's bills, and it is only when the burden is exceptionally prolonged, or the necessity usually grave and sudden, that he ought to think of making use of the Fund for this object.

(2) For the same reasons, a careful scrutiny should be applied to requests for advance on account of betrothal, marriage or funeral expenses. Even where ceremonial expenditure is by religious custom obligatory, its extent should nevertheless be limited by the resources of the family, and no subscriber should be enabled to enhance such expenditure on the strength of deposits in the fund. An advance from the Fund can legitimately be made for obligatory ceremonial expenditure where no other resources exist but not in order to raise such expenditure to a more pretentious scale.

(3) All sanctioning authorities, while sanctioning advance from Fund shall take into consideration the date of retirement of subscriber and fix the number of instalments, in such a manner that it is possible to recover the entire amount of the advance before six months of actual retirement. No advance shall be sanctioned in the remaining period of six months of retirement.

Drawal from fund.

14. Drawal from Fund may be admissible in the shape of advances, withdrawals and final payment explained as under :—

- (i) **“advance”** means the amount sanctioned to a subscriber as a refundable advance for any of the purposes mentioned in rule 15 and as per conditions mentioned in rule 16 and the amount so advanced to be refunded in monthly instalments as fixed by the sanctioning authority.
- (ii) **“withdrawal”** means the amount sanctioned to a subscriber as non-refundable advance for any of the purposes mentioned in rule 18 and as per conditions mentioned in rule 19 to rule 23. The amount so sanctioned is not required to be refunded by the subscriber.
- (iii) **“final payment”** means the amount finally payable to a subscriber as a final settlement of accumulations standing in the accounts of the subscriber as mentioned in rule 24 i.e. on quitting service, on retirement or on death while in service or disappearance.

Purposes for grant of advance.

15. The Head of Office is appropriate sanctioning authority as shown in Annexure I to sanction the advance for the following purposes :—

- (1) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
- (2) to meet the cost of higher education including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him in the following cases :—
 - (a) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
 - (b) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is not less than two years;
 - (c) for attending coaching courses conducted by Government or by an approved institute for entry into professional courses, administrative or defence services in Government of India or in any State Government.
- (3) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage, the subscriber has to incur once in life in connection with betrothal, marriages, funerals or other ceremonies of the members of his family or any person actually dependent on him. The marriage also includes self marriage of the subscriber; and shall not include any personal religious ceremonies performed occasionally such as Jagran, Akhand paath, Ramayana Paath, Birthday and Marriage Anniversary etc.
- (4) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent on him;
- (5) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;
- (6) to purchase house-hold items such as television, video cassette recorder / video cassette player, washing machines, cooking range, geysers, solar heater, solar energy generation set, invertors and computers etc.

*Conditions for
sanction of advance.*

16. (1) The subscriber may be sanctioned an amount not exceeding six months pay or 50% of credit in the Fund, whichever is less, for the purposes mentioned at clauses (1) to (5) and six months of pay or 50% of credit in the Fund or actual cost of items not exceeding Rs. 20,000/-, whichever is least, for the purpose mentioned at clause (6) in rule 15.

(2) The subscriber shall be sanctioned only one advance at a time, from the Fund, for any of the purposes as given in rule-15.

(3) In case the first advance has not been availed of to the extent of permissible limits, the second advance may be granted after the expiry of a period of six months from the date of withdrawal of first advance by the same sanctioning authority to the extent of difference of amount of admissibility and sanction of first advance.

(4) Further advance shall not be granted unless and until repayment of the last instalment of any previous advance is effected.

(5) All persons on deputation/foreign service from or to State Government Departments shall continue to be governed by the rules of their respective parent department during the period of deputation. Therefore, the respective parent department will be the sanctioning authority for the grant of advance under this rule.

(6) The advance shall not be admissible to the subscriber simultaneously for the same purpose for which he has obtained withdrawal under rule 18.

(7) The subscriber may be granted advance from the Fund even after incurring of expenditure, if he applies for grant of advance within a reasonable time of two months.

(8) The advance may be sanctioned to a Government employee under suspension or on extraordinary leave. The admissibility of amount of advance shall be calculated on the basis of pay, the Government employee was drawing immediately before suspension/extraordinary leave.

(9) The advance for education purpose will be admissible to the subscriber for approved institutions or institutions run by the State Government including Government of India or any other State Government/Union Territory for the approved courses as mentioned in Appendix B.

(10) The advance shall not be sanctioned for the marriage of child/children before their attaining the age of 21 years in the case of son and 18 years in the case of daughter or any other female dependent.

(11) The advance shall not be sanctioned to the subscriber for the purpose mentioned in clause (4) of rule 15, who institutes legal proceedings against the Government in any court of law.

(12) The subscriber, who has submitted the application for final withdrawal and the same has been forwarded to Accountant General and further applies for any advance from the Fund for the purposes mentioned in clauses (1) to (6) of rule 15, shall be sanctioned advance only on receipt of prior concurrence from the Accountant General, who will arrange the same, as soon as possible.

(13) The subscriber shall utilize the advance within one month and also submit the utilization certificate accordingly. In case of non-submission of utilization certificate or misutilization of advance, action shall be taken as per provisions of rule 26.

(14) The advance in the case of Head of Office shall be sanctioned by the next higher authority.

*Recovery of
advance(s).*

17. (1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct, but such number shall not be less than twelve and more than thirty-six. However, the subscriber may opt for recovery of advance in

less than twelve instalments. The sanctioning authority may fix the number of instalments in such a manner that the advance is fully recovered six months prior to the date of retirement of the subscriber.

(2) Recovery shall commence from the month following the month in which the advance was drawn and the same will be credited in the subscriber's account. The subscriber may at his option repay more than one instalment in a month.

(3) Recovery shall not be made except with the subscriber's written consent while he is in receipt of subsistence allowance. However, the same may be recovered in lump sum from his arrears on his reinstatement, if he is paid full pay and allowances.

(4) The recovery shall not be made from the subscriber, if he is on leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay. However, the recoveries can be made with the consent of the subscriber.

(5) If the second advance has been granted to a subscriber under sub-rule (3) of rule 16, the same should be treated separately for the purpose of recovery.

*Purposes for
withdrawal.*

18. Except as otherwise provided, the Head of Department is the appropriate sanctioning authority to sanction the withdrawal for the following purposes :—

- (1) building or acquiring a suitable house or built-up flat for the residence of the subscriber including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by Housing Board, a House Building Society and any Development Agency approved by the State Government or Government of India or any other State Government/Union Territory ;
- (2) acquiring a built-up house/flat for residential purposes from open market through authorized agents;
- (3) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or built-up flat for the residence of the subscriber ;
- (4) purchasing a house-site for building a house thereon for the residence of the subscriber or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken by the subscriber for this purpose;
- (5) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;
- (6) renovating, additions or alterations or upkeep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan from Government ;
- (7) for acquiring or building commercial/industrial establishment or establishing business for settlement of unemployed children ;
- (8) meeting the cost of higher education of any child of the subscriber ;
- (9) meeting the expenditure in connection with the marriage of the subscriber's daughter(s) or any other female relation actually dependent on the subscriber ;
- (10) meeting the expenditure in connection with the marriage of subscriber's son(s);
- (11) meeting the expenditure in connection with self marriage of subscriber;
- (12) to purchase motor vehicle(s) i.e. Motor car and Motor cycle or Scooter or Moped ;
- (13) 90% withdrawal within one year before retirement on superannuation.

NOTE:—The subscriber, who has submitted the application for final withdrawal and the same has been forwarded to Accountant General and further applies for any withdrawal from the Fund for the purposes mentioned in clauses (1) to (13), shall be sanctioned withdrawal only on receipt of prior concurrence from the Accountant General, who will arrange the same, as soon as possible.

*Conditions for
withdrawal for
house building.*

19. (1) The application complete in all respects shall be submitted to the Head of Department keeping in view the conditions prescribed against each withdrawal from the Fund for the purposes mentioned in clauses (1) to (7) of rule 18. However, only one withdrawal shall be allowed for the same purpose during entire service career. The objects as mentioned in clauses (1) to (4) of rule 18 shall be treated as the same purpose for which withdrawal can be allowed upto 90% at the credit of subscriber or actual cost including registration charges, whichever is less, after completion of five years of regular service.

(2) While forwarding the proposal for sanctioning withdrawal from the Fund for any of the purposes mentioned in clauses (1) to (7) of rule 18, it shall be ensured that—

- (i) the subscriber has completed five years of regular service;
- (ii) the advance has been applied for the construction of a house on a plot of land already owned or acquired, the subscriber has undisputed title of ownership individually or jointly with his/her wife/husband to the land on which the house is to be constructed; or if the plot on which the house is to be constructed, is on lease, the terms of lease should be such as may entitle him/her to the grant of house building advance;
- (iii) in case of purchase of built up house from the open market, it should be free from all encumbrances;
- (iv) if the withdrawal has been applied for :—
 - (a) making additions and alterations to a house already owned or acquired; or
 - (b) repaying any outstanding amount of loan expressly taken for the purchase or reconstruction of a house or making additions and alterations to a house already owned or acquired, the subscriber has undisputed title to the land and/or house already owned or acquired, as the case may be, either individually or jointly with his/her wife/husband;
- (v) where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a flat constructed through the Development Authorities, State Housing Board or a House Building Society approved by the State, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any number of instalments subject to the condition that the total amount of the advance does not exceed 90% of the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund at the time of sanction of first instalment;
- (vi) if the house is to be constructed/reconstructed within the municipal limits of a city/town or any urban estate, the subscriber should also be required to produce attested copies of site plan along with estimates duly certified by architect(s) and if house is to be built in rural areas, the revenue authority will certify that the subscriber has undisputed title to the land/property and the same falls within 'Lal Dora' of the village. However, the subscriber will give the estimates along with site-plan duly certified by architect or approved building contractor or civil engineer ;
- (vii) a subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund, shall satisfy the sanctioning authority within a period of six months from the date of withdrawal that the money has been utilized for the purpose for which it was withdrawn and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn shall

forthwith be repaid in lump sum and in default of such refund, it shall be ordered by the sanctioning authority to recover the same from his pay either in lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the sanctioning authority:

Provided that before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-rule, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing within thirty days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of thirty days, the sanctioning authority shall enforce the repayment and the subscriber shall also be debarred for five years as per provision of rule 26 for any type of withdrawal under clauses (1) to (7) of rule 18:

- (viii) for the purpose as given in clause (5) of rule 18, the withdrawal to the extent of 50% at the credit of the subscriber or estimated cost, whichever is less, shall be allowed to the subscriber after five years of the sanction of first withdrawal;
- (ix) for the purpose as given in clause (6) of rule 18, the withdrawal to the extent of 50% at the credit of the subscriber or estimated cost, whichever is less, shall be allowed to the subscriber after five years of service for upkeep of ancestral house in which the subscriber has the specific share and after ten years of first withdrawal under clause (viii) of this sub-rule;
- (x) the subscriber shall also be allowed a fresh withdrawal for the purposes mentioned in clauses (1) to (4) of rule 18 even if he had previously taken withdrawal from General Provident Fund or loan from Government for the said purposes and intends to dispose off/disposed off the said built up house/flat/plot. The admissibility for fresh withdrawal shall be determined on the basis of total amount at the credit of the subscriber including the amount already withdrawn minus 10% of the amount so derived and the amount already taken on an earlier occasion as withdrawal from the current available balance in the General Provident Fund:

Provided that the cost of the plot and the construction of house thereon or flat or built up house to be purchased is more than the sale proceeds of plot/flat/built up house including the withdrawal now required. The cost price also includes registration charges. The purchase on power of attorney shall not be considered for this purpose;

The amount of admissibility for fresh withdrawal shall be calculated as under :—

ILLUSTRATION: Mr. "X" had already taken withdrawal from General Provident Fund amounting to Rs. 2 lac for the purchase of built up house/flat/plot. The present balance at the credit of the subscriber is Rs. 6 lac. Now he has applied for fresh withdrawal amounting to Rs. 3 lac for the purchase of another built up house/flat/plot at a cost of Rs. 6 lac after the disposal of earlier one at a cost of Rs. 3 lac.

(Amount in Rs.)

1. Withdrawal taken earlier	2.00 lac
2. Credit in General Provident Fund (presently)	6.00 lac
3. Total (1+2)	8.00 lac
4. 10% of Col. 3	0.80 lac
5. Withdrawal admissible (Col. 2 minus Col. 4)	5.20 lac

6. Deduct withdrawal already taken (Col. 1) 2.00 lac

7. Withdrawal now admissible (Col. 5 minus Col. 6) 3.20 lac

Mr. "X" can be sanctioned upto Rs. 3,20,000/- for the purposes mentioned in clauses (i) to (iv) of sub-rule (2).

(xi) for the purpose as given in clause (7) of rule 18, the withdrawal to the extent of 50% at the credit of the subscriber shall be allowed for each child after completion of five years of regular service. The withdrawal shall be permissible only if the unemployed children including unmarried daughter have attained the age of eighteen years;

(xii) a subscriber who has been permitted under clauses (1) to (7) of rule 18 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Governor), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the competent authority:

Provided that such permission shall not be necessary for –

(a) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years; or

(b) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalized Banks, the Life Insurance Corporations or any other Corporation owned or controlled by the State Government including Government of India or any other State Government/Union Territory which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house or purchase of plot;

(xiii) the total withdrawal from the Fund including house-building advance taken from the Government shall not exceed Rs. 18 lac or as decided by the State Government from time to time for house building advance;

(xiv) the withdrawal in the case of Head of Department shall be sanctioned by the next higher authority.

*Conditions for
withdrawal for
higher education.*

20. The withdrawal under clause (8) of rule 18 shall be permitted to the extent of 75% of the amount at the credit of the subscriber or the actual amount required as per certificate from the concerned Institution, whichever is less, for each child for initial admission and 50% of the amount at the credit of the subscriber or actual amount required by the institution, whichever is less, for each child for subsequent academic years subject to the following conditions :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and for medical, engineering and other technical or specialised courses in India beyond the High School stage; provided that the course of study is not less than two years duration;

(ii) the withdrawal will be admissible in respect of courses approved by Government from time to time. The detail of approved courses is given in **Appendix B**;

(iii) in case where payments are to be made on semester basis for subsequent years, the subscriber shall be allowed withdrawal twice in a year not exceeding of 25% of the amount standing at his credit or the estimated expenditure involved as certified by the concerned institution, whichever is less;

- (iv) the subscriber shall utilize the withdrawal within one month and also submit the utilization certificate accordingly;
- (v) any amount withdrawn from the Fund, which is found to be in excess of that actually required by the subscriber for the purpose, shall be repaid forthwith into the Fund;
- (vi) the withdrawal in the case of Head of Department shall be sanctioned by the next higher authority.

Conditions for withdrawal for marriage.

21. The withdrawal under clauses (9), (10) and (11) of rule 18 shall be permitted to the extent of 75% of the amount at the credit of the subscriber for the marriage of each daughter or any other female relation actually dependent on the subscriber: for each son of the subscriber and for self marriage of the subscriber subject to the following conditions :—

- (i) the age of the daughter or any other female dependent should not be less than 18 years and 21 years in the case of son. Necessary proof of age will be required to be given by the subscriber while applying advance for marriage of daughter/female dependent and son. The age of subscriber shall not be less than 18 years in the case of female and 21 years in the case of male for the purpose of self marriage;
- (ii) if two or more marriages are to be celebrated simultaneously, the amount admissible in respect of each marriage shall be determined as if the advances are sanctioned separately one after the other;
- (iii) in respect of the same marriage a subscriber may either withdraw the money under this rule or under rule 15;
- (iv) a subscriber who draws an advance under rule 15 may convert, at his discretion by written request addressed to the Head of office, the outstanding balance into a final withdrawal from the competent authority on his satisfying the conditions laid down in this rule;
- (v) the withdrawal may be allowed to a subscriber not earlier than three months preceding the month in which the marriage actually takes place;
- (vi) the subscriber shall furnish a certificate to the sanctioning authority within a period of one month from the date of marriage, or if he is on leave, within one month on return from leave that the money withdrawn had actually been utilized for the purpose for which it was intended. If the subscriber fails to furnish the requisite certificate or if the amount withdrawn is utilized for a purpose other than that for which sanction was given, the entire amount shall be repaid forthwith into the Fund in lump sum by the subscriber, and, if he fails to do so, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his pay either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by such authority;
- (vii) the betrothal ceremony and marriage ceremony should be treated separately. The subscriber shall be permitted withdrawal from the Fund for the purpose of marriage though he had availed of advance under rule 15 for betrothal ceremony;
- (viii) the withdrawal in the case of Head of Department shall be sanctioned by the next higher authority.

Conditions for withdrawal for purchase of motor vehicle(s).

22. The withdrawal for the purchase of vehicle i.e. a motor car and motor cycle or scooter or moped, under clause (12) of rule 18 shall be allowed to the extent of 50% of the amount at the credit of the subscriber or the cost of the vehicle, whichever is less, subject to the following conditions: -

- (i) the pay of a subscriber should be Rs. 9750/- per mensem or more as decided by the Government from time to time in the case of withdrawal for the purchase of motor

car. There is no condition of minimum pay for withdrawal for purchase of motorcycle or scooter or moped;

- (ii) the subscriber should have minimum 5 years regular service at his credit;
- (iii) the subscriber may be sanctioned withdrawal for the purchase of motor car and motorcycle or scooter or moped only once in service career;
- (iv) the subscriber may be sanctioned withdrawal from the Fund to the extent of difference of the cost of vehicle and the amount of loan taken from the Government for the same purpose;
- (v) the subscriber may also be allowed withdrawal from the Fund for repaying any loan expressly taken from the Government or Bank for the purposes mentioned in clause (12) of rule 18;
- (vi) the withdrawal in the case of Head of Department shall be sanctioned by the next higher authority.

Conditions for 90% withdrawal before retirement on superannuation.

23. (1) The withdrawal under clause (13) of rule 18 shall be allowed to the subscriber within one year before the date of retirement on superannuation to the extent of 90% of the amount at the credit of the subscriber in the Fund without assigning any reason or purpose.

(2) The withdrawal in the case of Head of Department shall be sanctioned by the next higher authority.

Final payment of accumulation.

24. The accumulation of the subscriber in the Fund shall become finally payable in the event of his quitting service; on his retirement; on his death while in service, as per conditions given as under :—

(1) ON QUITTING SERVICE —

- (i) When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him.
- (ii) In case a subscriber, who has been dismissed/removed from the service and is subsequently reinstated in the service shall repay any amount paid to him from the Fund along with interest thereon at the rate prescribed in rule 12. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.
- (iii) When a subscriber quits the service from one department for taking appointment in another department under Haryana Government, it shall not be treated as quitting of the service.
- (iv) The retrenchment of the subscriber shall amount to quitting of service.

(2) ON RETIREMENT —

When a subscriber has been retired on superannuation or otherwise or permitted to retire, the amount standing to the credit of a subscriber shall become payable. The Accountant General shall authorize payment of that portion of the amount standing to the credit of a subscriber, in regard to which there is no dispute or doubt, before fifteen days of the retirement of the employee on superannuation and within three months in other cases, the balance be released as soon as possible.

(3) ON DEATH OR DISAPPEARANCE —

- (i) When a subscriber dies while in service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to the members of his family/nominee(s).

- (ii) When a subscriber disappears/absconds and his whereabouts are not known, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to the members of his/her family/nominee(s), after receipt of report of police that the employee is not traceable.

(4) WHEN THE SUBSCRIBER LEAVES A FAMILY—

- (i) If a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 7 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.
- (ii) If no such nomination in favour of a member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall divide between them in equal parts only the share which that son would have received, if he had survived the subscriber.

(5) WHEN THE SUBSCRIBER LEAVES NO FAMILY—

When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of rule 7 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination. In case if a subscriber dies having no family member and valid nomination then the payment shall be made to the claimant(s) on production of succession certificate from the court of law.

(6) STATUS OF POSTHUMOUS CHILD—

Subscriber's posthumous child is a member of his family at the time of his death and if born alive, should be treated in the same way as surviving child born before the subscriber's death. If the existence of an unborn posthumous child is brought to the notice of the Disbursing Officer, the amount which will be due to the child in the event of its being born alive should be retained and the balance be distributed in the normal way. If the child is born alive, payment of the amount retained should be made as in the case of minor child; but if no child is born, the amount retained should be distributed among the family in accordance with the ordinary rules.

(7) WHEN A SUBSCRIBER DISAPPEARS/ABSCONDS AND HIS WHEREABOUTS ARE NOT KNOWN—

When any employee disappears leaving his family, the family can be paid in the first instance the amount of General Provident Fund having regard to the nomination by the employee after observing the following formalities :—

- (i) the family must lodge a report with the concerned police station and obtain a report that the employee has not been traced after all efforts made by the police;
- (ii) an Indemnity bond should be taken from the nominee/dependents of the employee that all payments will be adjusted against the payments due to the employee in case he appears on the scene and makes any claim;
- (iii) the family shall not be allowed any payment which is facing trial for the murder of the Government employee till the court's decision.

Manner of payment. 25. The payment from the Fund can be drawn by taking advance under rule 15, withdrawals under rule 18 and final payment under rule 24 in the following manner: -

(1) **ADVANCE—**

Advance from the Fund can be obtained for the purposes mentioned in rule 15 subject to the conditions prescribed in rule 16 in Form No. **P.F.-3 (Annexure C)**. The competent authority shall issue a sanction in the proforma No. **P.F.-7 (Annexure G)** for drawal of the advance as per admissibility to the subscriber, a copy of which shall also be endorsed to the Accountant General, Haryana. The competent authority shall categorically mention the number of instalments in which the advance is to be recovered. The amount from the Fund shall be drawn from the Treasury/Sub-Treasury as per their jurisdiction and the same will be disbursed to the subscriber. It shall be the responsibility of the Head of Office to recover the advanced amount as per sanction of the advance. The Accountant General, Haryana will deduct the withdrawal from the Fund as per procedure followed in his office.

(2) **WITHDRAWAL—**

Withdrawal from the Fund can be obtained for the purposes mentioned in rule 18 subject to the conditions prescribed in rules 19, 20, 21, 22 and 23 in Form No. **P.F.-4 (Annexure D)**. The subscriber shall apply to the Head of Office for any of the intended withdrawals, in the prescribed Form in duplicate. The Head of Office after scrutinizing the application shall forward one copy of the same along with the supporting documents to the Head of Department, if he has not been delegated the powers of Head of the Department as mentioned in Annexure I to these rules. The Head of Department shall issue sanction in Form No. **P.F.-8 (Annexure H)** for the withdrawal from the Fund after satisfying the conditions and admissibility of the withdrawal, a copy of which shall also be endorsed to the concerned Head of Office and Accountant General, Haryana. The amount from the Fund shall be drawn by the Head of Office from the Treasury/Sub-Treasury as per their jurisdiction and the same will be disbursed to the subscriber. In case the withdrawal pertains to a subscriber working in the office of Head of Department, the withdrawal shall be made by that office. The Accountant General, Haryana shall keep a proper note of the sanction for the withdrawal from the Fund as per procedure followed in his office.

(3) **FINAL PAYMENT—**

(i) The Head of Office after obtaining the application Form for final payment in application Form No. **P.F.-5 (Annexure E)** in duplicate from the subscriber, shall forward the same to the Accountant General, Haryana six months in advance from the date of his retirement. The Head of Office shall also indicate the recovery to be effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawal, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accountant General, Haryana. The Accountant General shall after verification with the ledger account, take necessary steps to issue the authority to the Head of Office or Treasury as per option of the subscriber, for the amount payable to him at least fifteen days before the date of superannuation, payable on the next working day of superannuation. The Treasury Officer shall allow the payment only after receipt of a copy of authorization issued by the Accountant General meant for Treasury Office.

(ii) In the case of death of the subscriber during service, the Head of Office shall get the application in Form No. **P.F.-6 (Annexure F)** for final payment of accumulation in Fund from the family members/nominee(s) of the subscriber for submission to the Accountant General immediately for initiation of action. The payment in the case of minor(s) shall be made through legal guardian, if the minor has no natural guardian alive. The other pre-requisites/formalities as

mentioned in clause (i) of this sub-rule shall be completed and authorization be issued accordingly.

- (iii) If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid is a lunatic for whose estate a Manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912), the payment shall be made to such Manager and not to the lunatic :

Provided that where no Manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912), to the person having charge of such lunatic and the Accountant General shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid to him for maintenance.

- (iv) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive the payment in India.

*Misutilization of
advance/
withdrawal*

26. Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt the money drawn as an advance or withdrawal from the Fund under rule 15 or 18 has been utilized for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within thirty days of the receipt of such communication by him whether the advance or withdrawal has been utilized for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of thirty days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith, or, in default, order the amount to be recovered by deduction in lump sum from the pay of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's pay, recoveries shall be made in monthly instalments, as may be determined by sanctioning authority not exceeding $\frac{1}{3}^{\text{rd}}$ of his pay. The subscriber shall also be debarred, for a period of two years for taking any advance, and, for a period of five years for withdrawal from the Fund.

*Maintenance of
General Provident
Fund accounts in
the office of
Accountant
General.*

27. (1) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in the books of Government to an account named "The General Provident Fund". Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these rules, shall be transferred to "Deposits" at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

(2) When paying a subscription in India, either by deduction from pay or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Accountant General. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accountant General.

(3) The Accountant General shall, if required by a subscriber, once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

*Issuance of annual
General Provident
Fund statement.*

28. (1) As soon as possible, after the 31st March of each year, the Accountant General shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date.

The Accountant General shall attach to the statement of accounts the date of birth of the employee concerned, if available in his office and an enquiry whether the subscriber: —

- (i) desires to make any alteration in any nomination made under rule 7; or
- (ii) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the first proviso to sub-rule (1) of rule 7.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Accountant General within three months from the date of the receipt of the statement.

Delegation.

29. The Heads of Departments may re-delegate the powers delegated to them for sanctioning advances/withdrawals under these rules, on their own responsibility and subject to such restrictions, as they may like to impose, to any officer working at their headquarter /district / any other office(s).

Relaxation of rules.

30. When it is felt that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, the Finance Department, may notwithstanding anything contained in these rules, deal with the cases of such subscriber in such a manner as may appear just and equitable.

Interpretation.

31. If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Finance Department, Haryana whose decision thereon shall be final.

Repeal and saving.

32. The Punjab General Provident Fund Rules 1936, are hereby repealed. Anything done or any action taken under rules so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

ANNEXURE A
FORM NO. PF-1

(see rule 6)

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT NUMBER

(To be submitted in triplicate)

Name of applicant & Father/Husband name	Date of birth/ Date of joining regular service	Designation and Official address	Nature of post held (i) On probation (ii) Temporary (iii) Permanent	Existing Scale and Basic pay per mensem	Rate of subscription per mensem	Whether the applicant has a family or not ?	Account number to be allotted by Accountant General
1	2	3	4	5	6	7	8

Place _____

Date _____ 20

Signature of Applicant

(Signature)
Head of Office

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, HARYANA, CHANDIGARH.

No. _____

Dated: _____

Returned to _____ with General Provident Fund Account number allotted as mentioned in Column 8. This number should be quoted for all future correspondence connected therewith. The nomination form duly accepted is also returned for office record.

(Signature)
Accountant General, Haryana.

ANNEXURE B
FORM NO. PF-2
(see rule 7)
FORM OF NOMINATION

Account No. _____

I, _____ hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/non-member(s) of my family as defined in rule 7 of the Haryana General Provident Fund Rules to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid:

Name and address of the nominee(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person(s), if any, to whom the right of nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in rule 3, indicate the reasons
1	2	3	4	5	6	7

Place-----

Dated this _____ day of _____, 20____

Signature of the subscriber

Name in Block Letters _____

Designation_____

Signature of two witnesses:

Name and Address

Signature

1.

2.

NOTE:

(1) The form of nomination shall be filled in triplicate. Two copies will be sent to Accountant General, Haryana, who will return one copy duly accepted and signed to the Head of Office for office record.

(2) In column 4, if only one person is nominated, the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee to cover the whole amount of the Fund shall be specified.

For use by the Head of Office

Nomination received from Sh./Ms. _____

Designation _____ on dated _____ for onward submission to the Accountant General, Haryana.

Dated _____

(Signature)

Head of Office

For use by A.G., Haryana

Nomination made by Sh./Ms. _____ Designation _____,

O/o _____ is hereby accepted and returned to _____ (Head of Office) for office record.

(Signature)

**ACCOUNTANT GENERAL,
HARYANA.**

ANNEXURE C
FORM NO. PF -3

(see rules 15 to 17)

APPLICATION FOR ADVANCE FROM GENERAL PROVIDENT FUND

Department/Office _____

1. Name of the Subscriber:
2. Designation:
3. Account number (complete):
4. Existing Scale of pay:
5. Basic pay including Dearness Pay, Personal Pay,
Special Pay, if any, in the existing scale : Rs.
6. Date of joining service :
7. Date of Superannuation :
8. Balance at credit of the subscriber on
the date of the application as below :—
 - (i) Closing balance as per latest General Provident Fund statement
for the year _____ (copy enclosed) Rs.
 - (ii) Add regular monthly subscription plus lumpsum
subscription, if any, after the date of General Provident Fund
statement mentioned at (i) above: Rs.
 - (iii) Add refunds of advance(s) after the date of
statement mentioned at (i) above: Rs.
 - (iv) Total (i) + (ii) + and (iii): Rs.
 - (v) Less amount of advance(s) and Withdrawal(s)
taken after the date of General Provident Fund statement mentioned
at (i) above: Rs.
 - (vi) Net balance at credit: Rs.
9. Amount of advance required: Rs. _____
10. Purpose for which the advance is required:
11. Date of ceremony:
12. Rule under which the advance is admissible :
13. Full details of advance taken previously :

Serial Number	Purpose of advance	Date of Drawal	Amount	Name of the office from where payment received
1.				
2.				
3.				

14. Whether full recovery has been made of the previous advance:
15. If the reply to item 14 above is negative then give the following information: -

Serial Number	Purpose of advance	Amount of advance	Month of Drawal	No. of Instalments for recovery	Advance recovered	Balance of advance
1.						
2.						

1. Certified that I have utilized the advance(s) taken from my General Provident Fund earlier for the purpose for which the advance(s) was/were sanctioned and I have already submitted the utilization certificate to the Head of Office as required under rule 16.
2. Certified that the person for whose ceremony/education etc. the advance has been applied for, is fully and solely dependent upon me.
3. Certified that the information given in this application is true and correct and nothing has been concealed or mis-stated therein. I am aware that in case of any concealment or mis-statement of facts, I will be debarred from taking any advance(s) from my General Provident Fund Account for a period of two years.

Signature of the Applicant

Name_____

Designation_____

Branch_____

Dated_____

ANNEXURE D

FORM NO. PF- 4

(see rules 18 to 23)

APPLICATION FOR WITHDRAWAL FROM GENERAL PROVIDENT FUND

PART - I

Department_____

Head of Office_____

1. Name of the Subscriber:
2. Designation:
3. Account number (complete) :
4. Existing Scale of pay :
5. Basic pay including Dearness Pay, Personal Pay.
Special Pay, if any, in the existing scale : Rs.
6. Date of joining service :
7. Date of superannuation :
8. Balance at credit of the subscriber on
the date of the application as below :—
 - (i) Closing balance as per latest General Provident Fund statement
for the year_____ (copy enclosed) Rs.
 - (ii) Add regular monthly subscription plus lump sum
subscription, if any, after the date of General Provident Fund
statement mentioned at (i) above : Rs.
 - (iii) Add refunds of advance(s) after the date of
statement mentioned at (i) above : Rs.
 - (iv) Total (i) + (ii) + and (iii) : Rs.
 - (v) Less amount of advance(s) and withdrawal(s)
taken after the date of General Provident Fund statement
mentioned at (i) above: Rs.
 - (vi) Net balance at credit : Rs.
9. Amount of withdrawal required: Rs. _____
10. Purpose for which withdrawal is required:
11. Rule under which withdrawal is admissible:

12. Whether any withdrawal was taken for the same purpose earlier, if so, indicate the Amount and the date :—

Serial Number	Date of drawal	Sanction Number and Date	Amount	Name of office from where payment was received
1.				
2.				
3.				

NOTE : All withdrawals taken for purchase of plot, purchase of house, construction, addition and alteration, repair of house and repayment of loans taken for these purposes should be treated as same purpose. All withdrawals taken for purchase of motor cycle, scooter, and moped should be treated as same purpose and withdrawal for motor car can be obtained separately subject to conditions mentioned in rule 22.

13. Additional information be given in the relevant (Part ____ attached)
 part i.e. acquisition of Plot/flat in part-II/detail of marriage ceremony in Part-III/details of higher education in Part-IV/details of motor vehicle(s) in Part-V :

1. Certified that I have utilized the withdrawal(s) taken from my General Provident Fund earlier for the purpose for which the withdrawal(s) was/were sanctioned. I have already submitted the utilization certificate to the Head of Office as required under rules 19/20/21/22.
2. Certified that the person for whose ceremony/education etc. the advance has been applied for, is fully and solely dependent upon me.
3. Certified that the information given in this application is true and correct and nothing has been concealed or mis-stated therein. I am aware that in case of any concealment or mis-statement of facts, I will be debarred from taking any withdrawal(s) from my General Provident Fund Account for a period of five years.

(Signature of applicant)

Designation : _____

Dated: _____

Office: _____

(Examination/Verification by the Office)

1. This is to certify that the office has checked and verified the details submitted by the subscriber in this application. All the details furnished by the subscriber are verified to be correct.
2. The subscriber is entitled to the withdrawal being applied for under the rule 18; or the subscriber is not entitled to the withdrawal applied for and has requested for relaxation in rules on the following counts:
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)

(Signature of the Head of office with Seal)

ANNEXURE D
FORM NO. PF-4
PART - II

If the application is for seeking withdrawal for acquisition of a plot and construction of house thereon/acquisition of flat or house/construction of house, the following additional information be provided:

Serial Number	Subject	Particulars
1.	Purpose:	(i) Acquisition of a plot for house (ii) Acquisition of a built up flat (iii) Acquisition of a built up house (iv) Construction of House (v) Re-payment of loan taken from a financial institution expressly for acquiring a dwelling unit (vi) Repair/Renovation of a house
2.	Source of acquisition (please give details of the agency e.g. Haryana Urban Development Authority/Co-op. Housing Society/ Open market or any other source	
3.	Person in whose name the plot/ house/flat (Clear title). Enclose proof of ownership/copy of allotment letter	
4.	Amount of House Building Advance taken from the Government under its Scheme, if any.	
5.	Whether withdrawal from General Provident Fund taken earlier for this purpose?	Yes / No
6.	If the answer to above is 'yes' , please give the details: (i) withdrawal taken for the same unit (ii) withdrawal taken for some other unit(s) (iii) whether the previous unit has been disposed off and the advance taken for the same deposited back in the account	(i) (ii) (iii)
7.	If the withdrawal is being applied for a plot in the name of spouse, please indicate who is the first nominee to receive the General Provident Fund accumulations.	

(Signature of applicant)

Designation _____

Office _____

ANNEXURE D
FORM NO. PF-4

PART - III

(withdrawal for marriage ceremony)

Serial Number	Subject	Particulars
1.	Marriage of Self/Son/Daughter/ dependent Sister	
2.	Name of the dependent for whose marriage advance is applied	
3.	Date of birth of the dependent	
4.	Has any withdrawal been taken earlier for marriage? If yes, the amount of withdrawal taken with detail:	
5.	Amount of withdrawal being applied for	
6.	Date of marriage ceremony	

(Signature of applicant)

Designation _____

Office _____

ANNEXURE D
FORM NO. PF-4
PART - IV
(withdrawal for higher education of children)

Serial Number	Subject	Particulars
1.	Withdrawal is being applied for higher education of:	Son/Daughter
2.	Name of the Child	
3.	Details of the Course of Study	
4.	Name of the Institute of Study	
5.	Evidence of Admission	
6.	Evidence of fees to be supported to justify the advance	
7.	Details of withdrawals taken earlier for the purpose:	(i) (ii) (iii)

(Signature of applicant)

Designation _____

Office _____

ANNEXURE D,
FORM NO. PF-4
PART-V

(withdrawal for purchase of motor vehicle(s))

Serial Number	Subject	Particulars
1.	Withdrawal is being applied for motor vehicle i.e. motor car, motor cycle, scooter or moped	
2.	Particulars of withdrawal or loan taken previously, if any.	Amount Date of drawal withdrawal or Loan
3.	Cost of vehicle (proforma invoice to be attached)	
4.	Amount required for purchase of vehicle	

(Signature of applicant)

Designation _____

Office _____

ANNEXURE E
FORM NO. PF - 5
(see rule 24)

**APPLICATION FOR FINAL PAYMENT/TRANSFER TO CORPORATE BODIES/OTHER
GOVERNMENTS**

To

The Accountant General,
Haryana, Chandigarh.

(Through the Head of office)

Sir,

I am to retire/have retired/have been discharged/dismissed/have been permanently transferred to _____/have resigned finally from Government service/have resigned service under _____ Government to take up appointment with _____ and my resignation has been accepted with effect from _____ forenoon/afternoon. I joined service with _____ on _____ forenoon/afternoon.

2. My Fund Account No. is _____

3. I desire to receive payment through my office _____ or through the _____ Treasury / Sub-Treasury. Particulars of my personal marks of identification, left hand thumb and finger impressions (in the case of illiterate subscribers) and specimen signature (in the case of literate subscribers) in duplicate, duly attested by a Gazetted Officer of the Government, are enclosed.

4. I request that the entire amount at my credit with interest due under the rules may be paid to me/transferred to _____

Yours faithfully,

Date:-

(Signature)

(To be specified)

Name:

Address:

(FOR USE BY HEAD OF OFFICE)

Forwarded to the Accountant-General, Haryana for necessary action.

2. Sh./Ms _____ has finally retired/has been discharged/dismissed/has been permanently transferred to _____/has resigned finally from Government service/has resigned service under _____ Government to take up appointment with _____ and his/her resignation has been accepted with effect from _____ forenoon / afternoon. He/she joined service with _____ on _____ forenoon /afternoon.

3. The last fund deduction was made from his/her pay in the Office Bill No _____ dated _____ for Rs _____ (Rupees _____). Treasury Voucher No _____ of _____ Treasury, the amount of deduction being Rs.....and recovery on account of refund of advance Rs.....

4. Certified that he/she had taken the following advances in respect of which _____ instalment of Rs. _____ are yet to be recovered and credited to the Fund Account. The details of advance(s) / withdrawal(s) granted to him/her during the twelve months immediately preceding the date of his/her quitting service/proceeding on leave preparatory to retirement or thereafter are also indicated below :—

Serial Number	Amount of Advances/Withdrawals	Place of encashment	Voucher Number and Date
1.			
2.			
3.			
4.			

5. Certified that he/she has not resigned from Government service with prior permission of the State Government to take up an appointment in Central Government or under State Government or under a body corporate owned or controlled by the State.

6. Certified that no advance/withdrawal will be sanctioned to the subscriber henceforth without the concurrence of Accountant General, Haryana.

7. Certified that the subscriber/claimant submitted the application on _____
Date _____ Month _____ Year.

(Signature of Head of Office)

ANNEXURE F

FORM No. PF - 6

(see rule 24)

APPLICATION FOR FINAL PAYMENT TO THE NOMINEES OR ANY OTHER CLAIMANTS WHERE NO NOMINATION SUBSISTS

To

The Accountant General,
Haryana, Chandigarh.
(Through the Head of office)

Sir,

It is requested that arrangements may kindly be made for the payment of the accumulations in the General Provident Fund Account of Sh./Ms. The necessary particulars required in this connection are given below: -

1. Name of the Government employee :
2. Date of birth :
3. Post held by the Government employee :
4. Date of death :
5. Proof of death in the form of a death certificate :
(issued by the municipal authorities, etc.)
6. General Provident Fund Account Number of subscriber (Complete) :
7. Amount at the credit of the subscriber at
the time of his death, if known :
8. Details of the nominees alive on the date of
death of the subscriber, if a nomination subsists:

Name of the Nominee	Relationship with the subscriber	Share of the nominee	Remarks :
1			
2			
3			

9. In case the nomination is in favour of person other than a member of the family, the details of the family, if the subscriber subsequently acquired a family:

Name of the Nominee	Relationship with the subscriber	Age on the date of death	Remarks
1			
2			
3			

10. In case no nomination subsists, the details of the surviving members of the family on the date of death of the subscriber. In the case of a daughter or of a daughter of a deceased son of the subscriber married before the death of the subscriber, it should

he stated against her name whether her husband was alive on the date of death of the subscriber:

Name	Relationship with the subscriber	Age on the date of death	Remarks
1			
2			
3			

11. Name of the Natural/legal guardian:
(in case the amount is due to a minor child)

12. If the subscriber has left no family and no nomination subsists, the names of persons to whom the Provident Fund money is payable (to be supported by letter of Probate or succession certificate etc.):

Name	Relationship with the subscriber	Address	Remarks
1			
2			
3			

13. The payment is desired through the office of _____/through the _____ Treasury/ Sub-Treasury. In this connection the following documents duly attested by a Gazetted Officer/ Magistrate are attached: -

- (i) Personal marks of identification
- (ii) Left/Right Hand thumb or finger impressions (in the case of illiterate claimants)
- (iii) Specimen signatures in duplicate (in the Case of literate claimants):

Yours faithfully,

Place _____

(Signature of claimant)

Dated _____

(Full Name and Address)

(FOR USE OF HEAD OF OFFICE)

Forwarded to the Accountant General, Haryana for necessary action. The particulars furnished above have been duly verified.

2. The General Provident Fund Account number of Sh./Ms. _____ is _____

3. He/she died on _____ A death certificate issued by the Municipal authorities has been produced (copy enclosed).

4. The last General Provident Fund deduction was made from his/her pay for the month of _____ drawn vide Treasury Voucher No. _____ dated _____ in this Office Bill No. _____ dated _____ for Rs. _____ Rupees _____ Treasury Challan No. _____ dated _____ Treasury, the amount of deduction being Rs. _____ and recovery amount being Rs. _____.

5. Certified that he/she had taken the following advances in respect of which _____ instalment of Rs. _____ are yet to be recovered and credited to the Fund Account. The details of the withdrawals granted to him/her during the twelve months immediately preceding the date of his/her death are also indicated below :—

Serial Number	Amount of Advances/Withdrawals	Place of encashment	Voucher Number and Date
1.			
2.			
3.			
4.			

6. Certified that the claimant submitted the application on _____ date _____ month _____ year.

(Signature of the Head of Office)

ANNEXURE G

FORM NO. PF- 7

SANCTION ORDER FOR ADVANCE

(see rule 15)

Sanction is hereby accorded under rule _____ of Haryana General Provident Fund Rules for the grant of an advance of Rs. _____ (Rupees _____ only) to Shri/Ms. _____ from his/her General Provident Fund Account Number _____ to enable him/her to defray charges on account of _____.

2. The advance will be recovered in _____ monthly instalments of Rs. _____ each, commencing from the salary of next month succeeding the drawal month _____.

3. The balance at the credit of Shri/Ms. _____ as on the date of sanction is detailed below :—

- | | |
|--|-----|
| (i) Balance as per General Provident Fund Statement for the year _____ | Rs. |
| (ii) Subsequent deposits | Rs. |
| (iii) Total of column (i) and (ii) | Rs. |
| (iv) Subsequent advance/withdrawals, if any | Rs. |
| (v) Balance as on date of sanction column {(iii) minus (iv)} | Rs. |

(Name)

Dated

Head of Office

Endst. No.

Dated

Copy forwarded to: —

1. The Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana, Chandigarh for information and to make a note in the ledger account of the subscriber.

2. Shri _____ His attention is drawn to the provisions of the rule _____ of Fund rules according to which a subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund should satisfy the sanctioning authority that the money has been utilized for the purpose for which it was withdrawn. A certificate to the effect that the amount withdrawn has been utilized for the purpose for which it was sanctioned be furnished within one month from the date of drawal.

3. Treasury Officer, _____

(Signature)

ANNEXURE H
FORM NO. PF- 8
SANCTION ORDER FOR WITHDRAWAL
(see rule 18)

Sanction is hereby accorded under rule _____ of the Haryana General Provident Fund Rules to Sh/Ms. _____ (here enter the name and designation) for withdrawal of an amount of Rs _____ (Rupees _____ only) from his / her General Provident Fund Account No. _____ to enable him/her to meet expenditure in connection with _____.

2. The amount of withdrawal is within the limits as prescribed in the conditions meant for this withdrawal.
3. The balance at the credit of Shri/Ms. _____ as on the date of sanction is detailed below:

- | | |
|--|-----|
| (i) Balance as per General Provident Fund Statement for the year _____ | Rs. |
| (ii) Subsequent deposits | Rs. |
| (iii) Total of columns (i) and (ii) | Rs. |
| (iv) Subsequent advances/withdrawals, if any | Rs. |
| (v) Balance as on date of sanction columns {(iii) minus (iv)} | Rs. |

Dated _____

(Name)
 Head of Department

Endst. No. _____

Dated _____

Copy forwarded to:—

1. The Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana, Chandigarh for information and to make a note in the ledger account of the subscriber.

2. Shri _____ His attention is drawn to the provisions of the rule _____ of General Provident Fund rules according to which a subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund should satisfy the sanctioning authority that the money has been utilized for the purpose for which it was withdrawn. A certificate to the effect that the amount withdrawn has been utilized for the purpose for which it was sanctioned be furnished within _____ months from the date of drawal.

3. Head of office _____

4. Treasury Officer, _____

(Signature of Head of Department)

Annexure I*[see rules 2 (iv), 15 and 18]***List of authorities competent to sanction Advance/Withdrawal**

Serial Number	Rule	Nature of power	To whom delegated	Extent of power
01.	15(1) 15(2) 15(3) 15(4) 15(5)	To sanction advance for:- illness, confinement or disability higher education obligatory expenses legal proceedings in court of law defence in departmental inquiry	Head of Office	Six months pay or 50% of credit in General Provident Fund account whichever is less and further subject to the conditions laid in rule 16.
02.	15(6)	To sanction advance for:- purchase of house hold item(s)	Head of Office	Six months pay or 50% of credit in General Provident Fund account or actual cost of items whichever is least and further subject to the conditions laid in rule 16.
03.	18(1) 18(2) 18(3) 18(4)	To sanction withdrawal for :- Building or acquisition of house/flat/plot from Government agency. acquisition of house/flat/plot from open market repaying of loan for house/ flat purchase of house-site	Head of Department	90% of credit in General Provident Fund account or the actual cost whichever is less and further subject to the conditions laid in rule 19.
04.	18(5) 18(6) 18(7)	To sanction withdrawal for :- additions or alternations in house/flat upkeep of ancestral house acquiring commercial/ industrial establishment or establishing business for settlement of unemployed children.	Head of Department	50% of credit in General Provident Fund account or the actual cost whichever is less and further subject to the conditions laid in rule 19.

05.	18(8)	To sanction withdrawal for :- higher education of child	Head of Department	<p>(i) For initial admission –</p> <p>Upto 75% of credit in General Provident Fund account or the actual amount required by the institution whichever is less for each child and further subject to the conditions laid in rule 20.</p> <p>(ii) For annual payment —</p> <p>50% of credit in General Provident Fund account or the actual amount required by the institution whichever is less for each child and further subject to the conditions laid in rule 20 .</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>25% of credit in General Provident Fund account or the actual amount required by the institution whichever is less, twice in a year for each child and further subject to the conditions laid in rule 20.</p>
06.	18(9) 18(10) 18(11)	To sanction withdrawal for :- daughter's marriage or female relative's marriage son's marriage Self marriage	Head of Department	75% of credit in General Provident Fund account and further subject to the conditions laid in rule 21.
07.	18(12)	To sanction withdrawal for :- purchase of motor vehicle(s)	Head of Department	50% of credit in General Provident Fund account or the actual cost of vehicle whichever is less and further subject to the conditions laid in rule 22.
08.	18(13)	To sanction 90% withdrawal before retirement on superannuation	Head of Department	90% of credit in General Provident Fund account and further subject to the condition laid in rule 23.

Note 1 : The Head of Departments may re-delegate any of the powers delegated to them in the above table, in writing, on their sole responsibility and further subject to such restrictions and conditions as they may like to impose, to any officer working under them at their headquarter/ District / any other office(s). The copies of re-delegation shall be endorsed to the concerned Administrative Department and Accountant General, Haryana,

Note 2 : The following officers shall exercise the powers of Heads of Departments so far as these rules are concerned in respect of officers/officials working under them and subordinate establishment under their control :-

- (i) Commissioner(s) of Division(s).
- (ii) District and Sessions Judge(s).
- (iii) Inspector General / Deputy Inspector General of Police (Range/Railway).
- (iv) Conservator of Forest(s).

- (v) Controller of Printing and Stationery
- (vi) Superintending Engineer(s) of Public Works Department(s).
- (vii) District Education Officers / Sub Divisional Education Officers
- (viii) Principal(s) of Government Art and Professional Colleges.
- (ix) Sub-Divisional Officers (Civil) in the Sub-Division of the Civil Department and City Magistrate at Headquarters of the District.

Note 3 : The advance/withdrawal for the Head of Office/Head of Department shall be sanctioned by the Head of Department and Administrative Department respectively.

Note 4: The sanctioning authorities shall send a consolidated list of advance/withdrawals sanctioned by them, to the Head of the Department quarterly commencing from April of each financial year, mentioning therein complete details of advance/withdrawal such as name of the subscriber, General Provident Fund account number, amount and purpose for verifying the actual debit of advance/withdrawal to the concerned General Provident Fund account of the subscriber. The Heads of the Departments will consolidate the advance/withdrawal sanctioned by the subordinate offices including advances/withdrawals sanctioned at Headquarter(s) and the same shall be reconciled with the Accountant General, Haryana.

Note 5 : The subscriber, who has submitted the application for final withdrawal and the same has been forwarded to Accountant General, shall be sanctioned advance/withdrawal only on receipt of concurrence from the Accountant General, Haryana.

ANNEXURE J

(see rule 12)

Example of an Interest calculation on General Provident Fund accumulation for the year 2003-04 from the following data: -

Serial Number	Particulars	Amount
1.	Opening Balance as on 01-04-2003	Rs. 2,25,980/-
2.	Monthly Subscription	Rs. 3,000/- p.m.
3.	Arrear of D.A. deposited in 6/2003	Rs. 2,214/-
4.	Advance for daughter's betrothal ceremony paid on 12/12/2003(to be recovered @ Rs. 1000/- p.m. in 25 instalments	Rs. 25,000/-
5.	Arrear of D.A. deposited in 2/2004	Rs. 3,035/-
6.	Withdrawal on 04-03-2004 for Higher Education of Son	Rs. 30,000/-
7.	Rate of interest during the year	8% p.a.

Solution

Paid month	Subscription	Recovery of Advance	Total	Drawal	Balance	Monthly product
04/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 12 = 36000$
05/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 11 = 33000$
06/2003	$3000 + 2214$	---	5214	---	5214	$5214 \times 10 = 52140$
07/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 9 = 27000$
08/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 8 = 24000$
09/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 7 = 21000$
10/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 6 = 18000$
11/2003	3000	---	3000	---	3000	$3000 \times 5 = 15000$
12/2003	3000	---	3000	25000	$(-)22000$	$(-)22000 \times 4 = (-)88000$
01/2004	3000	1000	4000	---	4000	$4000 \times 3 = 12000$
02/2004	$3000 + 3035$	1000	7035	---	7035	$7035 \times 2 = 14070$
03/2004	3000	1000	4000	30,000	$(-)26000$	$(-)26000 \times 1 = (-)26000$
						138210

Annual Product

(1) Opening Balance	Rs. 2,25,980.00
(2) Product during the financial year	Rs. 11,517.50
138210 divided by 12 = 11,517.50	
Total (1 + 2)	Rs. 2,37,497.50
Interest = $237497.50 \times 8\% = 18999.80$	Say Rs. 19,000.00

APPENDIX-A

[see rule 3 (2)]

THE PROVIDENT FUNDS ACT 1925

AN ACT TO AMEND AND CONSOLIDATE THE LAW RELATING TO GOVERNMENT AND OTHER PROVIDENT FUNDS

Whereas it is expedient to amend and consolidate the law relating to Government and other Provident Fund, it is hereby enacted as follows: -

1. Short title, extent and commencement .— (1) This Act may be called the Provident Funds Act, 1925.

- (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions. — In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

- (a) "compulsory deposit" means a subscription to, or deposit in, a Provident Fund which, under the rules of the Fund, is not, until the happening of some specified contingency, repayable on demand otherwise than for the purpose of the payment of premia in respect of a policy of life insurance or the payment of subscription or premia in respect of a family pension fund, and includes any contribution and any interest or increment which has accrued under the rules of the Fund on any such subscription, deposit or contribution, and also any such subscription, deposit, contribution, interest or increment remaining to the credit of the subscriber or depositor after the happening of any such contingency;
- (b) "contribution" means any amount credited in a Provident Fund, by any authority administering the Fund, by way of addition to, a subscription to, or deposit or balance at the credit of an individual account in the Fund; and "Contributory Provident Fund" means a Provident Fund the rules of which provide for the crediting of contributions;
- (c) "dependent" means any of the following relatives of a deceased subscriber to, or a depositor in, a Provident Fund, namely, a wife, husband, parent, child, minor brother, unmarried sister and a deceased son's widow and child, and, where no parent of subscriber or depositor is alive, a paternal grandparent;
- (d) "Government Provident Fund" means a Provident Fund, other than a Railway Provident Fund, constituted by the authority of the Secretary of State, the Central Government, the Crown Representative or any State Government for any class or classes of persons in the service of the Government or of persons employed in educational institutions or employed by bodies existing solely for educational purposes, and references in this Act to the Government shall be construed accordingly;
- (e) "Provident Fund" means a fund in which subscriptions or deposits of any class or classes of employees are received and held on their individual accounts, and includes any contributions and any interest or increment accruing on such subscriptions, deposits or contributions under the rules of the Fund;
- (f) "Railway administration" means —
 - (i) any company administering a railway or tramway in any part of India either under a Special Act of Parliament of the United Kingdom or an Indian law, or under contract with the Government, or
 - (ii) the Manager of any railway or tramway administered by the Central Government or by a State Government, and includes, in any case referred to in sub-clause (ii) the Central Government or the State Government, as the case may be;
- (g) "Railway Provident Fund" means a Provident Fund constituted by the authority of a Railway administration for any class or classes of its employees.

3. Protection of compulsory deposit. —

- (1) A compulsory deposit in any Government or Railway Provident Fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order

of any Civil, Revenue or Criminal Court in respect of any debt or liability incurred by the subscriber or depositor, and neither the official Assignee nor any receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920), shall be entitled to, or have any claim on any such compulsory deposit.

- (2) Any sum standing to the credit of any subscriber to, or depositor in, any such Fund at the time of his decease and payable under the rules of the Fund to any dependent of the subscriber or depositor, or to such person as may be authorized by law to receive payment on his behalf, shall, subject to any deduction authorized by this Act and, save where the dependent is the widow or child of the subscriber or depositor, subject also to the rights of an assignee under an assignment made before the commencement of this Act, vest in the dependent, and shall, subject as aforesaid, be free from any debt or other liability incurred by the deceased or incurred by the dependent before the death of the subscriber or depositor.

4. Provisions regarding repayment. —

- (1) When under the rules of any Government or Railway Provident Fund the sum standing to the credit of any subscriber or depositor, or the balance thereof after the making of any deduction authorized by this Act, has become payable, the officer whose duty it is to make the payment shall pay the sum or balance, as the case may be, to the subscriber or depositor, or, if he is dead, shall—
- (a) if the sum or balance, or any part thereof, vests in a dependent under the provisions of section 3, pay the same to the dependent or to such person as may be authorized by law to receive payment on his behalf; or
- (b) if the whole sum or balance, as the case may be, does not exceed five thousand rupees, pay the same, or any part thereof, which is not payable under clause (a) to any person nominated to receive it under the rules of the Fund, or, if no person is so nominated, to any person appearing to him to be otherwise entitled to receive it; or
- (c) in the case of any sum or balance, or any part thereof, which is not payable to any person under clause (a) or clause (b) pay the same,—
- (i) to any person nominated to receive it under the rules of the Fund, on production by such person of probate or letters of administration evidencing the grant to him of administration to the estate of the deceased or a certificate granted under the Succession Certificate Act, 1889 (VII of 1889), or under the Bombay Regulation VIII of 1827, entitling the holder thereof to receive payment of such sum, balance or part, or
- (ii) where no person is so nominated, to any person who produces such probate, letters or certificates:

Provided that, where the whole or any part of any sum standing to the credit of the subscriber or depositor has been assigned to any other person before the commencement of this Act, and notice in writing, of the assignment has been received by the officer from the assignee, the officer shall, after making any deduction authorized by this Act, and any payment due under clause (a) to or on behalf of the widow or children of the subscriber or depositor —

- (i) if the subscriber or depositor or, if he is dead, the person to whom in the absence of any valid assignment the sum or balance would be payable under this sub-section gives his consent in writing, pay the sum or part of the balance thereof, as the case may be, to the assignee, or —
- (ii) if such consent is not forthcoming, withhold payment of the sum, part of balance, as the case may be, pending a decision of a competent Civil Court as to the person entitled to receive it.
- (2) The making of any payment authorized by sub-section (1) shall be a full discharge to the Government or the Railway administration, as the case may be, from all liability in respect of so much of the sum standing to the credit of the subscriber or depositors as is equivalent to the amount so paid.

5. Rights of nominees.—

(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any disposition, whether testamentary or otherwise, by a subscriber to, or depositor in, a Government or Railway Provident Fund of the sum standing to his credit in the Fund, or of any part thereof, where any nomination, duly made in accordance with the rules of the Fund, purports to confer upon any person the right to receive the whole or any part of such sum on the death of the subscriber or depositor occurring before the sum has become payable or before the sum, having become payable, has been paid, the said person shall, on the death as aforesaid of the subscriber or depositor, become entitled, to the exclusion of all other persons, to receive such sum or part thereof, as the case may be, unless—

- (a) such nomination is at any time varied by another nomination made in like manner or expressly cancelled by notice given in the manner and to the authority prescribed by those rules, or
- (b) such nomination at any time becomes invalid by reason of the happening of some contingency specified therein and if said person predeceases the subscriber or depositor, the nomination shall, so far as it relates to the right conferred upon the said person, become void and of no effect:

Provided that where provision has been duly made in the nomination in accordance with the rules of the Fund, conferring upon some other person such right instead of the person deceased, such right shall, upon the decease as aforesaid of the said person, pass to such other person.

(2) Notwithstanding anything contained in the Indian Succession Act, 1925 or the Bombay Regulation VIII of 1827, any person, who becomes entitled as aforesaid, may be granted a certificate under that Act or that Regulation, as the case may be, entitling him to receive payment of such sum or part, and such certificate shall not be deemed to be invalidated or superseded by any grant to any other person of probate or letters of administration to the estate of the deceased.

(3) The provisions of this section as amended by Sub-section (1) of Section 2 of the Provident Funds (Amendment) Act, 1946 also shall apply to all such nominations made before the date of the commencement of that Act :

Provided that the provisions of this section as so amended shall not operate to affect any case, in which before the said date any sum has been paid, or has under the rules of the Fund become payable in pursuance of any nomination duly made in accordance with those rules.

6. Power to make deductions.—When the sum standing to the credit of any subscriber or depositor in any Government or Railway Provident Fund which is a Contributory Provident Fund becomes payable, there may, if the authority specified in this behalf in the rules of the Fund so directs, be deducted therefrom and to Government or the Railway administration, as the case may be —

- (a) any amount due under a liability incurred by the subscriber or depositor to Government or the Railway administration, but not exceeding in any case the total amount of any contributions credited to the account of the subscriber or depositor and of any interest or increment which has accrued on such contributions; or
- (b) where the subscriber or depositor has been dismissed from his employment for any reasons specified in this behalf in the rules of the Funds, or where he has resigned such employment within five years of the commencement thereof, the whole or any part of the amount of any such contributions, interest and increment.

6-A. Withholding or recovery of Government Contributions in case of Central Government Officers taking up, without prior permission, commercial employment within two years of their retirement.—

(1) In this section, unless the context otherwise requires, —

- (a) "Central Government Officers" means a subscriber to, or depositor in, a Contributory Fund constituted by the Central Government, who, immediately before his retirement, is a member of a Central Service Class I, but does not include an officer appointed under a contract of service for a specified term.

(b) "Commercial employment" means employment in any capacity (including that of an agent) under any company, co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also—

(i) a directorship of a company;

(ii) the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of president, chairman, manager, secretary, treasurer, by whatever name called in a co-operative society; and

(iii) the setting up of practice, either independently or as partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the Central Government Officer,—

(A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(B) has professional qualification, but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of the posts held by him under the Central Government, or

(C) has to undertake work involving liaison or contract with the offices or officers of Central Government,

but does not include employment in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by Government or employment in or under a body controlled or financed wholly or substantially by Government;

(c) "Government contributions" means contributions made after the commencement of the Provident Funds (Amendment) Act, 1975, in respect of any period after such commencement, by the Central Government or by a State Government or by a local authority within the meaning of the Local Authorities Loans Act, 1914;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made by the Central Government by notification in the Official Gazette.

(2) No Central Government Officer shall have any right to the Government contributions made to his credit in a Contributory Provident Fund in any case where he takes up commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the prior permission of the Central Government.

EXPLANATION 1.— For the purposes of this sub-section and Sub-section (7), "date of retirement" in relation to a Central Government Officer re-employed after retirement without any break either in the same or any other class I post under the Central Government or any other equivalent post under a State Government, shall mean the date on which such Central Government Officer finally ceases to be re-employed in Government service.

EXPLANATION 2.— A Central Government Officer permitted by the Central Government to take up a particular commercial employment during his leave preparatory to retirement shall be deemed, for the purposes of this sub-section, to have obtained prior permission of the Central Government for his continuance in such employment after retirement.

(3) Subject to the provisions of sub-section (4), the Central Government may, by order in writing, on an application made in the prescribed form by a Central Government Officer, grant subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission, to such officer to take up the commercial employment specified in the application.

(4) In granting or refusing permission under this section to a Central Government Officer for taking up any commercial employment, the Central Government shall have regard to the following factors, namely : —

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

- (b) whether his duties in the employment which he proposes to make up might be such as to bring him into conflict with Government;
- (c) whether the officer while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as might afford a reasonable basis for the suspicion that such officer had shown favour to such employer;
- (d) any other relevant factors which may be prescribed.

(5) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under Sub-section (3), the Central Government does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the Central Government shall be deemed to have granted the permission applied for.

(6) Where the Central Government grants the permission applied, for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the orders of the Central Government to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Central Government may make such orders thereon as it deems fit :

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-section without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(7) If any Central Government Officer takes up any commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the prior permission of the Central Government or commits a breach of any condition subject to which permission to take up any commercial employment has been granted to him under this section, it shall be competent for the Central Government to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to such part of the Government contributions made in relation to such officer as may be specified in the order and if he has received payment thereof, to direct that he shall refund to the Central Government an amount equivalent to such part of the Government contributions :

Provided that no such order shall be made without giving the officer concerned an opportunity of showing cause against such declaration or direction :

Provided further that in making any order under this sub-section, the Central Government shall have regard to the following factors, namely :

- (i) the financial circumstances of the officer concerned;
- (ii) the nature of, and the emoluments from, the commercial employment taken up by the officer concerned;
- (iii) such other relevant factors as may be prescribed.

(8) Any amount required to be refunded by an order under Sub-section (7) may, if it is not refunded within the prescribed period, be recovered as arrears of land revenue.

(9) Every order passed by the Central Government under this section shall be communicated to the officer concerned.

(10) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or the rules applicable to any contributory provident fund.

(11) Every rule made by the Central Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session, or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

7. **Protection for acts done in good faith .-** No suit or other legal proceeding shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

8. **Power to apply the Act to the Provident Fund .-** (1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Act except Section 6-A shall apply to any Provident Fund

established for the benefit of its employees by any local authority within the meaning of the Local Authority Loans Act, 1914, and on the making of such declarations, this Act shall apply accordingly, as if such Provident Fund were a Government Provident Fund and such local authority were the Government.

(2) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of this Act (except Section 6-A) shall apply to any Provident Fund established for the benefit of the employees of any of the institutions specified in the Schedule, or of any group of such institutions and, on the making of such declaration, this Act shall apply accordingly, as if such Provident Fund were a Government Provident Fund and the authority having custody of the Fund were the Government:

Provided that Section 6 shall apply as if the authority making the contributions referred to in that section were the Government.

(3) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, add to the Schedule the name of any public institution it may deem fit, and any such addition shall take effect as if it had been made by this Act.

(4) In this section, "the appropriate Government" means —

- (a) in relation to a cantonment authority, a port authority for a major port, and any institution which, or the objects of which, appear to the Central Government to fall within List I in the Seventh Schedule to the Constitution, the Central Government; and
- (b) in other cases, the State Government.

EXPLANATION.— "The State Government" in relation to an institution registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) means the State Government of the State in which the Society is registered.

9. Savings as to estates of soldiers.— Nothing in Section 4 or Section 5 shall apply to money belonging to any estate for the purpose of the administration of which the Regimental Debts Act, 1893, applies.

10. Repeals.— [Repealed by the Repealing Act, 1927(12 of 1927), S.2 and Sch.]

THE SCHEDULE

(Not added)

APPENDIX-B

[see rule 16(9)]

List of approved courses as mentioned in rule-21

Serial Number	Name of the Course
1.	Diploma Course in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication/Radio Engineering, Metallurgy, Automobile Engineering, Textile Technology, Leather Technology, Printing Technology, Chemical Technology, etc. conducted by recognized technical institutions.
2.	Degree courses in the various fields of Engineering and Technology, e.g. Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication/Radio Engineering, Metallurgy, Automobile Engineering, Textile Technology, Leather Technology, Printing Technology, Chemical Technology, etc. conducted by recognized technical institutions.
3.	Postgraduate courses in the various fields of Engineering and Technology conducted by the Universities and recognized institutions.
4.	Degree and Diploma courses in Architecture, Town Planning and allied fields conducted by recognized institutions.
5.	Diploma and Certificate courses in Commerce conducted by recognized institutions.
6.	Diploma courses in management conducted by recognized institutions.
7.	Degree Courses in Agriculture, Veterinary Science and allied subjects conducted by recognized Universities and institutions.
8.	Degree and Diploma courses in Art/Applied Art and allied subjects conducted by recognized institutions.
9.	Medical courses (including Allopathic, Homoeopathic, Ayurvedic and Unani systems) conducted by recognized institutions.
10.	Bachelor of Science (Home Science) courses.
11.	Degree and Diploma course in Hotel Management conducted by recognized institutions.
12.	Degree and Postgraduate course in Home Science.
13.	Pre-Professional course in Medicine if part or regular 5 years course in Medicine.
14.	Doctorate of Philosophy in Biochemistry.
15.	Degree and Postgraduate course in Law.
16.	"Honours" course in Microbiology.
17.	Associateship of the Institute of Chartered Accountants.
18.	Associateship of the Institute of Costs and Works Accountants.
19.	Degree and Master's course in Business Administration or Management.
20.	Master of Science course in Statistics, Computer Application.
21.	The Company Secretaryship course or the Institute of Company Secretaries of India.
22.	The course or pre-sea training imparted on the Training Ship "Rajendra" to prospective paginating officers on merchantships.
23.	The course in Marine Engineering conducted in the Directorate of Marine Engineering Training.

BHASKAR CHATTERJEEFinancial Commissioner and Principal Secretary to Government,
Haryana, Finance Department.